सूर्योदय 6.15 सूर्यास्त 6:07

आज का तापमान

शिमला	15.0 न्यू	26.0 अधि
धर्मशाला	16.0 न्यू	28.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	72,480
निफ्टी	22, 620

सोना 1,48,379 चांदी 2,21,600

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | वीरवार, 1 अक्तूबर 2026 | 15 अश्विन, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 157, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

जम्मू-कश्मीर में लश्कर कमांडर हाशिम मूसा ढेर

एजेंसी, बडगाम। जम्मू-कश्मीर के बडगाम में सुरक्षाबलों ने मंगलवार देर रात लश्कर-ए-तैयबा के एक टॉप कमांडर हाशिम मूसा को मार गिराया। मुठभेड़ यूसमर्ग के कोराग इलाके में हुई। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ को यहां आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था, जिसके बाद ज्वॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक मारे गए आतंकी की पहचान मूसा के तौर पर हुई है। अलग-अलग रिपोर्टों में उसका नाम सुलेमान शाह उर्फ मूसा, फौजी मूसा और मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा बताया गया है। इंडियन आर्मी ने इस एनकाउंटर को ऑपरेशन कोराग नाम दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना को यहां और भी आतंकी छिपे होने की जानकारी मिली है।

दिल्ली दंगा केस- हाईकोर्ट ने उमर खालिद व शरजील की जमानत खारिज की

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने कड़कड़डूमा कोर्ट के 4 जुलाई के आदेश के खिलाफ दोनों की अपील खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की पृष्ठभूमि में फरवरी 2020 में हुए दंगों की साजिश से जुड़ा है।

वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म-6 से अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा

एजेंसी, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) पूरा हो चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म 6 से अतिरिक्त घोषणा हटा दी है। यानी एसआईआर पूरा होने के बाद फॉर्म 6 में इससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगी जाएगी। यह बदलाव मंगलवार देर रात ECINET पोर्टल पर किया गया। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को इसका ऐलान किया था। हालांकि, जिन राज्यों में एसआईआर जारी है, वहां फॉर्म 6 में यह घोषणा अब भी दिख रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने इस पर आपत्ति जताई थी।

नीला ड्रम केस: सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और प्रेमी दोषी करार

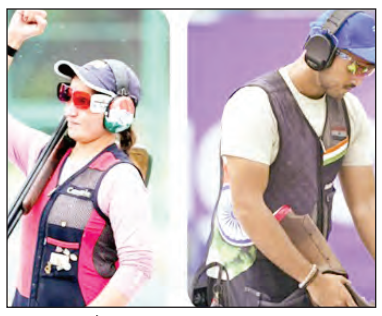
एजेंसी, मेरठ। मेरठ में पति को मारकर नीले ड्रम में छिपाने वाली मुस्कान और उसके प्रेमी को बुधवार को कोर्ट ने हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने माना कि दोनों ने मिलकर सौरभ को मारा था। शव के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में पैक कर दिया था। घटना के 576 दिन बाद 126 तारीखों में 22 से ज्यादा गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने फैसला लिया। सजा का ऐलान कोर्ट 15 दिन बाद करेगी। हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। जुलाई 2025 में जिला जज की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ था। पुलिस ने 1,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। 19 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

एशियन गेम्स : भारत को 11वें दिन 4 गोल्ड

तीरंदाजी में तीन, शूटिंग में एक गोल्ड जीता, मेडल टैली में सातवें नंबर पर पहुंचा भारत

एजेंसी, नागोया। भारत ने एशियन गेम्स के 11वें दिन 4 गोल्ड जीते। इनमें 3 गोल्ड तीरंदाजी और 1 शूटिंग में आया। इसके साथ भारत के 10 गोल्ड समेत 60 मेडल हो गए हैं। वह ईरान को पीछे छोड़कर मेडल टैली में 7वें नंबर पर पहुंच गया है।

बुधवार को पहला गोल्ड विमेंस कंपाउंड आर्चरी टीम ने जीता। इसके बाद चिकिता तनिपार्थी और साहिल जाधव की जोड़ी ने मिक्स्ड कंपाउंड आर्चरी में गोल्ड जीता। नीरू ढांडा और किनान चेनाई की जोड़ी को शूटिंग में गोल्ड मिला। दिन का चौथा गोल्ड कंपाउंड आर्चरी के पुरुष टीम इवेंट में साहिल, गणेश और कुशल ने जीता। भारत ने कंपाउंड आर्चरी के तीनों इवेंट में गोल्ड जीते। विमेंस टीम ने चीन को 238-234 से हराकर अपने खिताब का बचाव किया। मिक्स्ड टीम फाइनल में







चिकिता और साहिल का मुकाबला साउथ कोरिया की पार्क जंगयून और चोई योंगही से था। भारत ने शूट-ऑफ में गोल्ड अपने नाम किया।

इस जीत के साथ भारत ने लॉस एंजिलिस ओलिंपिक के कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट के लिए कोटा भी हासिल किया। पुरुष टीम फाइनल में साहिल, गणेश और कुशल की टीम ने चीन को 238-237 से हराया। भारत शुरुआती एंड में 58-60 से पीछे था, लेकिन इसके बाद भारतीय तीरंदाजों ने लगातार शानदार निशाने लगाए। फाइनल के बाद के 180 में भारत ने 180 अंक हासिल किए।

साहिल ने अपने सभी 8 शॉट में 10 अंक बनाए, जबकि गणेश और कुशल ने भी दबाव के बीच लगातार 10 लगाए। बॉक्सिंग में प्रियंका घंघास को विमेंस 60 किग्रा सेमीफाइनल में चीन की यांग चेंग्यू से 4-1 से हार मिली। उन्हें ब्रॉन्ज मिला। कपिल पोखरियाने पुरुषों के 90 किग्रा सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान के तुराबेक खाबिबुल्लाएव के खिलाफ 4-1 से हार के बाद ब्रॉन्ज जीता। वहीं, लवलीना बोरगोहेन ने विमेंस 75 किग्रा सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की नताल्या बोगदानोवा को 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

हॉकी: साउथ कोरिया को 2-0 हराकर फाइनल में भारत

भारतीय महिला हॉकी टीम ने साउथ कोरिया को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारत के लिए इशिका ने पेनल्टी कॉर्नर की वैरिएशन पर गोल किया, जबकि कसान सलिमा ने दूसरे हाफ में बढ़त दोगुनी की। अब भारत का गोल्ड मेडल मैच चीन से होगा। यह मुकाबला 2 अक्तूबर को खेला जाएगा।

पटाखों पर पूरी तरह रोक भी नहीं, लेकिन 24 घंटे की इजाजत भी नहीं : सुप्रीम कोर्ट

एजेंसी, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आगामी दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर कहा है कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, इसलिए न तो पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा और न ही चौबीसों घंटे आतिशबाजी की इजाजत दी जाएगी।

जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पटाखे जलाने के लिए समय तय करके बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, जबकि दिनभर पटाखे जलाने से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है इसलिए कोर्ट एक ऐसा समाधान निकालेगा, जिससे दिवाली के दौरान पटाखे जलाने के लिए एक खास समय तय किया जा सके सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बेरियम-बेस्ड पटाखों की टेस्टिंग रिपोर्ट जमा करने के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड



(सीपीसीबी) की ओर से 15 अक्टूबर तक का समय मांगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि 'लड़ी' या जॉइंट पटाखों के निर्माण की कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी जा सकती है, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताई। सीपीसीबी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि किन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति मिलेगी। पटाखा निर्माताओं के वकील के. परमेश्वर ने मांग की कि नियम बनाते समय सिर्फ दिल्ली को अलग से न देखा जाए, बल्कि पूरे देश के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाए। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए कोर्ट इस मामले की सुनवाई अर्जुन गोपाल और एम.सी. मेहता केस के साथ मिलाकर करने पर भी सहमत हुआ।

इजराइल जा रही फ्लाइट क्रैश कराने की कोशिश, पायलट को चाकू मारा

एजेंसी, रियाद। दुबई से तेल अवीव जा रही एक फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की गई। को-पायलट ने साथी पायलट पर चाकू से हमला किया और विमान का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश की। दूसरे पायलट और कुछ यात्रियों ने हाथापाई कर उसे रोक लिया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाई दुबई की फ्लाइट में यह घटना बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुई। इस वजह से 1 मिनट के अंदर विमान करीब 17 हजार फुट नीचे आ गया। इसके बाद विमान से हाईजैक का अलर्ट भेजा गया। इजराइल ने तुरंत फाइटर जेट्स रवाना किए। उनकी निगरानी में फ्लाइट का रास्ता बदला गया और उसे सऊदी अरब के ताबुक एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में करीब 180 यात्री सवार थे

केंद्र ने रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाई, गेहूं में 25 रुपए की बढ़ोतरी

एजेंसी, नई दिल्ली। कैबिनेट ने बुधवार को साल 2027-28 के लिए सभी छह रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाने को मंजूरी दी। गेहूं के एमएसपी में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई।

फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में दी। कुसुम का एमएसपी सबसे ज्यादा 675 रुपए बढ़ा। इसके बाद सरसों-राई में 413 रुपए और मसूर में 390 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज-III योजना को भी मंजूरी दी। इस योजना पर 1,86,405 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 जीडब्ल्यू तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा। यह काम साल 2032-33 तक पूरा करने का लक्ष्य



◆1.86 लाख करोड़ के ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को भी मंजूरी

है। कैबिनेट ने दिल्ली के ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए 1,790 करोड़ रुपए के इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ के तहत पीएफ कटने की अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। खेती के लिए सस्ते दाम पर खाद उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने उर्वरकों पर 41,533 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है।

भोपाल में रिटायर्ड आईएएस की गला रेतकर हत्या

एजेंसी, भोपाल। भोपाल में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की बुधवार सुबह सूरजनगर स्थित घर में हत्या कर दी गई। उनका शव कमरे में जमीन पर मिला। गले पर धारदार हथियार के निशान हैं। घर में अलमारी के लॉक टूटे मिले। किचन में एलपीजी सिलेंडर का पाइप निकला था, जिससे पूरे घर में गैस भर गई थी। आग लगाने की साजिश थी। शुरुआती जांच में पुलिस का शक 27 सितंबर को काम पर रखे गए केयरटेकर वरुण कुमार पर है, जो वारदात के बाद से लापता है। वरुण की आखिरी लोकेशन कुरवाई-बीना रोड मिली है। वरुण सीसीटीवी फुटेज में घर से जाते दिख रहा है। राकेश अग्रवाल की पत्नी ने पुलिस को बताया कि घर में कोई कीमती ज्वेलरी नहीं रखी थी।

टैक्स की दरें बढ़ाकर नहीं आधार बढ़ाकर मजबूत होगी राजस्व व्यवस्था : नायब सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा की अपनी राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य करों की दर बढ़ाकर नहीं, बल्कि कर आधार का विस्तार, बेहतर अनुपालन, राजस्व हानि पर रोक और आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग के माध्यम से हासिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को विकसित हरियाणा 2047 के लिए 'हरियाणा की अपनी कर-राजस्व व्यवस्था' के विश्लेषण व मजबूती के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। स्वर्ण जयंती हरियाणा इंस्टीट्यूट फॉर फिस्कल मैनेजमेंट (एसजेएचआईएफएम) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार



डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता सहित नीति-निर्माता, कर प्रशासक, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों, अप्रैल से अगस्त तक, हरियाणा का राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) संग्रह 29 प्रतिशत बढ़कर 24,662 करोड़ हो गया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह संग्रह 19,174 करोड़ था। अगस्त 2026 में भी हरियाणा के एसजीएसटी संग्रह में 21 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि 13 प्रतिशत रही।

उन्होंने कहा कि देश के कुल जीएसटी करदाताओं में हरियाणा की हिस्सेदारी 4 प्रतिशत से कम है, लेकिन देश के कुल जीएसटी संग्रह में राज्य का योगदान लगभग 7.7 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत सेवाओं का विस्तार हो रहा है।

शाह बोले- दिल्ली शराब घोटाले वाले नशामुक्ति नहीं कर सकते

एजेंसी, जालंधर। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को जालंधर में कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) ने पंजाब को चिट्टे (नशे) में धकेल दिया है। 2027 का चुनाव भाजपा नशामुक्त पंजाब के नाम पर लड़ेगी। मैं पंजाब के युवाओं को वादा करके जाता हूं कि भाजपा को वोट करें। हम 31 दिसंबर, 2029 से पहले पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे।

उन्होंने रैली में कहा भगवंत मान ने नशे के व्यापार को और बढ़ाया है। नशे में गुरु का अपमान करने वाला नशामुक्ति नहीं कर सकता, जो दिल्ली में शराब बेचने के घोटाले में पकड़े गए हों, वे पंजाब को नशामुक्त कैसे करेंगे? शाह की रैली से पहले बम की धमकी भी मिली थी। कैंब्रिज स्कूल को भेजे ई-मेल में दावा किया गया कि रैली के स्टेज के नीचे आईईडी रखा गया



◆आप ने पंजाब को चिट्टे में धकेला, 31 दिसंबर 2029 से पहले हम नशामुक्त कर देंगे

है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की जांच में वहां कुछ नहीं मिला। शाह ने कहा- भारतीय जनता पार्टी ने ये अभियान जो चलाया है, ये हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं। पंजाब में हम एक ग्राम ड्रग नहीं बेचने नहीं देंगे और न ही दूसरे हिस्से में जाने देंगे। मित्रों भारतीय जनता पार्टी ये तभी कर सकती है, जब पंजाब की हर मां-बहन और पंजाब के युवा एक मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे।

2-8 अक्तूबर तक विपक्षी गठबंधन का देशभर में प्रदर्शन

छह अक्तूबर को चुनाव आयोग घेरेंगे, इंडिया ब्लॉक का फैसला

एजेंसी, नई दिल्ली। 'इंडिया' गठबंधन ने चुनाव प्रणाली से जुड़ी कथित अनियमितताओं के खिलाफ बुधवार को एक साझा कार्ययोजना के तहत देशभर में आंदोलन और सभाएं आयोजित करने का निर्णय किया तथा इस बात पर जोर दिया कि 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन' (ईवीएम) की जगह मतपत्र के जरिए चुनाव कराए जाएं।

गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सभी नेताओं ने मिलकर लड़ाई लड़ने की बात की है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निर्वाचन आयोग का 'कठपुतली' की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खरगे ने विपक्ष की साझा कार्ययोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि दो से आठ अक्तूबर तक



जिला स्तर पर 'लोकतंत्र बचाओ मार्च' निकाला जाएगा। इसके अलावा छह अक्तूबर को विपक्षी दलों के सभी सांसद निर्वाचन आयोग तक मार्च निकालेंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा जाएगा और आयोग के समक्ष विपक्षी दल अपनी चिंताओं से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की ओर से पांच बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी, जिनके माध्यम से जनता के समक्ष यह बात रखी जाएगी कि विपक्ष के अनुसार सरकार लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को प्रभावित कर रही है।

खरगे ने कहा कि विपक्षी नेताओं की मांग है कि उच्चतम न्यायालय चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों की जल्द सुनवाई कर उनका निस्तारण करे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बैठक में शामिल सभी दलों की राय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला किया है।

3000 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार

एजेंसी, मुंबई। ईरानी नाव में 3,000 करोड़ की ड्रग्स के साथ 5 पाकिस्तानी नागरिकों को कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपी 526 किलो मेथामफेटामाइन और हेरोइन को समुद्री रास्ते से मुंबई ले जा रहे थे।

सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई लक्षद्वीप के पास 25 सितंबर को की थी। हालांकि, इसकी जानकारी बुधवार को सामने आई। इससे पहले अप्रैल 2025 में भी गुजरात तट के पास एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल ने करीब 311 किलो मेथामफेटामाइन जब्त की थी, जिसकी कीमत 1,800 करोड़ बताई गई। यह खेप पाकिस्तान के पसनी पोर्ट से तमिलनाडु ले जाना था। सुरक्षाबलों को देखकर तस्करों ने ड्रग्स समुद्र



◆ईरानी नाव से मुंबई जा रहे थे, लक्षद्वीप के पास कोस्ट गार्ड और एटीएस ने पकड़ा

में फेंक दी और पाकिस्तान की समुद्री सीमा की ओर भाग गए। खुफिया सूचना मिलने के बाद तटरक्षक बल ने समुद्र से निगरानी की। संदिग्ध नाव को लक्षद्वीप के पश्चिम में रोककर तलाशी ली गई। नाव, चालक दल और ड्रग्स को सुरक्षा के बीच मुंबई लाया गया है, जहां पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

चिंता न करें, हर समस्या का होगा समाधान : योगी

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं करीब 150 लोगों की समस्याएं

एजेंसी, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं व समाधान के प्रति आश्वस्त किया।



उन्होंने शिकायत लेकर आए लोगों से कहा कि चिंता मत करिए, सरकार हर व्यक्ति की समस्या का समाधान प्रतिबद्धता से कराएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी तत्परता व संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले। हर पात्र को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, जमीन कब्जाने वाले भू माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में शीघ्रता से निस्तारण के निर्देश दिए। बुधवार को भी जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए थे। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके उच्च स्तरीय इलाज का इस्टीमेट शीघ्रता से बनवाकर उपलब्ध कराएं। इस्टीमेट मिलते ही सरकार विवेकाधीन कोष से धन उपलब्ध कराएगी।

सुरक्षा सीएम ने किया गीतांजलि फायर स्टेशन का उद्घाटन, अग्निशमन सेवा को समर्पित किए 46 नए वाहन

संकट के समय दिल्ली के हर नागरिक तक मदद पहुंचाना संकल्प: रेखा

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गीतांजलि फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पर दिल्ली फायर सर्विस के बेड़े में 20 फायर रिस्पांस मोटरबाइक और 26 क्विक रिस्पांस व्हीकल्स को शामिल किया गया। ये वाहन तंग गलियों और संकरे रास्तों तक तेजी से पहुंचकर आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कि संकट के समय दिल्ली के हर नागरिक तक कम से कम समय में मदद पहुंचने हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधन और मजबूत फायर सर्विस के साथ



हमारी सरकार दिल्ली को और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इस अवसर पर सांसद बांसुरी स्वराज, गृहमंत्री आशीष सूद, विधायक सतीश उपाध्याय उपस्थित रहे। सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि गीतांजलि फायर स्टेशन दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ तैनात नई मोटरसाइकिलें और क्विक रिस्पांस व्हीकल्सआपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया को और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली जैसे जीवंत और तेजी से विकसित होते महानगर के लिए सुरक्षा नागरिकों के विश्वास का आधार है। संकट की घड़ी में मदद कितनी जल्दी पहुंचती है, यही एक सुरक्षित शहर की असली पहचान है।

मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली फायर सेवा को और अधिक तेज, सक्षम और प्रभावी बनाने की दिशा में 20 फायर रिस्पॉन्स मोटरसाइकिल और 26 क्विक रिस्पॉन्स वाहन भी सेवा में जोड़े गए। विशेष रूप से संकरी गलियों और कठिन पहुंच वाले क्षेत्रों में ये वाहन आपात स्थिति के दौरान त्वरित सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में दिल्ली के किसी भी नागरिक तक मदद पहुंचने में देरी न हो, यही हमारा संकल्प है।

कई क्षेत्रों को मिलेगा त्वरित अग्निशमन लाभ

विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि लगभग 3,920 वर्ग मीटर भूमि पर आधुनिक एसपीएस तकनीक से निर्मित यह फायर स्टेशन विशेष रूप से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के गीतांजलि एन्क्लेव, साकेत, खिड़की एक्सटेंशन और हौज रानी जैसे क्षेत्रों में महज 5 से 7 मिनट में अग्निशमन सहायता उपलब्ध कराने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल दिल्ली की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के साथ ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एचपीएसईबीएल के 102 लेखा कार्मिकों को वित्तीय नियमों का मिला प्रशिक्षण

प्रशिक्षण से पारदर्शिता, दक्षता और एकरूपता होगी मजबूत



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) की ओर से हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 102 लेखा कार्मिकों को अद्यतन लेखा नियमावली, बैंकिंग, बजट और खरीद संबंधी वित्तीय प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया गया। यह क्षमता निर्माण कार्यक्रम डेलॉयट इंडिया एलएलपी के सहयोग से आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य लेखा कार्मिकों को बदलती वित्तीय प्रक्रियाओं और नियमों की जानकारी देकर कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और प्रक्रियात्मक एकरूपता को बढ़ावा देना रहा। निदेशक (वित्त एवं कार्मिक) श्रवण कुमार ने कहा कि वित्तीय एवं लेखा प्रक्रियाओं में बदलाव के अनुरूप अधिकारियों और कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है। अद्यतन नियमों की बेहतर समझ से कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

वित्तीय प्रबंधन को मिलेगा नया आधार

प्रशिक्षण के दौरान बैंकिंग, बजट, खरीद नियमावली और उनके व्यावहारिक अनुपालन की जानकारी दी गई। डेलॉयट इंडिया की ओर से सीए अमन ढल, सीए सचिन गुप्ता, सीए अशोक कुमार, सीए अक्षय अग्रवाल और सीए नियंता पटेल ने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में एचपीएसईबीएल के मुख्य लेखा अधिकारी कपिल कुमार भीमटा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। बोर्ड के अनुसार यह पहल वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बनाने में सहायक होगी।

21 से 29 सितंबर तक चार बैचों में आयोजित प्रशिक्षण में अब तक 102 लेखा कार्मिकों ने भाग लिया। अंतिम बैच में 26 कार्मिक प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, अधीक्षक (डिवीजन अकाउंट्स) और जेओए (अकाउंट्स) शामिल रहे।

आज से तीन दिन रोहडू-रामपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण

विद्यार्थियों और ग्रामीणों से करेंगे संवाद, एंटी चिट्टा रैली में भी लेंगे भाग

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू अक्तूबर माह के निर्धारित दौरा कार्यक्रम के तहत आज से तीन अक्तूबर तक शिमला जिले के रोहडू, चिड़गांव, रामपुर और आसपास के क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के साथ स्थानीय लोगों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। नशे के खिलाफ जन-जागरूकता अभियान भी दौरे का प्रमुख हिस्सा रहेगा। सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

आज रोहडू और चिड़गांव में कार्यक्रम : आज मुख्यमंत्री शिमला से रोहडू जाएंगे। वहां पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (सीबीएसई) में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इसके बाद एंटी चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाकर उसमें भाग लेंगे। इसके पश्चात सड़क मार्ग से चिड़गांव पहुंचेंगे। नगर पंचायत मैदान में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री संदाशु स्थित एचपीएसईबीएल रेस्ट हाउस जाएंगे। शाम को ग्राम भटवारी, ग्राम पंचायत दियुड़ी मायला में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव भटवारी में ही होगा।



विकास योजनाओं के उद्घाटन संग ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री

दो अक्तूबर को रामपुर पहुंचेंगे : दो अक्तूबर को मुख्यमंत्री ग्राम भटवारी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद रामपुर के शिंगला हेलीपैड पहुंचेंगे। यहां विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के साथ नोग घाटी की जनता से संवाद करेंगे।

इसके बाद मुख्यमंत्री तकलेच और काशा गांव का दौरा करेंगे। काशा में 'सरकार गांव के द्वार' कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से बातचीत करेंगे। उनका रात्रि ठहराव पट गांव में निर्धारित है।

तीन अक्तूबर को नोगली और रामपुर में कार्यक्रम : तीन अक्तूबर को मुख्यमंत्री पट गांव से नोगली जाएंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पदम उत्कृष्ट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (सीबीएसई), रामपुर में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। यहां एंटी चिट्टा रैली को हरी झंडी दिखाकर उसमें भाग लेंगे।

इसके बाद सर्किट हाउस रामपुर में दोपहर का भोजन करने के बाद मुख्यमंत्री शिंगला हेलीपैड से हेलीकॉप्टर द्वारा शिमला के अनाडेल हेलीपैड लौटेंगे और सड़क मार्ग से ओक पहुंचेंगे।

अधिकारियों से विकास कार्यों की लेंगे जानकारी

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री संबंधित विभागों के अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी भी लेंगे। स्थानीय स्तर पर लंबित समस्याओं और आवश्यकताओं को लेकर अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर रहेगा। मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध तरीके से विकास कार्य पूरा करने पर जोर देंगे।

जाखू मंदिर के रंग-रोगन पर विवाद, समिति ने मांगी कार्रवाई



भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला के जाखू स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में चल रहे जीर्णोद्धार और रंग-रोगन के कार्य को लेकर हिंदू संघर्ष समिति ने आपत्ति जताई है। समिति के सदस्यों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। समिति का आरोप है कि मंदिर के गुंबद पर रंग-लिपाई का काम मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से करवाया जा रहा है।

समिति के सदस्य मदन ठाकुर ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि मंदिर के गुंबद पर रंग-रोगन का कार्य मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति से कराया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि मंदिर में इस प्रकार का कार्य करवाने की अनुमति किसने दी और क्या इसके लिए निर्धारित नियमों की जांच की गई है।

मदन ठाकुर ने कहा कि जाखू मंदिर प्राचीन धार्मिक स्थल है और इसकी प्राण-प्रतिष्ठा के बाद धार्मिक परंपराओं तथा निर्धारित नियम-कायदों का पालन किया जाना चाहिए। समिति ने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

समिति का कहना है कि मंदिर से जुड़े कार्यों में धार्मिक भावनाओं और परंपराओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से समिति ने प्रशासन से यह स्पष्ट करने की मांग की कि मंदिर के गुंबद पर रंग-रोगन का कार्य किसकी अनुमति से कराया जा रहा है और कार्य के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है।

मदन ठाकुर ने कहा कि समिति ने फिलहाल उपायुक्त कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। यदि मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समिति इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएगी। उन्होंने कहा कि देश संविधान और कानून के अनुसार चलता है, लेकिन धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में वहां की परंपराओं और श्रद्धालुओं की भावनाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर स्थिति स्पष्ट करने तथा नियमों के अनुसार उचित कदम उठाने की मांग की।

ओस्लो पहुंचे पठानियां, पर्यटन विकास पर करेंगे मंथन

नॉर्वे की पर्यटन व्यवस्था और विकास मॉडल का अध्ययन कर साझा करेंगे अनुभव

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद इन दिनों स्कैंडिनेवियाई देशों के अध्ययन प्रवास पर हैं। नॉर्वे के बर्गेन में एक दिन के प्रवास के बाद वह जलमार्ग से फ्योर्ड क्रूज के माध्यम से नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे। यहां उनके रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है।



बर्गेन प्रवास के दौरान पठानियां ने शहर के कई ऐतिहासिक और प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। उन्होंने बर्गेन को पर्यटन की दृष्टि से विकसित और आकर्षक शहर बताते हुए कहा कि यहां की प्राकृतिक परिस्थितियां और पर्यटन सुविधाएं उल्लेखनीय हैं। उन्होंने नॉर्वे की पर्यटन व्यवस्था तथा स्थानीय जीवनशैली का भी अध्ययन किया।

बर्गेन नॉर्वे के पश्चिमी तट पर स्थित ऐतिहासिक शहर है। पहाड़ियों और समुद्र से घिरे होने के कारण यहां का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे नॉर्वे के प्रसिद्ध फ्योर्ड क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। वहीं, ओस्लो देश की राजधानी होने के साथ प्रशासन, व्यापार, शिक्षा और आधुनिक संस्कृति का प्रमुख केंद्र है।

बर्गेन प्रवास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने भारतीय समुदाय से जुड़े व्यापारियों, उद्यमियों और शिक्षाविदों से मुलाकात की। इस दौरान पर्यटन, स्थानीय विकास, सामाजिक विषयों और भारत तथा नॉर्वे के लोगों के बीच संबंधों को लेकर विचार-विमर्श किया गया।

पठानियां ने कहा कि अध्ययन प्रवास के दौरान उन्हें नॉर्वे की पर्यटन व्यवस्था और स्थानीय विकास मॉडल को समझने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश लौटने के बाद वह अपने अनुभवों को हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ साझा करेंगे। उन्होंने हिमाचल में पर्यटन को और अधिक विकसित करने के लिए विदेशों में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं से सीख लेने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ओस्लो पहुंचने के बाद उनके अध्ययन प्रवास का अगला चरण शुरू होगा।

चायल-कोटी कॉलेज में जूडो प्रतियोगिता संपन्न, सोलन और बिलासपुर बने विजेता

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राजकीय डिग्री कॉलेज चायल-कोटी में आयोजित दो दिवसीय अंतर महाविद्यालय जूडो प्रतियोगिता संपन्न हो गई। समापन समारोह में निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. सुनीता सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम निदेशक प्रो. संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और ट्रॉफियां प्रदान कर सम्मानित किया। पुरुष वर्ग में राजकीय डिग्री कॉलेज सोलन और महिला वर्ग में राजकीय डिग्री कॉलेज बिलासपुर ने ओवरऑल खिताब जीता।



कॉलेज की प्राचार्या डॉ. दीपशिखा भारद्वाज ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 18 और महिला वर्ग की 13 टीमों ने भाग लिया। महिला वर्ग में 48 किलोग्राम में हमीरपुर की दाक्षी, 52 किलोग्राम में बिलासपुर की प्रज्जवल चौहान, 57 किलोग्राम में बिलासपुर की मेघा, 63 किलोग्राम में सोलन की गुंजन, 70 किलोग्राम में पीयू सेंटर की अंकिता, 78 किलोग्राम में बिलासपुर की दीपाली और 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में बिलासपुर की निताल ने स्वर्ण पदक जीते।

पुरुष वर्ग में 60 किलोग्राम में सोलन के अभिषेक, 66 किलोग्राम में बिलासपुर के शिवाच, 73 किलोग्राम में तिस्सा के साहिल, 81 किलोग्राम में हमीरपुर के आदित्य, 90 किलोग्राम में सोलन के अनिल, 100 किलोग्राम में सोलन के वंश ठाकुर और 100 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में तिस्सा के आदित्य ने स्वर्ण पदक हासिल किए।

पुरुष वर्ग में सोलन कॉलेज ने 60, 90 और 100 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। वहीं महिला वर्ग में बिलासपुर कॉलेज ने 52, 57, 78 और 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए।

शिमला में अंडर-19 इंडोर खेलकूद प्रतियोगिता शुरू



अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लालपानी, शिमला में 67वीं जिला स्तरीय वार्षिक अंडर-19 इंडोर खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में शिमला जिले के 62 विद्यालयों के करीब 400 विद्यार्थी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

प्रतियोगिता में बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जूडो, कुश्ती, भारोत्तोलन, ताइक्वांडो, योग, टेबल टेनिस, कुराश और कराटे सहित विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और खेल कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा।

प्रगति की सूची में शिमला-धर्मशाला, विकास योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख शहर शिमला और धर्मशाला केंद्र सरकार के प्रगति कार्यक्रम के तहत चयनित 50 शहरों की सूची में शामिल किए गए हैं। नगर निगम शिमला और नगर निगम धर्मशाला के विकास कार्यों की अब केंद्र स्तर पर निगरानी होगी। इससे दोनों शहरों में लंबित विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। प्रगति कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें सीवरेज, जल निकासी, सड़क, पार्किंग, कचरा प्रबंधन और हरित ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

हमीरपुर में दो दिन बिंदल करेंगे संगठन पर मंथन

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल 3 और 4 अक्टूबर 2026 को जिला हमीरपुर के दो दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वह पार्टी के विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से जुड़े विषयों पर संवाद करेंगे।

प्रवास कार्यक्रम के अनुसार डॉ. राजीव बिंदल कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लेंगे। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक गतिविधियों, कार्यप्रणाली और विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी होगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारी बैठक में भी भाग लेंगे। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ संगठन की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को गति देने तथा कार्यकर्ताओं की भूमिका को लेकर भी विचार-विमर्श होने की संभावना है।



डॉ. राजीव बिंदल का हमीरपुर प्रवास 3 अक्टूबर से शुरू होकर 4 अक्टूबर तक रहेगा। इस दौरान कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग और प्रदेश पदाधिकारी बैठक उनके प्रमुख कार्यक्रम होंगे। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी से आयोजित इन कार्यक्रमों में संगठनात्मक विषयों पर मंथन किया जाएगा।

नेरचौक में 6 अक्टूबर को छह घंटे बिजली आपूर्ति रहेगी बंद

भारतेन्दु संवाददाता,मंडी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के विद्युत उपमंडल नेरचौक के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में छह अक्टूबर को बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत बोर्ड के अनुसार 11 केवी लाइन की आवश्यक मरम्मत तथा पुराने और पेड़ों की कटाई-छंटाई का कार्य किया जाएगा। इसके चलते सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस दौरान गांव रत्ती, मलोहें, गलमा, बार्ट, कांडी, करेड़ी, सोएरा, बागा, चजरौट, दामू, सुनापानी, भंगरेड़ खड्डेर, चराखा व पोरेलैन के आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित विद्युत कट मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

सचिवालय में आयुष्मान आरोग्य शिविर, 350 अधिकारियों-कर्मचारियों ने लिया स्वास्थ्य लाभ

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं महासंघ की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सहयोग से बुधवार को सचिवालय परिसर में एक दिवसीय आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने सुबह 10:30 बजे शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में सचिवालय के करीब 350 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अलावा आम लोगों ने भी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाया। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों की स्वास्थ्य जांच की और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर आवश्यक परामर्श एवं जानकारी दी।

भारतेन्दु Classifieds

नाम परिवर्तन

मैं, रामेश्वर दास, पुत्र श्री भगवानु राम, निवासी गाँव साई, डाकघर मनलोगकलाँ, तहसील रामशहर, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ब्यान करता हूं कि मैं अपना नाम रामेश्वर बंसल से बदलकर रामेश्वर दास रख लिया है। भविष्य में मुझे रामेश्वर दास नाम से जाना जाएं। सभी नोट करें।

कार्यालय ग्राम पंचायत री
विकास खंड सुजानपुर टीहरा, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत री विकास खंड सुजानपुर टीहरा जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) विभिन्न शीर्ष के अंतर्गत विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न सामग्री (P/F Main Vertical Partitions Book Panel, Book shelf's, Shelf Supports, Vertical Wood strips, Lower Storage Cabin, Cabinet Shelter, Cabinet Handle, Hinges, LED lightening, LED profiteer, and all kinds of Electronic & Electrical points with fitting (ACP/WPC/PVC), (Stael TMT bar 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm and binding wire), (Floor Tiles 12x12, 24x24), (Wall Tiles 12x15, 12x24), (Sanitary items English WC, Wash basin with pedestal, Angle Lock, PVC Connection, waste pipe, bend, Elbow, Taps, P-Trap, S-Trap and all types of accessories, Plumbing items(P/F PVC, CPVC/ UPVC / GI / per rmt), curtains and SS Grade 304 and 202 etc. क्रय करने के लिए GST पंजीकृत फर्म से निविदा / कोटेशन सात दिनों के भीतर भीतर आमंत्रित करती है। **प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत री विकास खंड सुजानपुर टीहरा, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)**

कार्यालय ग्राम पंचायत बसूट
विकास खंड बाली चौकी, जिला मंडी (हि.प्र.)

निविदा सूचना

आज की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए निविदा आमन्त्रण वारे प्रस्ताव रखा गया । इस प्रस्ताव पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा विचार-विमर्श के वाद निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए निविदा आमंत्रित करनी उचित है। इसलिए सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। सभी से निवेदन है कि दिनांक 09/10/2026 तक आवेदन ग्राम पंचायत बसूट में पहुंचने अनिवार्य है । इस तिथि के बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । सभी अपने आवेदन डाक माध्यम से भेजें । याद रहे हाथ दस्ती आवेदन प्राप्त नहीं होंगे । दिनांक 10/10/2026 को आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी । सामग्री का विवरण इस प्रकार से है।

क्रं.	नाम बस्तु	दर
1.	रेत (Water Borne) With M Form	प्रति फुट में
2.	बजरी (Krusher) With M Form	प्रति फुट में
3.	लोकल पत्थर (With M Form	Cu. Mtr में
4.	ईटें (मिटटी के भठे की)	प्रति ईट
5.	JCB द्वारा cutting और Stone Breaking	Cu. Mtr में
6.	सीमेंट ढुलान बालीचौकी से	प्रति बैग
7.	सरिया	प्रति किलोग्राम
8.	Dustvin	प्रति नग
9.	GI Sheet छत बाली	प्रति शीट
10.	ग्रिल लोहा	प्रति किलोग्राम
11.	सूचना बोर्ड साइज़ वार	प्रति बोर्ड
12.	खच्चर ढलवान रोड से गांव	प्रति फुट

शर्तें -: 1 अनुमोदित निविदादाता के पास अपनी गाड़ी होनी अनिवार्य है जिसकी RC आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी आवश्यक है। 2 निविदादाता का अपना पंजीयन पैन संख्य GST नम्बर होना अनिवार्य है। 3 GST या CGST निविदा के साथ व समग्री के साथ मूल्य सहित स्पष्ट रूप से दर्शायें । 4 खनिज पदार्थ वाली सामग्री में M फॉर्म प्रदान करना आवश्यक होगा । 5 अनुमोदित निविदादाता को धरोहर राशी के रूप में 5000 रूपये पंचायत के खाता में जमा करने होंगे । 6 सामग्री की गुणवता से कोई समझौता नहीं होगा । 7 आवेदन को रद्द करने का अधिकार पंचायत के पास सुरक्षित है । 8 अगर सामग्री की आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है तो विना पूर्व सूचना के अनुबंध रद्द किया जायेगा । **नोट - सामग्री निम्न स्थानों में गाड़ी द्वारा पहुंचानी होगी ।** 1 बसूट 2 शाला गाड 3 बिझर । मूल्य सभी स्थानों के लिए बराबर रहेगा । **प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत बसूट विकास खंड बाली चौकी, जिला मंडी (हि.प्र.)**

कार्यालय ग्राम पंचायत थाची
विकास खंड बाली चौकी, जिला मंडी (हि.प्र.)

निविदा सूचना

आज की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए निविदा आमन्त्रण वारे प्रस्ताव रखा गया । इस प्रस्ताव पर बैठक में विचार-विमर्श किया गया तथा विचार-विमर्श के वाद निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए निविदा आमंत्रित करनी उचित है। इसलिए सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के लिए निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। सभी से निवेदन है कि दिनांक 10/10/2026 तक आवेदन ग्राम पंचायत थाची में पहुंचने अनिवार्य है । इस तिथि के बाद किसी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा । सभी अपने आवेदन डाक माध्यम से भेजें। याद रहे हाथ दस्ती आवेदन प्राप्त नहीं होंगे । दिनांक 12/10/2026 को आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी । सामग्री का विवरण इस प्रकार से है।

क्रं.	नाम बस्तु	दर
1.	रेत (Water Borne)	फुट में
2.	बजरी (Krusher)	फुट में
3.	लोकल पत्थर	Cu. Mtr में
4.	ईटें (मिटटी के भठे की)	प्रति ईट
5.	JCB द्वारा cutting और Stone Breaking	Cu. Mtr में
6.	सीमेंट ढुलान बालीचौकी से	प्रति बैग
7.	खच्चर किराया	प्रति फुट व प्रति पेवर/ईंट
8.	Dustvin	प्रति नग
9.	GI Sheet छत बाली	प्रति शीट
10.	ग्रिल लोहा	प्रति किलोग्राम
11.	सूचना बोर्ड साइज़ वार	प्रति बोर्ड
12.	सरिया	प्रति किलो

शर्तें:- 1 अनुमोदित निविदादाता के पास अपनी गाड़ी होनी अनिवार्य है जिसकी RC आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी आवश्यक है। 2 निविदादाता का अपना पंजीयन पैन संख्य GST नम्बर होना अनिवार्य है। 3 GST या CGST निविदा के साथ व समग्री के साथ मूल्य सहित स्पष्ट रूप से दर्शायें । 4 खनिज पदार्थ बाली सामग्री में M फॉर्म प्रदान करना आवश्यक होगा । 5 अनुमोदित निविदादाता को धरोहर राशी के रूप में 5000 रूपये पंचायत के खाता में जमा करने होंगे । 6 सामग्री की गुणवता से कोई समझौता नहीं होगा। 7 आवेदन को रद्द करने का अधिकार पंचायत के पास सुरक्षित है । 8 अगर सामग्री की आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है तो विना पूर्व सूचना के अनुबंध रद्द किया जायेगा । **नोट - सामग्री निम्न स्थानों में गाड़ी द्वारा पहुंचानी होगी ।** 1 थाची 2 ददवास 3 बुरना 4 चोडी 5 रोपा । मूल्य सभी स्थानों के लिए बराबर रहेगा । **प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत थाची विकास खंड बाली चौकी, जिला मंडी (हि.प्र.)**

तकनीक एयरोपोनिक्स तकनीक से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन पर ताजिकिस्तान की नजर

ताजिकिस्तान तक पहुंचेगी शिमला की आलू तकनीक

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) की उन्नत आलू उत्पादन तकनीक अब ताजिकिस्तान तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच आलू अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाने की दिशा में चर्चा हुई है। इसे लेकर सीपीआरआई शिमला और ताजिकिस्तान की एलसीसी एकोमा के प्रतिनिधियों के बीच वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। नई दिल्ली स्थित ताजिकिस्तान दूतावास के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए।

बैठक में सीपीआरआई के निदेशक डॉ. ब्रजेश सिंह ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। उन्होंने ताजिकिस्तान के प्रतिनिधियों को भारत में आलू अनुसंधान, उन्नत उत्पादन तकनीक और गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया की जानकारी दी। दोनों पक्षों ने आलू उत्पादन की पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर भी चर्चा की।



उन्नत तकनीक से किसानों को मिलेगा बेहतर बीज और उत्पादन का लाभ

सीपीआरआई के वैज्ञानिकों ने संस्थान में विकसित विभिन्न तकनीकों, अनुसंधान उपलब्धियों और बीज उत्पादन की आधुनिक व्यवस्थाओं से ताजिक प्रतिनिधियों को अवगत कराया। भारतीय दल में डॉ. आलोक कुमार, डॉ. जगदेव शर्मा, डॉ. संजीव शर्मा, डॉ. विनोद कुमार, डॉ. सोम दत्त और डॉ. पिनबियांगलांग के. सहित वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल रहे। ताजिकिस्तान की ओर से अलीशेर खोलमातोव, बेखरुज इब्रागिमोव और परविज रहीमजोड सहित अन्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बैठक में एयरोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले आलू बीज उत्पादन को विशेष महत्व दिया गया। इस तकनीक में बिना मिट्टी के नियंत्रित वातावरण में पौधों का विकास कर बीज सामग्री का तेजी से गुणन किया जाता है। ताजिकिस्तान के प्रतिनिधियों ने इस तकनीक की उत्पादन प्रक्रिया और उपयोगिता को समझने में विशेष रुचि दिखाई।

दोनों पक्षों के बीच ताजिकिस्तान के कृषि विशेषज्ञों के लिए सीपीआरआई शिमला के भ्रमण का प्रस्ताव भी रखा गया। प्रस्तावित दौरे के दौरान विशेषज्ञ एयरोपोनिक्स आधारित बीज उत्पादन, आलू फसल प्रबंधन और संस्थान की आधुनिक अनुसंधान सुविधाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकेंगे।

दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण को सरकार प्रतिबद्ध : रामदास अठावले

उत्तराखंड में विशेष जरूरत वाले बच्चों की पहचान को शुरू हुआ राज्य स्तरीय मैपिंग अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा को कम नहीं करती।

रामदास अठावले ने बुधवार को देहरादून के झाझरा स्थित आईटीआईटीआई दून संस्कृति स्कूल में विशिष्ट अधिगम अक्षमता और ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के लिए उत्तराखंड के पहले राज्य स्तरीय मैपिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य दिव्यांग बाल अभियान के तहत आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद तरुण विजय और विधायक खजान दास भी मौजूद रहे।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने विद्यार्थियों से संवाद कर दिव्यांग बच्चों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि संस्थान में पूर्वोत्तर राज्यों के करीब 150 विद्यार्थी और 67 दिव्यांग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। करीब 13 एकड़ में स्थापित संस्थान में विद्यार्थी समावेशी वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

दिव्यांगजनों के लिए 950 करोड़ का प्रावधान

अठावले ने कहा कि देश में 2.68 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं। सरकार शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और सामाजिक समावेशन के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने दिव्यांगजनों से संबंधित विभिन्न पहलों के लिए करीब 950 करोड़ रुपये के प्रावधान की जानकारी दी। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम बुनियादी ढांचे, शिक्षा और आवश्यक सहायता प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दिया।

अठावले ने धामी के नेतृत्व में विकास की सराहना की

अठावले ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए देशभर में 706 वृद्धाश्रमों के निर्माण या वित्त पोषण में सहायता दी गई है, जबकि उत्तराखंड में चार केंद्रों को सहयोग मिला है। उन्होंने नशा मुक्ति केंद्रों से जुड़ी पहलों की भी समीक्षा की और बताया कि देशभर में 790 नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। अठावले ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना अच्छा मित्र बताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में विकास कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

◆ डिस्लेक्सिया-ऑटिज्म प्रभावित बच्चों की मैपिंग शुरू



वर्ल्डस्किल्स-2026 में उत्तराखंड के युवाओं का शानदार प्रदर्शन

शंघाई में आयोजित वर्ल्डस्किल्स-2026 में उत्तराखंड की प्रतिभा का जलवा, सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने जीते रजत

अनिल थपलियाल

देहरादून। चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर, 2026 तक आयोजित 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता-2026 में उत्तराखंड के दो प्रतिभाशाली युवाओं ने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए रजत पदक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया। उत्तरकाशी की सानिया जोशी ने रिटेल सेल्स और देहरादून के पार्थ वोहरा ने औद्योगिक डिजाइन तकनीकी कौशल में रजत पदक जीता। दोनों की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि विश्व के प्रतिष्ठित कौशल मंच पर उत्तराखंड के युवाओं का देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक हासिल करना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। यह उपलब्धि अन्य युवाओं को कौशल विकास और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी।

परियोजना निदेशक उत्तराखंड कौशल विकास समिति नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता को कौशल के क्षेत्र में ओलंपिक के समान प्रतिष्ठित वैश्विक मंच माना जाता है। इस वर्ष प्रतियोगिता में करीब 1,400 प्रतिभागियों ने 64 विभिन्न कौशल विधाओं में प्रतिभाग किया। भारत ने आठ रजत पदक और 20 उत्कृष्टता पदक हासिल कर विश्व स्तर पर 10वां स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बताया गया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर की इस प्रतियोगिता में भारतीय युवाओं का प्रदर्शन देश में कौशल विकास के बढ़ते स्तर को दर्शाता है।



◆ रिटेल सेल्स और औद्योगिक डिजाइन में जीते रजत

अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमके उत्तराखंड के युवा

उन्होंने बताया कि सानिया जोशी और पार्थ वोहरा ने इंडियास्किल्स की राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वर्ल्डस्किल्स के लिए स्थान बनाया था। दोनों प्रतिभागियों ने चयन के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण और अभ्यास किया। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग तथा उत्तराखंड कौशल विकास समिति की ओर से दोनों प्रतिभागियों को प्रशिक्षण, अभ्यास शिविर, यात्रा और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भी आवश्यक प्रशिक्षण और सहयोग उपलब्ध कराया। सानिया ने रिटेल सेल्स और पार्थ ने औद्योगिक डिजाइन में अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किया। उनकी सफलता से उत्तराखंड के कौशल विकास कार्यक्रमों को भी नई पहचान मिली है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, इस प्रकार की उपलब्धियां युवाओं को पारंपरिक रोजगार के साथ कौशल आधारित क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इससे प्रदेश में व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए युवाओं की तैयारी को और गति मिलने की उम्मीद है।

मोनिका रावत ने क्यारकुली-भट्टा से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद पर किया नामांकन

सुनील सोनकर

मसूरी। क्यारकुली-भट्टा ग्रामसभा क्षेत्र में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए मोनिका रावत ने समर्थकों के साथ नामांकन किया। उनके साथ बड़ी संख्या में क्षेत्र पंचायत सदस्य और समर्थक मौजूद रहे। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य सृष्टि रावत के पति आशीष रावत ने कहा कि मोनिका को क्षेत्र की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और वह विकास को लेकर किए गए वादे पूरे करने में सक्षम होंगी।



◆ पूर्व सदस्य सृष्टि रावत के सरकारी सेवा में चयन के बाद खाली हुआ था पद

आशीष रावत ने बताया कि उनकी पत्नी सृष्टि रावत पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य थीं, लेकिन सरकारी विभाग में चयन के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से गांव की बेटी और उनके भाई की पत्नी मोनिका रावत को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उन्होंने कहा कि जनता और सहसपुर ब्लाक के 15 क्षेत्र पंचायत सदस्यों के सहयोग से नामांकन किया गया है।

उन्होंने कहा कि सृष्टि रावत के कार्यकाल में विकास को लेकर किए गए योजनाएं और वादे सरकारी सेवा में चयन के कारण पूरे नहीं हो सके। अब मोनिका के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। सहसपुर ब्लाक प्रमुख अर्चना ने भी समर्थन जताते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।

नामांकन के दौरान समर्थकों में उत्साह रहा। मोनिका ने विकास कार्यों को गति देने का संकल्प जताया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य गोविंद पुंडीर, संजय रावत, जितेंद्र जदवाण, राकेश कोठारी, रिंकू थापली, वीरेंद्र थापली, मदन कोठारी, वीरेंद्र जदवाण, भीम कोठारी, नितिन रावत सहित अन्य समर्थक मौजूद रहे।

प्रदेशभर में आज से शुरू होगी मिलेट्स की खरीद : डॉ. धन सिंह रावत

◆ कहा, विगत वर्ष 11,153 किसानों से खरीदा गया 53,860.652 कुंतल मंडुवा

◆ 250 क्रय केंद्रों पर 52.05 रूपये प्रति किलो के भाव से खरीदा जायेगा मंडुवा

विकास बलूनी

देहरादून। सूबे के पर्वतीय क्षेत्रों में पारम्परिक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ) 1 अक्टूबर से प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर मिलेट्स की खरीद करेगा। मिलेट्स मिशन योजना के तहत यूसीएफ इस फसली वर्ष 250 क्रय केंद्रों के माध्यम से मंडुवा, झंगोरा, तिलहन, चैलाई व दालें, सहित अन्य पहाड़ी उपजों की खरीद सीधे किसानों से करेगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने पारंपरिक व मोटे अनाज की खेती छोड़ दी थी वह फिर से पारम्परिक खेती करने लगे हैं। डॉ. रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को शत-प्रतिशत ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों जैविक खेती होने का फायदा किसानों को मिल रहा है क्योंकि उनके



उत्पादों को अब सीधे बाजार मिल रहा है और भविष्य में जैविक उत्पादों की मांग और बढ़ेगी।

विभागीय मंत्री ने बताया कि इस फसली वर्ष यूसीएफ के माध्यम से किसानों से मिलेट्स की खरीद की जायेगी। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली मिलेट्स खरीदी प्रक्रिया के लिये यूसीएफ ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिये इस वर्ष मंडुवा 52.05 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदा जायेगा जबकि विगत वर्ष यह 48.86 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया था।

सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने बताया कि प्रदेश में मिलेट्स खरीद और इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिसमें खरीद केंद्रों और निर्धारित खरीद मूल्य की जानकारी किसानों तक पहुंचाने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के साथ ही खरीद का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने को कहा।

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ल ने बताया कि मिलेट्स मिशन योजना के तहत इस फसली वर्ष मिलेट्स की खरीद को भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिये प्रदेशभर में 250 क्रय केंद्र खोले गये हैं, जबकि विगत वर्ष 214 केंद्रों के माध्यम से खरीद की गई थी, इस लिहाज से इस वर्ष 36 अतिरिक्त केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूसीएफ हाट के माध्यम से भी किसानों के उत्पादों की खरीद और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। मंडुवा की खरीद निर्धारित 52.05 प्रति किलो की दर पर की जाएगी, जबकि सोयाबीन, दाल, झंगोरा, चैलाई तथा अन्य सूखे अनाज एवं पहाड़ी उत्पादों की खरीद बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों से खरीदे गये उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बेहतर विपणन किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हो सके और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

पिछले वर्ष 11,153 किसानों से खरीदा गया 53,860.652 कुंतल मंडुवा



सहकारिता मंत्री,डॉ. धन सिंह रावत

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूसीएफ ने प्रदेश में 214 क्रय केंद्रों के माध्यम से कुल 53,860.652 कुंतल मंडुवा की खरीद की थी। यह खरीद प्रदेश के 11,153 किसानों से की गई। पिछले वर्ष चमोली जनपद में सर्वाधिक मंडवे की खरीद की गई जबकि सर्वाधिक किसानों ने टिहरी में अपने उत्पादों का विक्रय किया। वहीं कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जनपद में सबसे अधिक मंडुवा खरीदने में अव्वल रहा।

किसानों से 52.05 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदा जायेगा मंडुवा

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ), जो सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसके माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में किसानों से सीधे मिलेट्स की खरीद की जाएगी। इस वर्ष मंडुवा का खरीद मूल्य ₹52.05 प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वहीं अन्य पहाड़ी उत्पादों की खरीद बाजार मूल्य के आधार पर यूसीएफ हाट के माध्यम से की जाएगी। सरकार द्वारा लगातार मंडवे के खरीद मूल्य में वृद्धि की जा रही है। पिछले वर्ष मंडुवा की खरीद ₹48.86 प्रति किलो की दर से की गई थी। इससे पहले मंडुवा ₹18 प्रति किलो की दर पर खरीदा गया, जबकि इस वर्ष खरीद दर बढ़ाकर ₹52.05 प्रति किलो कर दी गई है। प्रत्येक क्विंटल की खरीद पर संबंधित सहकारी समिति को ₹200 की आय प्राप्त होगी, जिससे समितियों की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।

जरूरतमंदों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने आगे आएं लोग : सीएम धामी

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिवस का उद्देश्य आमजन को रक्तदान के प्रति जागरूक करना और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि रक्त की आवश्यकता किसी भी मरीज को कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदाता अस्पतालों और रक्त बैंकों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।



मुख्यमंत्री ने रक्तदान को महादान बताते हुए कहा कि रक्तदान के माध्यम से किसी व्यक्ति को जीवन का नया उपहार दिया जा सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा निर्धारित अंतराल पर किया गया रक्तदान जरूरतमंद मरीजों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति द्वारा चिकित्सकीय मानकों के अनुसार रक्तदान करने से सामान्यत: स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और शरीर दान किए गए रक्त की पूर्ति प्राकृतिक रूप से कर लेता है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे रक्तदान को सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि नियमित स्वैच्छिक रक्तदान से रक्त की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलती है और आपात स्थिति में मरीजों को समय पर आवश्यक रक्त उपलब्ध कराया जा सकता है।

यूटीईटी में सॉल्वर बैठाने वाला मुख्य अभ्यर्थी काशीपुर से गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, पौड़ी। उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी) में अपने स्थान पर सॉल्वर बैठाने वाले मुख्य अभ्यर्थी विशाल कुमार को कोटद्वार पुलिस ने बुधवार को काशीपुर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार विशाल ने खुद परीक्षा देने के बजाय बिजनौर निवासी हिमांशु चौहान को अपने स्थान पर परीक्षा देने भेजा था। हिमांशु को पुलिस पहले ही परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार कर चुकी है। एसएसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि 29 सितंबर को कोटद्वार के कलाबड़ स्थित मेहरबान सिंह कंडारी सरस्वती इंटर कॉलेज में यूटीईटी परीक्षा के दौरान जांच में पता चला कि विशाल कुमार के स्थान पर हिमांशु चौहान परीक्षा दे रहा था। पूछताछ और सत्यापन के बाद पुलिस ने हिमांशु को मौके से गिरफ्तार कर लिया। प्रधानाचार्य की तहरीर पर कोतवाली कोटद्वार में धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना और साक्ष्य संकलन के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि विशाल ने ही हिमांशु को अपने स्थान पर परीक्षा देने भेजा था।

प्रदेश के सभी एसटीपी की रियल टाइम मॉनिटरिंग का बनेगा मैकेनिज्म

भारतेन्दु संवाददाता, देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में 25 बिंदु कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ उनके धरातलीय प्रभाव और आमजन को मिल रहे वास्तविक लाभ का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी योजना की सफलता केवल कार्यों की संख्या से नहीं, बल्कि उससे लोगों के जीवन में आए बदलाव से तय होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने पिरूल संग्रहण से लाभार्थियों को अब तक मिले आर्थिक लाभ और उनकी आय में हुई वृद्धि का पूरा आंकड़ा तैयार करने को कहा। उन्होंने डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण और कचरे के पृथक्करण की व्यवस्था को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। कचरे के संग्रहण से लेकर पृथक्करण और निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और पेयजल विभाग के अधिकारियों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित एसटीपी का उनकी क्षमता के अनुरूप पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी एसटीपी की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए प्रभावी और

हर माह होगी 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा

मुख्य सचिव ने अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए जिलास्तर पर नियमित निगरानी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। पार्किंग योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों में तेजी लाने और बाधाओं का समयबद्ध समाधान करने को कहा। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 25 बिंदु कार्यक्रम की हर माह समीक्षा करने और कम प्रगति वाले मामलों में कारण चिन्हित कर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

◆ योजनाओं की प्रगति के साथ आमजन को मिल रहे लाभ का भी करें आंकलन: आनंद बर्द्धन



केंद्रीकृत व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि संचालन और निर्धारित मानकों के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा सके। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़े व्यावसायिक संस्थानों और समूह आवासीय परिसरों में निजी एसटीपी की व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू कराने के निर्देश भी दिए गए।

नई टिहरी : जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के संचालन की प्रक्रिया तेज

भारतेन्दु संवाददाता, नई टिहरी। जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) के संचालन को लेकर जिला प्रबंधन समिति की बैठक हुई। विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं से मिले अभिरुचि प्रस्तावों की पात्रता, अनुभव और निर्धारित मानकों के आधार पर समीक्षा की गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रेष्ठा भाकुनी ने बताया कि केंद्र में दिव्यांगजनों को पुनर्वास एवं परामर्श, दिव्यांगता आकलन, सहायक उपकरण, फिजियोथेरेपी, चिकित्सकीय सेवाएं, कौशल विकास, स्वरोजगार मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की व्यवस्था होगी।

◆ दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण को मिलेगा नया आधार, डीडीआरसी संचालन की कवायद तेज



संस्थाओं ने संचालन की कार्ययोजना, मानव संसाधन, तकनीकी क्षमता, उपकरण और प्रस्तावित सेवाओं का प्रस्तुतीकरण किया तथा अर्जुन पोर्टल की सुविधाओं की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने संस्थाओं की पात्रता, अनुभव, संसाधनों और प्रस्तावित कार्यों का परीक्षण किया। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम-1860 और दर्पण पोर्टल पंजीकरण समेत मानकों की जानकारी ली गई। समिति ने प्रस्तावों पर विचार के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई पर सहमति दी। बैठक में सीडीओ वरुणा अग्रवाल, सीएमओ डॉ. राम प्रकाश, लीड बैंक अधिकारी मनीष मिश्रा, सीएमएस डॉ. बृजेश डोभाल सहित अधिकारी और संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

प्रशिक्षण प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों ने समझा आपदा प्रबंधन का संस्थागत ढांचा

आपदा प्रबंधन में त्वरित निर्णय जरूरी: प्रकाश चंद्र

अनिल थपलियाल

देहरादून। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में वर्ष 2024 और 2026 बैच के प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षकों को राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था, संस्थागत ढांचे और आपदा के विभिन्न चरणों में पुलिस की भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी, प्रतिवादन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया। साथ ही आपदा के दौरान विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता पर भी जानकारी दी गई।



कहा- आपदा प्रबंधन में अधिकारियों की भूमिका अहम

उन्होंने बताया कि आपदा के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पहुंच, लोगों की सुरक्षित निकासी, भीड़ और यातायात प्रबंधन, राहत सामग्री के निर्बाध वितरण में सहयोग, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, अफवाहों पर नियंत्रण और सही सूचना का प्रसार पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल हैं। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई करना भी जरूरी है। अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी ने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों को भविष्य में आपदा प्रबंधन से जुड़ी रणनीतिक और नेतृत्वकारी जिम्मेदारियां निभानी होंगी।

राहत कार्यों में समन्वय पर जोर

उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में समर्पण, मानवीय संवेदनशीलता, अनुशासन और त्वरित निर्णय क्षमता प्रभावी कार्रवाई के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रशिक्षण कार्यक्रम से अधिकारियों को आपदा प्रबंधन की व्यावहारिक समझ मिलेगी और वे राज्य की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान देंगे।

प्रशिक्षु अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली और इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम की अवधारणा एवं संरचना के बारे में बताया गया। इसके अलावा चेतावनी प्रसारण तंत्र, आपदा पूर्व तैयारियों, आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया तथा आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका, उनके नीतिगत दिशा-निर्देश और राज्य स्तर पर उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षु अधिकारियों ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की कार्यप्रणाली को भी समझा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र ने कहा कि आपदा प्रबंधन के पूरे चक्र में पुलिस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील होती है। किसी भी आपदा की स्थिति में पुलिस प्रमुख एजेंसियों में शामिल होती है, जो प्रभावित क्षेत्र में तेजी से पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा, सुरक्षित निकासी और प्रभावित लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने में भी उसकी अहम भूमिका होती है।

'जन-जन की सरकार' शिविर में चंद्रकला तिवारी ने सुनीं जनसमस्याएं

भारतेन्दु संवाददाता, चमोली। सेवा संकल्प अभियान के तहत दशोली ब्लॉक सभागार में 'जन-जन की सरकार' बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चंद्रकला तिवारी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में ऐसे बहुउद्देशीय शिविर महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है और उनकी समस्याओं को संबंधित विभागों के समक्ष रखकर समाधान की कार्रवाई की जाती है।

◆ कहा- अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना उद्देश्य

चंद्रकला तिवारी ने कहा कि जनसेवा, जनसंवाद और जनसमस्याओं के समाधान के उद्देश्य से आयोजित इन शिविरों से लोगों को अपनी समस्याएं सीधे अधिकारियों के सामने रखने का अवसर मिलता है। वहीं पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया भी समझाई जाती है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना तथा जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना ऐसे शिविरों का प्रमुख उद्देश्य है।

शिविर की अध्यक्षता नोडल अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने की। इस दौरान वरिष्ठ नागरिक उपाध्यक्ष हरक सिंह नेगी, दशोली मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र रावत, ब्लॉक प्रमुख विनीता देवी, नामित पार्षद कलावती देवी, ग्राम प्रधान, बीडीओ भवान सिंह राणा, तहसीलदार चमोली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और लाभार्थी मौजूद रहे।

कैंपस हिंसा से एलपीयू, चितकारा में प्लेसमेंट पर संकट

हिंसा की घटनाओं से विश्वविद्यालयों की छवि और कंपनियों का भरोसा प्रभावित होने की आशंका

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) और मोहाली की चितकारा यूनिवर्सिटी में हालिया विवादों के दौरान हुई हिंसक घटनाओं ने कैंपस के माहौल के साथ विद्यार्थियों के करियर को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। निजी विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नवंबर-दिसंबर का समय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दौरान देश-विदेश की बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए पहुंचती हैं।



इन विश्वविद्यालयों में प्रबंधन, इंजीनियरिंग और अन्य पाठ्यक्रमों के हजारों विद्यार्थी प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल होते हैं। कई कंपनियां योग्य विद्यार्थियों को आकर्षक वेतन पैकेज भी देती हैं। ऐसे में कैंपस में किसी तरह की हिंसा, असुरक्षा या लंबे समय तक बना तनाव प्लेसमेंट गतिविधियों को प्रभावित करने की आशंका बढ़ा सकता है।

समग्र विश्वविद्यालय की छवि भी अहम : विशेषज्ञों के अनुसार कंपनियां प्लेसमेंट के लिए केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता को ही नहीं देखतीं, बल्कि विश्वविद्यालय के अनुशासन, सुरक्षा, स्थिरता और अकादमिक वातावरण को भी महत्व देती हैं। यदि किसी संस्थान की पहचान लगातार विवाद या हिंसक घटनाओं से जुड़ने लगे तो कंपनियां वहां प्लेसमेंट गतिविधियों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरत सकती हैं।

चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अरुण कुमार ग्रोवर ने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में अकादमिक सत्र एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत चलता है। विद्यार्थियों की उपस्थिति, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षाएं और अन्य गतिविधियां पूरे वर्ष तय कार्यक्रम के अनुसार होती हैं। ऐसे में लंबे समय तक खराब माहौल रहने का असर अकादमिक गतिविधियों के साथ प्लेसमेंट पर भी पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालयों में अभिभावक बच्चों की शिक्षा पर बड़ी राशि खर्च करते हैं। विद्यार्थी भी बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे रोजगार और करियर की उम्मीद लेकर दाखिला लेते हैं। यदि कैंपस का वातावरण सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं रहता तो इसका असर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा पर पड़ सकता है। मेधावी विद्यार्थी भी भविष्य में ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने को लेकर विचार कर सकते हैं।

समग्र कंपनियां माहौल को भी देती हैं महत्व : मोहाली स्थित अमेठी यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रो. आरके कोहली ने कहा कि हिंसक घटनाओं और बिगड़े माहौल का असर विद्यार्थियों की प्लेसमेंट पर पड़ सकता है। कंपनियां विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्तर के साथ परिसर की स्थिति को भी ध्यान में रखती हैं। यदि किसी संस्थान में लगातार तनाव या अव्यवस्था बनी रहती है तो कंपनियां वहां कैंपस प्लेसमेंट में भाग लेने से पहले सुरक्षा और अन्य परिस्थितियों का आकलन कर सकती हैं।

उन्होंने कहा कि अभिभावक भी दाखिले के समय विश्वविद्यालय की प्लेसमेंट दर, कंपनियों की भागीदारी और कैंपस के वातावरण को महत्व देते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ परिसर में शांति, सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है।

प्लेसमेंट प्रक्रिया में कंपनियों के प्रतिनिधि विद्यार्थियों के साक्षात्कार, तकनीकी परीक्षण और समूह चर्चा जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से चयन करते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालयों को पहले से आवश्यक व्यवस्थाएं करनी होती हैं। यदि परिसर में तनाव या सुरक्षा संबंधी स्थिति बनी रहती है तो इन गतिविधियों के सुचारू संचालन में बाधा आ सकती है। इसका असर उन विद्यार्थियों पर पड़ सकता है, जो लंबे समय से प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को ऐसी घटनाओं के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ विद्यार्थियों के बीच संवाद और विश्वास बहाल करने पर भी ध्यान देना चाहिए।

अकाल तख्त के आदेश उल्लंघन पर एसजीपीसी के दो सदस्यों को नोटिस



भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के उल्लंघन के आरोप में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के दो वरिष्ठ सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। श्री अकाल तख्त साहिब सचिवालय की ओर से एसजीपीसी सदस्य मिट्ठू सिंह कानेके और जसवंत सिंह पुड़ैण से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोनों पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात करने का आरोप है।

सचिवालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से पहले जारी किए गए आदेशों के विपरीत है। दोनों सदस्यों को निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस मिलने के दस दिन के भीतर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण दें।

दस दिन में पेश होकर देना होगा जवाब : यह कार्रवाई श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज के आदेश पर किए जाने की बात कही गई है। सचिवालय के पत्र में संबंधित आदेशों और उनके पालन से जुड़े निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। दोनों सदस्यों से कथित अनुशासनहीनता को लेकर अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा गया है।

नोटिस जारी होने के साथ दोनों सदस्यों पर अंतरिम अनुशासनात्मक रोक भी लगाई गई है। जब तक वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण नहीं देते और श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे एसजीपीसी की बैठकों और अन्य एकत्रताओं में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

मुख्यमंत्री से मुलाकात बनी कार्रवाई का आधार : सचिवालय के अनुसार, पांच सिंह साहिबान की ओर से जारी आदेश में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से संबंधित पंथक स्तर का निर्णय लिया गया था। इसी पृष्ठभूमि में दोनों एसजीपीसी सदस्यों की मुख्यमंत्री से मुलाकात को आदेशों के उल्लंघन के तौर पर देखा गया है। अकाल तख्त और पंजाब सरकार के बीच इस वर्ष विभिन्न धार्मिक और कानूनी मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आए हैं। इसी क्रम में जून में अकाल तख्त की ओर से पंजाब सरकार के बेअदबी कानून से जुड़े प्रावधानों पर भी आपत्तियां जताई गई थीं।

जवाब के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई : अब दोनों सदस्यों को निर्धारित अवधि में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा। उनके लिखित स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत पेशी के बाद श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से मामले में आगे का निर्णय लिया जाएगा।

फिलहाल दोनों सदस्यों की ओर से नोटिस को लेकर कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनका पक्ष सामने आने के बाद मामले से जुड़े आरोपों और उनके जवाब की स्थिति अधिक स्पष्ट होगी।

ड्रग्स मामले में मजीठिया और भोला तलब पांच अक्टूबर को एसआइटी करेगी पूछताछ

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब के बहुचर्चित ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। एसआइटी ने उन्हें पांच अक्टूबर को जांच में शामिल होने के निर्देश दिए हैं। इसी दिन ड्रग्स मामले के प्रमुख आरोपित और बर्खास्त डीएसपी जगदीश सिंह भोला को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों को एक ही दिन तलब किए जाने की पुष्टि विभिन्न रिपोर्टों में हुई है।

मामला पंजाब में सामने आए सिंथेटिक ड्रग्स रैकेट से जुड़ा है, जिसे राजनीतिक और जांच के संदर्भ में करीब छह हजार करोड़ रुपये के कथित ड्रग्स मामले के तौर पर भी जाना जाता रहा है। मौजूदा जांच में एसआइटी का ध्यान ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और धन के प्रवाह पर भी है। जगदीश सिंह भोला का नाम वर्ष



2013 में सामने आए ड्रग्स रैकेट की जांच के दौरान प्रमुखता से सामने आया था। बाद की जांच में उनके और अन्य आरोपितों के बयान दर्ज किए गए। मजीठिया के खिलाफ दिसंबर 2021 में मादक पदार्थों से संबंधित कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मजीठिया ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से लगातार इनकार किया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में भी मजीठिया से जुड़े मामले में ड्रग्स नेटवर्क के आरोपितों के बयानों और कथित वित्तीय लेनदेन से संबंधित जांच बिंदुओं का उल्लेख है।

एसआइटी की मौजूदा जांच में कथित मनी ट्रेल को महत्वपूर्ण पहलू माना जा रहा है। जांच टीम वित्तीय दस्तावेजों, बैंक खातों में हुए लेनदेन और ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े संभावित आर्थिक संबंधों की पड़ताल कर रही है। पांच अक्टूबर की पूछताछ में पुराने बयानों के साथ वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों और जांच में सामने आए तथ्यों पर भी सवाल किए जा सकते हैं।

फेस्टिवल सीजन से पहले चंडीगढ़ में छापा, दूध-पनीर समेत चार सैंपल भरे

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। फेस्टिवल सीजन से पहले शहर में दूध और इससे बने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। शनिवार सुबह खाद्य सुरक्षा विंग की टीम ने सेक्टर-31 सी की बूथ मार्केट स्थित एक थोक सप्लायर के ठिकाने पर छापेमारी की। टीम सुबह करीब 5:30 बजे मौके पर पहुंची और वहां उपलब्ध खाद्य पदार्थों की जांच की। कार्रवाई के दौरान विभाग की टीम ने दूध, दही, क्रीम और पनीर के सैंपल लिए। इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। विभाग की ओर से सैंपलों की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप होने की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि संबंधित खाद्य पदार्थ गुणवत्ता मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। त्योहारों के दौरान दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता परखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विभाग की टीम सप्लायर के यहां मौजूद उत्पादों और उनकी गुणवत्ता से जुड़े पहलुओं की जांच कर रही है।

रावी सीमा पर सुरक्षा पर जोर, ड्रोन तस्करी रोकने की कवायद

मकौड़ा पत्तन पर स्थायी पुल और सीमावर्ती गांवों के विकास की उठी मांग

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से शुरू की गई प्रहार राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति को पंजाब की सीमा पर प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है। पंजाब के पूर्व विशेष मुख्य सचिव केबीएस सिद्धू ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर रावी नदी से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा मजबूत करने और सीमावर्ती गांवों की समस्याओं के समाधान के लिए सात सुझाव दिए हैं। पत्र की प्रति पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी भेजी गई है।

सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है, लेकिन इसका प्रभाव सीमा के अंतिम छोर तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने अपने सुझावों को प्रहार के सात स्तंभों से जोड़ते हुए पंजाब की सीमा की भौगोलिक और सुरक्षा परिस्थितियों के अनुसार उपाय करने की बात कही है। सिद्धू बटाला के जिला



मजिस्ट्रेट, अमृतसर के उपायुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह के रूप में सेवाएं दे चुके हैं।

सिद्धू ने रावी नदी के क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से चुनौतीपूर्ण बताते हुए कहा कि नदी लगभग हर मानसून में अपना बहाव बदलती है। ऐसे में नदी के बीच पारंपरिक बाड़ लगाना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में लागू व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली को रावी और सतलुज के नदी वाले हिस्सों तक विस्तार देने का सुझाव दिया। बाढ़ से निपटने के लिए बाड़ की डिजाइन सीमा सुरक्षा बल और पंजाब के सिंचाई विभाग के समन्वय से तैयार करने की बात कही गई है।

सीमा पार से ड्रोन के जरिये नशीले पदार्थों और अन्य सामान की तस्करी रोकने के लिए सिद्धू ने बहुस्तरीय काउंटर-ड्रोन व्यवस्था विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने ड्रोन से बरामद सामान और घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से संभावित ड्रॉप जोन की पहचान करने की बात कही। जिला पुलिस और प्रशासन से मिलने वाली सूचनाओं को राष्ट्रीय खुफिया तंत्र से जोड़ने का सुझाव भी दिया गया है।

उन्होंने सीमा जिलों में नशे और आतंकवाद से जुड़े मामलों के लिए विशेष अदालतें तथा नजदीक फोरेंसिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने की आवश्यकता बताई। सीमा क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार, नशामुक्ति और पुनर्वास को भी अभियान में प्रमुखता देने का सुझाव है।

सीमावर्ती गांवों की सुविधाओं के लिए गुरदासपुर के मकौड़ा पत्तन पर स्थायी पुल बनाने की मांग की गई है। वर्तमान में रावी पार बसे गांवों के लोग मौसमी पोंटून पुल पर निर्भर हैं। सीमा बाड़ के पार खेती करने वाले किसानों के लिए उचित गेट समय और मुआवजे की व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया है।

नगर निगम सेक्रेटरी पदोन्नति नियम बदले, ग्रेड-2 से भरेंगे 90 प्रतिशत पद

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने नगर निगमों में कारपोरेशन सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नति के नियमों में संशोधन किया है। अब इस पद के 90 प्रतिशत पद कारपोरेशन सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 के कर्मचारियों में से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि 10 प्रतिशत पद सुपरिंटेंडेंट (सैनिटेशन) के कर्मचारियों के लिए निर्धारित किए गए हैं। स्थानीय निकाय विभाग ने इस संबंध में 28 सितंबर को अधिसूचना जारी की है।

नए नियमों के अनुसार कारपोरेशन सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नति के लिए संबंधित कर्मचारी का स्नातक होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उसके पास संबंधित सेवा में कम से कम चार वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से



हासिल की गई होनी जरूरी है।

सुपरिंटेंडेंट (सैनिटेशन) श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति के लिए भी स्नातक की डिग्री और चार वर्ष का अनुभव अनिवार्य किया गया है। इस तरह दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करनी होगी।

सरकार ने यह संशोधन पंजाब म्यूनिसिपल कारपोरेशन सर्विसेज के वर्ष 1978 में बनाए गए भर्ती एवं सेवा नियमों में किया है।

बदलते मौसम में बच्चों समेत वयस्क भी आए फ्लू की चपेट में

मौसम बदलते ही बढ़ा फ्लू, पीजीआई में 170 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़ । मौसम में बदलाव के साथ फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में जनवरी से 26 अगस्त तक इन्फ्लूएंजा के 170 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इनमें करीब आधे मामले अगस्त में ही दर्ज हुए हैं। पीजीआई के आंकड़ों के अनुसार संक्रमितों में 83 पुरुष और 87 महिलाएं शामिल हैं।

कुल मरीजों में 36 बच्चे भी हैं, जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। वहीं 134 वयस्कों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक पंजाब से सबसे अधिक 68 मरीज पीजीआई पहुंचे। इसके बाद हरियाणा से 34, चंडीगढ़ से 28 और हिमाचल प्रदेश से 20 मरीज सामने आए। उत्तर



प्रदेश से भी 10 मरीज उपचार के लिए पहुंचे, जबकि अन्य राज्यों के मरीज भी पीजीआई में इलाज कराने आए।

मौसम में बदलाव के दौरान बच्चों को फ्लू से बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। स्कूल जाने वाले बच्चों में लगातार बुखार, खांसी या गले में खराश जैसे लक्षण दिखाई देने पर उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

फ्लू के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिरदर्द और शरीर में दर्द शामिल हैं। कुछ मामलों में सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। लक्षण गंभीर होने या लंबे समय तक बने रहने पर चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है।

दोराहा में बस-ट्राला टक्कर कंडक्टर की मौके पर मौत

भारतेंदु संवाददाता, दोराहा । जीटी रोड पर मैकडोनाल्ड के पास बुधवार तड़के करीब 5:40 बजे पीआरटीसी बस और ट्राले की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस के कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार पीआरटीसी बस दिल्ली से लौट रही थी और उसमें करीब 10 से 15 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद बस में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को बाहर निकालने में मदद की। मृतक कंडक्टर जीरा-मखू क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है और लुधियाना में ड्यूटी करता था। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पीआरटीसी कर्मचारी यूनियन के नेताओं और कर्मचारियों ने सड़क पर जाम लगाकर रोष जताया। उन्होंने फरार ट्राला चालक को गिरफ्तार करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की।

अमृतसर में नशा और हथियार तस्करी के तीन नेटवर्कों का हुआ पर्दाफाश



भारतेंदु संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले तीन नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 13 पिस्तौल, 3.267 किलो हेरोइन और 22 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में आरोपितों के नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की सप्लाई से जुड़े होने की बात सामने आई है।

पुलिस ने मामले में थाना डी-डिवीजन और थाना छेहरटा में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की हैं। गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के आधार पर पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि बरामद हथियार और हेरोइन कहां से लाई गई थी और इन्हें आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।

पुलिस के अनुसार मामले में नेटवर्क की पिछली और आगे की कड़ियों को जोड़ने के लिए जांच की जा रही है। हथियार और नशीले पदार्थ उपलब्ध कराने वालों के साथ-साथ इनके खरीदारों और अन्य सहयोगियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

जांच का एक अहम पहलू विदेशी हैंडलरों से आरोपितों के कथित संपर्क की पड़ताल करना है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपितों को हथियार और हेरोइन की आपूर्ति किस माध्यम से होती थी और इसके पीछे कौन लोग सक्रिय थे।

पंजाब में स्कूलों का समय बदला, सुबह साढ़े आठ से दोपहर 2:50 बजे तक होगी पढ़ाई

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में मौसम में बदलाव को देखते हुए स्कूलों के समय में आज से बदलाव लागू हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक कार्यालय की ओर से जारी नई समय-सारिणी के अनुसार आज से 31 अक्टूबर 2026 तक राज्य के स्कूल सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:50 बजे तक संचालित होंगे। नए समय के तहत स्कूलों में आठ पीरियड होंगे और विद्यार्थियों को बीच में 35 मिनट का अवकाश मिलेगा।

नई समय-सारिणी के अनुसार सुबह 8:30 से 8:55 बजे तक प्रार्थना सभा होगी। इसके बाद पहला पीरियड सुबह 8:55 से 9:35 बजे तक चलेगा। दूसरा पीरियड 9:35 से 10:15 बजे तक और तीसरा पीरियड 10:15 से 10:55 बजे तक होगा। चौथा पीरियड सुबह 10:55 से 11:35 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इसके बाद पांचवां पीरियड 11:35 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक चलेगा। इसके बाद विद्यार्थियों को 35 मिनट का अवकाश मिलेगा। अवकाश का समय दोपहर 12:15 से 12:50 बजे तक निर्धारित किया गया है।

दोपहर 2:50 बजे होगी छुट्टी : अवकाश के बाद छठा पीरियड दोपहर 12:50 से 1:30 बजे तक होगा। सातवां पीरियड 1:30 से 2:10 बजे तक चलेगा, जबकि आठवां और अंतिम पीरियड 2:10 से 2:50 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार विद्यार्थियों की छुट्टी दोपहर 2:50 बजे होगी।

विभाग के अनुसार यह समय-सारिणी अक्टूबर महीने के लिए लागू की गई है। मौसम की स्थिति और तापमान में बदलाव को देखते हुए इसके बाद स्कूलों के समय को लेकर विभाग की ओर से आगे निर्णय लिया जा सकता है। नई व्यवस्था का उद्देश्य



मौसम के अनुसार विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए स्कूल संचालन को व्यवस्थित करना है। नई व्यवस्था के तहत विद्यालयों को निर्धारित समय-सारिणी का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने स्कूल प्रबंधन से कहा है कि सभी कक्षाओं का संचालन तय समय के अनुसार किया जाए। प्रार्थना सभा, पीरियड और अवकाश के समय में किसी तरह का बदलाव न किया जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

वापसी फर्जी दस्तावेजों के सहारे ब्रिटेन पहुंचे पंजाबियों पर कार्रवाई, पुलिस प्रत्यर्पण प्रक्रिया करेगी शुरू

फर्जी ई-वीजा मामले में 14 पंजाबियों के खिलाफ वारंट जारी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। फर्जी ई-वीजा और रोजगार संबंधी दस्तावेजों के सहारे ब्रिटेन पहुंचे पंजाब के 14 लोगों को वापस लाने के लिए पंजाब पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (बीओआई) ने मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआइटी) की रिपोर्ट के आधार पर सभी 14 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। अब गृह मंत्रालय के माध्यम से ब्रिटेन से उनके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। पुलिस ब्रिटेन से जांच के लिए जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य हासिल करने के लिए कानूनी सहायता अनुरोध भी भेजेगी।

मामला इस वर्ष जनवरी में सामने आया था। एसआइटी की जांच के अनुसार पंजाब के रहने वाले 14 लोग 11 से 16 जनवरी के बीच अमृतसर से एयर इंडिया की उड़ानों से लंदन पहुंचे थे। आरोप है कि यात्रियों ने यात्रा के दौरान मोबाइल फोन में फर्जी ई-वीजा और रोजगार संबंधी दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट दिखाए थे। ब्रिटेन पहुंचने के बाद सभी ने वहां शरण मांगी।

जांच के अनुसार पांच यात्री 11 जनवरी को अमृतसर से लंदन पहुंचे थे। ब्रिटेन पहुंचने के बाद उन्होंने शरण मांगी, जिसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया। उनके यात्रा दस्तावेजों की जांच में कथित तौर पर फर्जीवाड़ा सामने आया। ब्रिटेन की ओर से इसकी जानकारी एयर इंडिया और भारतीय अधिकारियों को दी गई।



इसके बावजूद 16 जनवरी को नौ अन्य यात्री कथित रूप से इसी तरह के दस्तावेजों के साथ अमृतसर से लंदन रवाना हो गए। इसके बाद एयर इंडिया और हवाई अड्डे की भूमि प्रबंधन व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई।

एसआइटी अब तक 30 लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। इनमें 14 यात्री, एयर इंडिया के तीन कर्मचारी, एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज के चार कर्मचारी, कई यात्रा एजेंट और अन्य संदिग्ध शामिल हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि 14 में से 10 यात्रियों की टिकट बुकिंग में कथित तौर पर एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस इसे यात्रियों की यात्रा व्यवस्था किसी एक व्यक्ति या संगठित नेटवर्क के जरिये कराए जाने के संभावित संकेत के रूप में देख रही है।

एयरलाइन और भूमि प्रबंधन से जुड़े कर्मचारियों के लैपटाप, मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए हैं। पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट के आधार पर यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि संबंधित कर्मचारियों की इस पूरे मामले में क्या भूमिका रही। इसके बाद उनके खिलाफ आगे वारंट जारी करने अथवा अन्य कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में वेतन विधेयक पर नेकां और भाजपा विधायकों में तीखी बहस

विधायकों के वेतन, कर्मचारियों की मांगों और इंटरनेट मीडिया नीति पर सदन में हंगामा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अंतिम दिन बुधवार को विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी से जुड़े विधेयक को वापस लिए जाने के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) और भाजपा विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पहलगाम से नेकां विधायक अल्ताफ कल्लू ने कुछ दस्तावेज लहराते हुए दावा किया कि भाजपा के विधायकों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अब भाजपा इस मुद्दे पर अलग रुख अपना रही है।

भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने कल्लू के आरोपों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने विधेयक को खारिज नहीं किया, बल्कि सरकार ने इसे वापस लिया है। शर्मा ने कहा कि विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के बजाय सरकार को दिहाड़ी मजदूरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, कैजुअल कर्मचारियों और अन्य अस्थायी कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई कर्मचारी नियमितीकरण और अन्य लाभों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।



इस दौरान विधानसभा परिसर में विधायकों के बीच अलग-अलग मुद्दों को लेकर नोकझोंक देखने को मिली। अंतिम दिन की कार्यवाही में वेतन विधेयक, कर्मचारियों की मांगों, इंटरनेट मीडिया के नियमन और विधायकों को बोलने का अवसर नहीं मिलने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। इसके अलावा सदन में विधायकों की कार्यशैली और कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई।

बहस के दौरान शर्मा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति केवल पैसे के लिए सदन में आया है तो उसे निजी नौकरी करनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और तेज हो गई। मामले को बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मंगलवार को ही चर्चा हो चुकी है और इसे दोबारा उठाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू कराया गया।

सदन में अनियंत्रित इंटरनेट मीडिया के इस्तेमाल का मुद्दा भी उठा। कुछ विधायकों ने ऐसे इंटरनेट मीडिया उपयोगकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई और नियमन की मांग की। मंत्री सकीना इटू ने बताया कि इस विषय की जांच के लिए विधायक अली मोहम्मद सागर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति ने सूचना विभाग को व्यापक मीडिया नीति तैयार करने की जिम्मेदारी दी है। यह नीति चार महीने के भीतर तैयार किए जाने की बात कही गई।

प्रश्नकाल के दौरान डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक मेहराज मलिक बोलने का अवसर नहीं मिलने से नाराज होकर सदन के वेल में पहुंच गए। उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की और कुछ नेकां विधायकों से भी बातचीत की। लगातार विरोध करने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें सदन से बाहर निकालने का निर्देश दिया। इसके बाद मार्शलों ने मेहराज मलिक को विधानसभा से बाहर कर दिया।

लेह से सात गंतव्यों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर शुरू

लेह। लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में हवाई संपर्क मजबूत करने के लिए लेह से सात गंतव्यों के लिए रियायती एकल-इंजन हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर शुरू कर दी हैं। ये सेवाएं 29 सितंबर से शुरू हुई हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के सहयोग से पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही हैं। प्रशासन के अनुसार, हेलीकॉप्टर सेवा के तहत लेह को कारगिल, पदुम, लिंगशेड, दिब्लिंग, न्येराक, डिस्किट और तुरतुक से जोड़ा गया है। इससे सर्दियों के दौरान इन क्षेत्रों के लोगों को आवागमन का वैकल्पिक साधन मिलेगा। आपातकालीन चिकित्सा जरूरतों में भी इन सेवाओं की मदद ली जा सकेगी। लेह-कारगिल मार्ग का रियायती किराया 7,750 रुपये प्रति यात्री निर्धारित किया गया है और उड़ान में करीब 50 मिनट लगेंगे। लेह-पदुम का किराया 6,975 रुपये और यात्रा अवधि करीब 45 मिनट होगी। लिंगशेड, दिब्लिंग, न्येराक और डिस्किट के लिए किराया 4,650 रुपये रखा गया है, जबकि उड़ान अवधि करीब 30 मिनट होगी।

पत्रकारों के लिए नई गाइडलाइन बनाने को समिति सूचना विभाग संग करेगी काम

चार महीने में पत्रकारों के लिए नई मीडिया नीति होगी तैयार : सकीना इटू

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार नई मीडिया नीति तैयार करने पर काम कर रही है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि पत्रकारों और मीडिया क्षेत्र के लिए नई गाइडलाइन चार महीने के भीतर तैयार कर ली जाएगी। इसके लिए पहले ही एक समिति गठित की जा चुकी है, जिसने नीति तैयार करने के लिए चार महीने का समय मांगा है। समिति सूचना विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है।

सकीना इटू ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है और मीडिया के बिना सरकार तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज अधूरा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रेस की भूमिका को महत्व देती है, लेकिन इंटरनेट मीडिया से पैदा होने वाली समस्याओं के लिए केवल पत्रकारों और मीडिया को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

मंत्री ने कहा कि इंटरनेट मीडिया के मौजूदा माहौल के लिए राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि खुद इंटरनेट मीडिया पर सामग्री साझा करते हैं और कई बार उसके प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने एक विधायक से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि कथित तौर पर एक घरेलू कर्मचारी के नाम से इंटरनेट मीडिया पेज चलाया जा रहा था। इस पेज पर कुछ ऐसी सामग्री भी डाली गई थी, जिसे लेकर असहज स्थिति बनी।

इटू ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भी इंटरनेट मीडिया पर अपने व्यवहार और गतिविधियों की समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने पुराने समय का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले लोग सार्वजनिक प्रसारक पर अपनी खबर प्रसारित होने का इंतजार करते थे। टेलीविजन समाचार का उस समय अलग महत्व था और लोग अपनी खबर प्रसारित होने पर उत्साहित होते थे। इंटरनेट मीडिया के विस्तार के बाद समाचार और सामग्री प्रसारित करने का तरीका तेजी से बदला है।

मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर से सदन के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विचार करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सदन में मोबाइल फोन की अनुमति होने से कार्यवाही की रिकॉर्डिंग की जा सकती है और बाद में उसके अंश इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जा सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर में बाढ़ से 507 करोड़ का नुकसान, राजौरी-पुंछ सबसे ज्यादा प्रभावित



भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में हालिया भारी बारिश और बाढ़ से बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। जल शक्ति विभाग ने विधानसभा में दी जानकारी में बताया कि प्रभावित ढांचे की बहाली के लिए कुल 507.47 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आंकी गई है। इसमें जम्मू संभाग में 449.42 करोड़ रुपये और कश्मीर संभाग में 58.05 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह जानकारी गुलमर्ग के विधायक पीरजादा फारूक अहमद शाह के सवाल के जवाब में दी गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जम्मू संभाग में बाढ़ और भारी बारिश से 1955 सड़कें, 1238 जलापूर्ति योजनाएं, 369 स्कूल और 11 स्वास्थ्य ढांचे प्रभावित हुए हैं। इनमें राजौरी और पुंछ जिले सबसे अधिक प्रभावित बताए गए हैं।

चार सहकर्मियों की हत्या का आरोपित सीआईएसएफ जवान गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ/बसोहली। जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के बसोहली माश्का क्षेत्र स्थित सेवा-2 जलविद्युत परियोजना में मंगलवार को सीआईएसएफ के एक हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर अपने चार सहकर्मियों पर सर्विस राइफल से गोली चला दी। घटना में सहायक कमांडेंट समेत चार कर्मियों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के कारणों की जांच की जा रही है। एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि गोलीबारी में चार लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि वारदात के पीछे क्या कारण रहा, इसकी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में आरोपित और कुछ सहकर्मियों के बीच पुरानी कहासुनी तथा विवाद की बात सामने आई है।

कुलगाम में 37 वर्षीय मजदूर का शव मिलने से सनसनी

भारतेंदु संवाददाता, कुलगाम। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार को 37 वर्षीय एक मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार, डीएच पोरा क्षेत्र में नंदीमार्ग-नुम्बलन सड़क के पास स्थानीय लोगों ने शव पड़ा देखा। इसके बाद उन्होंने तत्काल संबंधित पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक की पहचान डोबडाबन नंदीमार्ग निवासी करम दीन गोरसी के पुत्र बशीर अहमद गोरसी (37) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस शव मिलने के कारणों का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है।

पार्ट टाइम नौकरी का झांसा साइबर ठगों से सतर्क रहें जम्मूवासी

ठग नौकरी के बहाने बैंकिंग जानकारी लेकर कर रहे खाते खाली

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू



घर बैठे पार्ट टाइम नौकरी कर मोटी कमाई का लालच देकर साइबर ठग लोगों को निशाना बना रहे हैं। जम्मू पुलिस ने लोगों से अज्ञात नंबरों से आने वाले ऐसे फर्जी नौकरी के प्रस्तावों से सतर्क रहने की अपील की है। ठग आमतौर पर व्हाट्सएप या मोबाइल संदेश के जरिये संपर्क करते हैं और कुछ घंटे काम के बदले आकर्षक आमदनी का झांसा देते हैं।

बातचीत आगे बढ़ने पर ठग नौकरी की प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर बैंक खाते, एटीएम या डेबिट कार्ड, ओटीपी, यूपीआई पिन और अन्य निजी जानकारी मांगते हैं। कई मामलों में संदिग्ध लिंक भेजकर उस पर क्लिक करने या कोई एप डाउनलोड करने के लिए भी कहा जाता है। इसके बाद खाते से रकम निकालने या अन्य तरीके से आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

जम्मू के एसएसपी जोगिंदर सिंह ने लोगों को सलाह दी है कि कम समय में अधिक कमाई और घर बैठे नौकरी के प्रस्तावों पर बिना जांच के भरोसा न करें। किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। नौकरी के नाम पर पहले पैसे जमा कराने की मांग होने पर भी सतर्क रहने की जरूरत है।

पुलिस ने लोगों से कहा है कि कंपनी और नौकरी की पूरी जानकारी स्वतंत्र रूप से जांचें। संदिग्ध संदेशों और लिंक से दूरी बनाए रखें।

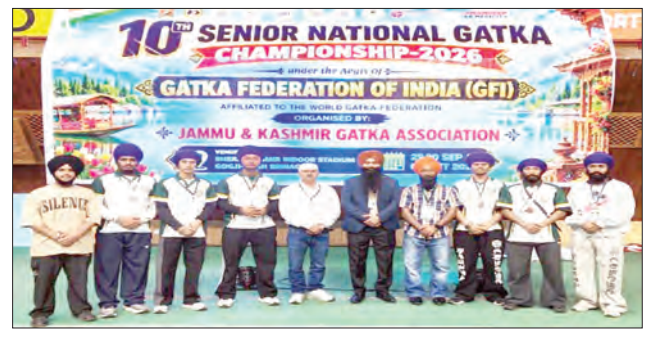
कठुआ में अनुच्छेद 370 के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य का पूर्ण दर्जा बहाल करने संबंधी प्रस्ताव में स्वायत्तता और विशेष दर्जे से जुड़े संदर्भों को लेकर कठुआ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। जिला भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका। भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में है, लेकिन अनुच्छेद 370 और वर्ष 2019 से पहले की विशेष संवैधानिक व्यवस्था की वापसी का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि पांच अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव हुआ है और इसे पीछे ले जाने वाले किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा।

श्रीनगर में हिमाचली खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

अजय कुमार और गुरप्रीत सिंह ने राष्ट्रीय गतका प्रतियोगिता में जीते कांस्य पदक

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



शेरे कश्मीर स्टेडियम, श्रीनगर में आयोजित दसवीं सीनियर नेशनल गतका प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 29 सितंबर से एक अक्तूबर तक आयोजित हो रही प्रतियोगिता के दूसरे दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में दमखम दिखाया।

इंडिविजुअल डेमो स्पर्धा में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी अजय कुमार ने तृतीय स्थान हासिल कर कांस्य पदक जीता। वहीं, गुरप्रीत सिंह ने इंडिविजुअल फाइट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन से हिमाचल की गतका टीम में उत्साह का माहौल है।

अजय कुमार और गुरप्रीत सिंह की उपलब्धि पर गतका स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने खुशी जताई। एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन संजय पराशर, उपाध्यक्ष शुभकरण सिंह, महासचिव सुनीता देवी, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह तथा समन्वयक सुभाष चंद, रविंद्र कुमार और अमर सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिमाचल के खिलाड़ियों का पदक जीतना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। अजय कुमार और गुरप्रीत सिंह का प्रदर्शन अन्य खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रतियोगिता के आगामी मुकाबलों में भी हिमाचल के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

बलहामा में जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर का आरोप

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र बलहामा में सेवानिवृत्त मत्स्य निदेशक मुफ्ती मंजूर की जमीन पर दूसरे व्यक्ति का मकान बनता मिलने के बाद सामने आया कथित जमीन फर्जीवाड़ा अब सात आरोपितों तक पहुंच गया है। मामले में तत्कालीन तहसीलदार नुसरत अजीज, पटवारी आशिक अली और जमीन ब्रोकर रियाज अहमद बट समेत सात लोगों को आरोपित बनाया गया है।

मामला वर्ष 2017 में सामने आया, जब मंजूर वर्षों बाद अपनी जमीन देखने पहुंचे। उन्होंने वर्ष 2012 में बलहामा में तीन प्लॉट खरीदे थे। जमीन के बिक्री विलेख पंजीकृत होने और स्टांप शुल्क जमा करने के बाद उनका म्यूटेशन परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज किया गया था। लेकिन मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जमीन पर बाड़ लगी थी और मकान का निर्माण हो रहा था।

शिकायत के बाद हुई जांच में आरोप है कि परिवार के नाम दर्ज म्यूटेशन करीब 58 दिन बाद रद कर दी गई। इसके बाद जमीन से जुड़े नए राजस्व दस्तावेज तैयार कर उसे दोबारा बेचने का रास्ता बनाया गया। जांच में एक कनाल जमीन नुसरत अजीज के नाम स्थानांतरित होने की बात भी सामने आई।

जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों के बोर्ड परिणाम में दस प्रतिशत सुधार

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

डिजिटल शिक्षा से बदली तस्वीर



जम्मू-कश्मीर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किए जा रहे सुधारों का असर अब बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी दिखाई देने लगा है। सरकार के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड परिणाम में एक वर्ष के भीतर करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं और कौशल शिक्षा को भी विस्तार दिया जा रहा है।

विधानसभा में जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता के सवाल के जवाब में सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति और उनमें किए जा रहे सुधारों का ब्योरा दिया। सरकार ने बताया कि नई शिक्षा नीति-2020 के तहत स्कूलों में आधारभूत ढांचे और शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं।

सरकार के अनुसार गुजरात मॉडल की तर्ज पर तैयार विद्या समीक्षा केंद्र सितंबर 2024 से संचालित है। यह कमांड और नियंत्रण केंद्र आंकड़ों के आधार पर स्कूलों की निगरानी और शैक्षणिक परिणामों में सुधार के लिए काम कर रहा है। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों की गतिविधियों और विद्यार्थियों की प्रगति पर बेहतर निगरानी संभव हुई है।

बडगाम में ढेर हुआ पहलगाम हमले का वांछित आतंकी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षाबलों ने तलाशी अभियान के दौरान पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा का शव बरामद किया है। चिनार कोर ने बुधवार को उसकी पहचान की पुष्टि की। शव पालमैदान इलाके में तलाशी के दौरान बरामद हुआ। उसके पास से युद्ध में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला।

सुरक्षाबलों ने मंगलवार देर रात विशेष खुफिया सूचना के आधार पर यूसमर्ग के कोराग इलाके में ऑपरेशन कोराग शुरू किया था। सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जवानों ने संदिग्ध गतिविधि देखी। सुरक्षाबलों ने चुनौती दी तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। अभियान के बाद इलाके में तलाशी जारी रही और बुधवार सुबह हाशिम मूसा का शव बरामद किया गया।

हाशिम मूसा का नाम 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच में प्रमुख संदिग्धों में सामने आया था। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय नागरिक समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली सूचना के लिए 20 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मूसा पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप का पूर्व पैरा-कमांडो था और बाद में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था। उसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिसंबर 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा, द रेजिस्टेंस फ्रंट और छह अन्य आरोपितों के खिलाफ 1,597 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन और उसके नेटवर्क की भूमिका का उल्लेख किया गया था।

अरनिया में पाकिस्तानी नंबरों से संपर्क के शक में बिहार का युवक पकड़ा



भारतेंदु संवाददाता, बिश्नाह। अरनिया के सीमावर्ती क्षेत्र काकू दे कोठे में सुरक्षा एजेंसियों और अरनिया पुलिस ने संदिग्ध गतिविधियों के संदेह में बिहार के एक युवक को हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवक की पहचान तारा चंद सदादा निवासी शोरिगौना, जिला अररिया (बिहार) के रूप में हुई है। युवक वर्तमान में अरनिया में किराये के मकान में रहकर मजदूरी करता था। सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि युवक आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे कुछ संदिग्ध लोगों के संपर्क में था। उसके मोबाइल फोन की जांच के दौरान कुछ पाकिस्तानी मोबाइल नंबर मिलने की बात सामने आई है। हालांकि, इन नंबरों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया गया और युवक का किसी संदिग्ध नेटवर्क से संबंध है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। मामले की सूचना मिलने के बाद आरएसपुरा के उपमंडल पुलिस अधिकारी गुरमीत सिंह भी अरनिया थाने पहुंचे। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां युवक से पूछताछ कर रही हैं।

नेत्रसेवा दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंचा विशेषज्ञ उपचार, डेढ़ लाख से अधिक लोगों की आंखों की हुई जांच

तंगधार में ऑपरेशन दृष्टि ने लौटाई 446 लोगों की आंखों की रोशनी

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर



जम्मू-कश्मीर के दूरदराज, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों को विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए गए 'ऑपरेशन दृष्टि' के दूसरे चरण का समापन हो गया। इस अभियान के तहत अब तक 1.5 लाख से अधिक लोगों की आंखों की जांच की गई, जबकि 446 मोतियाबिंद सर्जरी सफलतापूर्वक की गईं। अभियान का उद्देश्य उन लोगों तक आधुनिक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना रहा, जिनके लिए बड़े अस्पतालों तक पहुंचना कठिन है।

बादामी बाग छावनी स्थित चिनार ऑडिटोरियम में आयोजित समापन समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभियान से जुड़े चिकित्सकों, सेना के अधिकारियों, चिकित्सा दलों और सहयोगी कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद जरूरतमंद लोगों तक विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना इस पहल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उपराज्यपाल ने कुपवाड़ा के तंगधार क्षेत्र में किए गए चिकित्सा प्रयासों का विशेष उल्लेख किया। पहाड़ी भूभाग, सीमावर्ती क्षेत्र, कठिन सड़क संपर्क और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बीच वहां भूमिगत ऑपरेशन थिएटर तैयार किया गया। चिकित्सा उपकरणों को भी हवाई मार्ग से पहुंचाया गया। इस सुविधा के माध्यम से स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र के निकट ही विशेषज्ञ नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराई गई।

सिन्हा ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं केवल शहरों और बड़े चिकित्सा संस्थानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तंगधार जैसे क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा पहुंचाना सामूहिक प्रयास और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है।

1.5 लाख से अधिक लोगों की जांच

अभियान के दौरान 1.5 लाख से अधिक लोगों की नेत्र जांच की गई। इनमें से जरूरत के अनुसार मरीजों को आगे के उपचार और सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 446 मोतियाबिंद सर्जरी पूरी होने से प्रभावित लोगों को दृष्टि संबंधी समस्या से राहत मिली। उपराज्यपाल ने कहा कि किसी व्यक्ति की दृष्टि बहाल होना केवल चिकित्सा उपलब्धि नहीं, बल्कि उसके दैनिक जीवन, आत्मनिर्भरता और सामाजिक गरिमा से भी जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन दृष्टि' की वास्तविक सफलता उन लोगों के जीवन में दिखाई देती है, जिन्हें उपचार के बाद बेहतर जीवन जीने का अवसर मिला।

सेना और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग

सिन्हा ने अभियान में भारतीय सेना, चिकित्सकों, चिकित्सा दलों और अन्य कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने के साथ सेना और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग और विश्वास भी मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि कठिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना केवल उपचार देने तक सीमित नहीं है। यह लोगों को भरोसा दिलाने का भी माध्यम है कि उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है। उपराज्यपाल ने कहा कि शिविर का समापन अभियान का अंत नहीं है।

हिमाचल के राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्ट फूड नहीं, हिमाचली व्यंजनों की महके खुशबू





विशाल कल्याण

हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और स्वादिष्ट पारंपरिक खान-पान के लिए पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। हर वर्ष करोड़ों पर्यटक यहां की वादियों, मंदिरों, बर्फ से ढके पहाड़ों और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित अधिकतर ढाबों और रेस्तरां में पर्यटकों को पिज्जा, बर्गर, मोमोज, नूडल्स जैसे फास्ट फूड अधिक मिलते हैं, जबकि हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन बहुत कम दिखाई देते हैं। यह स्थिति सांस्कृतिक पहचान के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है।

हिमाचल का पारंपरिक भोजन केवल स्वाद नहीं, बल्कि यहां की जलवायु, कृषि और जीवनशैली से जुड़ी सांस्कृतिक धरोहर है। धाम, सिड्डू, मदरा, बबरू, चना मद्रा, पटांडे, सेपू बड़ी, तुदकिया भात, भेय, मक्की की रोटी, सरसों का साग और लिंगड़ी की सब्जी जैसे व्यंजन स्थानीय परंपरा का हिस्सा हैं। ये व्यंजन न केवल पौष्टिक हैं, बल्कि स्थानीय अनाज, दालों और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हैं। यदि इन्हें राजमार्गों के भोजनालयों में प्रमुख स्थान दिया जाए, तो पर्यटक हिमाचल के वास्तविक स्वाद और संस्कृति से परिचित हो सकते हैं।

आज फास्ट फूड का प्रसार तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यह जल्दी उपलब्ध होता है और बड़े ब्रांडों का प्रभाव अधिक है, लेकिन अधिकांश पर्यटक किसी नए स्थान पर वहां का स्थानीय भोजन अनुभव करना चाहते हैं। यदि उन्हें हर जगह वही वैश्विक फास्ट फूड मिलेगा, तो वे हिमाचल की विशिष्ट खाद्य पहचान से वंचित रह जाएंगे। पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देने से स्थानीय किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। हिमाचल के किसान मक्का, जौ, राजमा, दालें, घी और स्थानीय मसालों का उत्पादन करते हैं। यदि होटल और ढाबे इनका अधिक उपयोग करें, तो किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों और छोटे उद्यमियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।

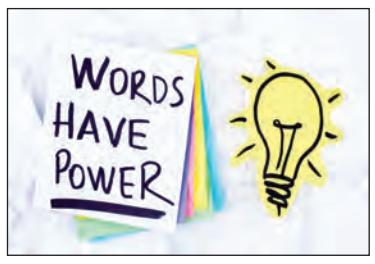
स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पारंपरिक भोजन फास्ट फूड की तुलना में अधिक लाभदायक है। इसमें मोटे अनाज, दालें, दही और देसी घी का संतुलित उपयोग होता है, जबकि फास्ट फूड में अधिक तेल, नमक और चीनी होती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती हैं। सरकार और पर्यटन विभाग इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर ढाबों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे अपने मेन्यू में पारंपरिक हिमाचली व्यंजन शामिल करें। इसके लिए प्रमाणन, कर छूट और पर्यटन सूची में स्थान जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं।

इसके साथ 'हिमाचली फूड कॉर्नर' जैसी अवधारणाएं विकसित की जा सकती हैं, जहां भोजन के साथ उसकी सांस्कृतिक जानकारी भी दी जाए। डिजिटल माध्यमों और सोशल मीडिया के जरिए इन व्यंजनों का प्रचार किया जाए ताकि वे एक पर्यटन आकर्षण बन सकें। फास्ट फूड को पूरी तरह समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पारंपरिक भोजन को समान या अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर हिमाचल अपनी खाद्य विरासत को संरक्षित कर सकता है।

हिमाचल के राष्ट्रीय राजमार्ग केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे राज्य की संस्कृति, परंपरा और पहचान के परिचायक भी हैं। यदि इन मार्गों पर यात्रियों का स्वागत हिमाचली व्यंजनों की खुशबू से हो, तो यह न केवल पर्यटकों के अनुभव को समृद्ध करेगा बल्कि स्थानीय किसानों, महिलाओं, उद्यमियों और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देगा। समय की मांग है कि हिमाचल अपने पारंपरिक भोजन को केवल त्योहारों और विशेष अवसरों तक सीमित न रखे, बल्कि उसे हर राजमार्ग, हर ढाबे और हर पर्यटक की थाली तक पहुंचाए।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

बोलचाल से झलकते हैं संस्कार और मानसिकता, शब्द बनाते व्यक्तित्व की पहचान





राकेश डोगरा
वरिष्ठ पत्रकार

भाषा मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इसी भाषा के माध्यम से हम अपने विचार, भावनाएं और संस्कार एक-दूसरे तक पहुंचाते हैं। कहा भी जाता है कि 'बोल ही मनुष्य की पहचान है।' व्यक्ति कैसा है, उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसकी सोच कितनी व्यापक है-यह सब उसकी बोलचाल से ही स्पष्ट हो जाता है। हमारी बोलचाल केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारे घर, परिवार, समाज और संस्कारों का आईना है।

संस्कार वह बीज हैं जो हमें बचपन से माता-पिता, परिवार और समाज द्वारा दिए जाते हैं। जिस घर में बड़ों का आदर करना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना सिखाया जाता है, उस घर के बच्चों की भाषा में भी मिठास और शालीनता दिखाई देती है। इसके विपरीत जिस घर में गाली-गलौज और कटु वचन आम हैं, वहां के लोग अनजाने में ही कठोर भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे पहली बार मिलता है तो वह आपके कपड़े या धन से नहीं, बल्कि आपके दो-चार वाक्यों से प्रभावित होता है। 'कृपया', 'धन्यवाद', 'क्षमा करें', 'आप कैसे हैं' जैसे छोटे-छोटे शब्द हमारे संस्कारों की गहराई बताते हैं। एक सुसंस्कृत व्यक्ति क्रोध में भी अपनी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्द एक बार मुंह से निकल जाएं तो वापस नहीं आते। देवभूमि हिमाचल में आज भी बुजुर्गों के पैर छूकर 'राम राम जी' कहना, पड़ोसी से 'नमस्ते' के साथ हालचाल पूछना आम बात है। यह केवल अभिवादन नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे संस्कारों का प्रतीक है।

मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि व्यक्ति जो बोलता है, वही सोचता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर बात में कमी निकालेगा, शिकायत करेगा और ताने देगा। वहीं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर स्थिति में उम्मीद और समाधान की बात करेगा। उदाहरण के लिए-बस लेट हो जाए तो एक व्यक्ति बोलेगा 'क्या बेकार सिस्टम है, कुछ नहीं हो सकता'। दूसरा व्यक्ति बोलेगा 'कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अगली बस पकड़ लेंगे।' दोनों की परिस्थिति एक है, पर बोलचाल अलग है। यहीं से उनकी मानसिकता का पता चलता है। आज सोशल मीडिया के युग में भी यही देखने को मिलता है। कुछ लोग कमेंट में दूसरों का सम्मान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। वहीं, कुछ लोग छोटी-छोटी बात पर ट्रोलिंग और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह सब उनकी अंदर की मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में अभिवादन का विशेष महत्व है। 'नमस्ते', 'राम-राम', 'सलाम', 'सत श्री अकाल' और 'आदाब' जैसे शब्द केवल अभिवादन नहीं, बल्कि सम्मान, प्रेम, अपनापन और अच्छे संस्कारों के प्रतीक हैं। ये हमारी सभ्यता और पारिवारिक मूल्यों को दर्शाते हैं। जब हम किसी का आदरपूर्वक अभिवादन करते हैं, तो संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ता है तथा वातावरण सकारात्मक बनता है। व्यक्ति की भाषा उसके संस्कार, शिक्षा और मानसिकता का परिचय देती है। मीठी वाणी से कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, जबकि कटु शब्द अच्छे संबंधों को भी तोड़ सकते हैं। संत तुलसीदास ने कहा है- 'ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय।' यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

आधुनिक जीवनशैली और पश्चिमी प्रभाव के कारण हमारी बोलचाल में परिवर्तन आया है। अंग्रेजी बोलना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा, शिष्टाचार और बड़ों के सम्मान को भूलना उचित नहीं। बच्चों में विनम्र भाषा, अभिवादन की आदत और बड़ों का सम्मान करने के संस्कार विकसित करना समय की आवश्यकता है। हमें बोलने से पहले यह अवश्य सोचना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को आहत तो नहीं करेंगे। मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार और सम्मानजनक भाषा ही सच्चे व्यक्तित्व की पहचान हैं। धन, पद और रूप-रंग समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और मीठी वाणी जीवनभर सम्मान दिलाते हैं।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

संपादकीय

जब हर तरफ हो खामोशी

कल्पना कीजिए कि एक सुबह आपकी आंख खुलती है और पूरा शहर असामान्य रूप से शांत है। सड़कों पर कोई वाहन नहीं, बाजार बंद हैं, मोबाइल पर कोई संदेश नहीं, आसपास किसी इंसान की आवाज नहीं। आप घर से बाहर निकलते हैं और दूर-दूर तक केवल खाली सड़कें दिखाई देती हैं। कुछ देर बाद आपके मन में एक सवाल उठता है—क्या इस पूरी दुनिया में अब केवल मैं ही जीवित हूं?

यह कल्पना सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन इसके भीतर मनुष्य के अस्तित्व, अकेलेपन और संघर्ष की कई गहरी परतें छिपी हैं। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में अकेला जीवित बच जाए, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल भोजन, पानी और सुरक्षित स्थान की तलाश नहीं होगी, बल्कि अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना भी होगी। मनुष्य मूल रूप से सामाजिक प्राणी है। हमारी पहचान परिवार, मित्रों, पड़ोस, समाज और दूसरे लोगों के साथ संबंधों से बनती है। अचानक इन सभी संबंधों का समाप्त हो जाना व्यक्ति के मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। शुरुआत में उसे स्वतंत्रता का अनुभव हो सकता है। कोई रोकने-टोकने वाला नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई समय सीमा नहीं। लेकिन कुछ ही समय बाद यही स्वतंत्रता भयावह अकेलेपन में बदल सकती है।

ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। उसे सुरक्षित स्थान तलाशना होगा, पीने के पानी और भोजन की व्यवस्था करनी होगी तथा मौसम और अन्य संभावित खतरों से बचने के उपाय करने होंगे। बिजली, संचार और परिवहन जैसी आधुनिक सुविधाएं धीरे-धीरे बंद हो सकती हैं। जिन चीजों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में सामान्य मानते हैं, उनका महत्व तब समझ आएगा जब वे अचानक उपलब्ध नहीं होंगी। लेकिन वास्तविक संघर्ष मन के भीतर शुरू होगा। किसी से बात करने वाला न हो तो व्यक्ति अपने विचारों के साथ अकेला रह जाएगा। उसे पुराने रिश्ते, परिवार और बीते हुए जीवन की याद सताएगी। वह शायद उन छोटी-छोटी बातों को याद करेगा जिन्हें सामान्य जीवन में वह महत्व नहीं देता था—परिवार के साथ भोजन, दोस्तों के साथ हंसी-मजाक, बाजार की भीड़, सड़क पर लोगों की आवाजें और किसी अनजान व्यक्ति का साधारण-सा अभिवादन।

समय के साथ व्यक्ति को अपने लिए एक नई दिनचर्या बनानी होगी। सुबह उठना, भोजन और पानी की व्यवस्था करना, सुरक्षित स्थान की देखभाल करना, उपलब्ध संसाधनों को बचाकर रखना और शारीरिक गतिविधि करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। मानसिक रूप से सक्रिय रहने के लिए वह किताबें पढ़ सकता है, डायरी लिख सकता है या अपने अनुभवों को दर्ज कर सकता है। शायद वह भविष्य के किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए संदेश भी लिखे, ताकि उसकी कहानी पूरी तरह उसके साथ समाप्त न हो। इस परिस्थिति में सबसे कठिन सवाल होगा—जीने का उद्देश्य क्या है? जब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी सफलता देखने के लिए मौजूद नहीं है, तब आप किसलिए संघर्ष करेंगे? यही प्रश्न मनुष्य को यह समझने पर मजबूर कर सकता है कि जीवन का मूल्य केवल दूसरों की मौजूदगी से नहीं, बल्कि स्वयं जीवन की अनुभूति से भी जुड़ा है।

हो सकता है कि अकेला जीवित व्यक्ति हर दिन किसी दूसरे इंसान की तलाश करे। वह दूर तक यात्रा करे, रेडियो संकेत भेजे, ऊंची इमारतों पर संदेश लिखे या किसी सुरक्षित स्थान पर अपने होने के निशान छोड़े। हर आवाज उसे उम्मीद दे सकती है और हर खाली सड़क निराश कर सकती है। लेकिन उम्मीद बनाए रखना ही उसके अस्तित्व का सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इस कल्पना का सबसे महत्वपूर्ण संदेश शायद यह है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, उसकी असली कीमत हमें तब समझ आती है जब हम उसके खो जाने की कल्पना करते हैं। परिवार की आवाज, दोस्तों की मौजूदगी, पड़ोसी की दस्तक, बाजार की हलचल और किसी के साथ बैठकर चाय पीना—ये सभी सामान्य लगने वाली चीजें वास्तव में हमारे जीवन को अर्थ देती हैं।

इसलिए 'अकेला उत्तरजीवी' केवल किसी विनाश के बाद बचा हुआ व्यक्ति नहीं है। वह मनुष्य के उस संघर्ष का प्रतीक है जिसमें वह विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीने का कारण तलाशता है। दुनिया चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी उम्मीद, अनुकूलन क्षमता और आगे बढ़ने की इच्छा है। और शायद उस सुनसान दुनिया में अकेला बचा व्यक्ति सबसे पहले यही समझेगा कि मनुष्य को केवल जीवित रहने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं होती, बल्कि **जीने के लिए दूसरे इंसानों की जरूरत होती है।

-शिवांश धाकड़

हम करें नयनाभिराम

भीम बसेड़ू राजपूत
महादेव (मंडी)

नयन देखते, बोलते, परखते हैं,
बिन शब्दों के मन की भाषा समझते हैं।
आंखों की हर हलचल में भाव छिपे होते हैं,
कभी खुशी, कभी दर्द, कभी ख्वाब दिखते हैं।
शब्दों की जरूरत पड़ती नहीं हर बार,
नयन कह देते हैं दिल की हर बात हजार।
इनकी चमक में उम्मीदों के रंग मिलते हैं,
इनकी नमी में मन के दर्द खिलते हैं।
जो बात जुबां कहने से रह जाती है,
वही आंखों से चुपके निकल जाती है।
नयन ही तो हैं मन का सच्चा आईना,
इनसे कुछ भी मुश्किल नहीं है छिपाना।
प्यार हो तो इनकी चमक बता देती है,
दर्द हो तो इनकी नमी जता देती है।
गुस्सा, अपनापन, शिकायत और एहसास,
सब पढ़े जा सकते हैं
इनकी भाषा के पास।
आंखों में आंखें डालकर जो मिलती है नजर,
वह बना देती है अनजान को भी अपना हमसफर।
कभी पलकों की झुकन शर्म का संदेश देती है,
कभी उठती नजर प्रेम की आवाज देती है।
नयन रंग-बिरंगी दुनिया को देखते हैं,
और भावों के अनगिनत दीप जलाते हैं।
आओ नयनों की भाषा को समझें आज,
बिन शब्दों के कर लें दिल से दिल की बात।
नयनाभिराम हो हर पल,
हर मुलाकात,
और आंखों-आंखों में होती रहे मन की बात।

हिमाचल में कृषि-बागवानी से भंग होता मोह, संभावनाओं का सृजन जरूरी





विक्रम वर्मा

हिमाचल प्रदेश में आजकल एक गंभीर चुनौती हमारे सामने खड़ी है-ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का तेजी से औद्योगिक क्षेत्रों और महानगरों की ओर पलायन। रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और आधुनिक जीवन की तलाश में गांवों से युवा लगातार शहरों की ओर जा रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रत्येक युवा अपने बेहतर भविष्य का सपना देखता है, किंतु इस पलायन का दूसरा पक्ष अत्यंत चिंताजनक है।

गांवों में खेती और बागवानी करने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप हजारों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि आज बंजर होती जा रही है। जिन खेतों में कभी धान, मक्का, गेहूं और सब्जियां लहलहाती थीं, जहां फलों के बाग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते थे, वहां आज झाड़ियां और वीरानी दिखाई देने लगी हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में हिमाचल की कृषि और बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। केवल भूमि का बंजर होना ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि इससे खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी।

समय की मांग है कि सरकार, कृषि और बागवानी विभाग मिलकर व्यापक और व्यवहारिक रणनीति तैयार करें। किसानों और विशेष रूप से युवाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों, आधुनिक मशीनों, गुणवत्तायुक्त एवं उन्नत बीजों, उच्च गुणवत्ता वाले पौधों तथा वैज्ञानिक खेती की जानकारी बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जाए। केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना भी आवश्यक है।

कृषि और बागवानी को लाभकारी एवं सम्मानजनक व्यवसाय बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शन खेत, मोबाइल तकनीकी दल, डिजिटल सलाह, प्रसंस्करण इकाइयां, शीत भंडारण, बेहतर विपणन व्यवस्था और उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। यदि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच को स्थानीय अनुभव के साथ जोड़ा जाए, तो हिमाचल का युवा खेती और बागवानी को भी एक सफल उद्यम के रूप में अपना सकता है। आज आवश्यकता स्मार्ट खेती और वैज्ञानिक बागवानी की है। जब युवाओं को यह विश्वास होगा कि आधुनिक कृषि से सम्मानजनक आय, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य प्राप्त किया जा सकता है, तब पलायन की गति स्वत: कम होगी।

रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में युवाओं का गांवों से पलायन बढ़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हिमाचल की कृषि और बागवानी पर पड़ रहा है। खेत खाली हो रहे हैं और उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे बंजर बनती जा रही है। बढ़ती खेती लागत, अनिश्चित बाजार, जलवायु परिवर्तन, जंगली जानवरों से फसलों की क्षति तथा आधुनिक तकनीकों की कमी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, सिंचाई, यंत्रीकरण, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, शीत भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। साथ ही कृषि और बागवानी को शिक्षा, तकनीक और उद्यमिता से जोड़कर युवाओं को स्टार्टअप तथा मूल्य संवर्धन के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। हिमाचल की उपजाऊ भूमि केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

स्वस्थ शरीर और शांत मन के लिए युवाओं को बदलनी होगी देर रात जागने की आदत

तकनीक के इस युग में युवा वर्ग तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ उसकी जीवनशैली में भी बड़े बदलाव आए हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वेब सीरीज और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना एक सामान्य आदत बनती जा रही है। शुरुआत में यह केवल मनोरंजन या सुविधा की आदत लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह युवाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन रही है।

मानव शरीर एक निश्चित जैविक घड़ी के अनुसार संचालित होता है, जिसे शरीर की आंतरिक घड़ी भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से दिन और रात के चक्र के साथ तालमेल बनाकर शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। समय पर सोना और जागना शरीर के हार्मोन संतुलन, पाचन तंत्र, मस्तिष्क की कार्यक्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विपरीत देर रात तक जागने की आदत इस प्राकृतिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।

चिकित्सकों के अनुसार लंबे समय तक नींद की कमी या अनियमित नींद लेने वाले युवाओं में तनाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, याददाश्त कमजोर होना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पर्याप्त नींद न मिलने से मस्तिष्क को आवश्यक आराम नहीं मिल पाता, जिसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नौकरीपेशा युवाओं की कार्यक्षमता पर पड़ सकता है। लगातार थकान रहने से व्यक्ति की उत्पादकता और निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है।

देर रात तक मोबाइल या अन्य स्क्रीन देखने की आदत इस समस्या को और बढ़ा देती है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर में नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के निर्माण को प्रभावित कर सकती है। इससे नींद आने में देरी होती है और व्यक्ति देर तक जागने के चक्र में फंसता चला जाता है। यह आदत लंबे समय तक बनी रहे तो मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता जैसी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का जोखिम बढ़ सकता है।





केशव शर्मा 'रसिक'
स्वतंत्र लेखक

बदलती जीवनशैली का सामाजिक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। देर से उठने वाले युवा अक्सर सुबह की सकारात्मक शुरुआत से वंचित रह जाते हैं। नाश्ता छोड़ना, व्यायाम से दूरी बनाना, परिवार के साथ कम समय बिताना और दिनभर थकान महसूस करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। इससे समय प्रबंधन, अनुशासन और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीरता भी प्रभावित हो सकती है। आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बीच स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखना इसलिए और अधिक जरूरी हो गया है।

शिक्षण संस्थानों में भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कई विद्यार्थी कक्षाओं में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। उनकी सीखने की क्षमता प्रभावित होती है और परीक्षा परिणामों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह नौकरी करने वाले युवाओं में थकान, कम उत्पादकता और काम के प्रति उत्साह में कमी देखी जा सकती है। इसलिए नींद को केवल आराम का विषय न मानकर स्वास्थ्य और कार्यक्षमता का महत्वपूर्ण आधार समझना होगा।

इस समस्या से निपटने के लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। माता-पिता को बच्चों के स्क्रीन समय पर संतुलित निगरानी रखनी चाहिए और स्वयं भी स्वस्थ जीवनशैली का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यालयों और महाविद्यालयों में नींद, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल संतुलन के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। युवाओं को भी यह समझना होगा कि लगातार ऑनलाइन रहना सफलता की गारंटी नहीं है।

स्वस्थ जीवन के लिए नियमित समय पर सोना और जागना आवश्यक है। सोने से पहले मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाना, नियमित व्यायाम करना, संतुलित भोजन लेना और दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखना उपयोगी हो सकता है। पर्याप्त नींद शरीर और मस्तिष्क को पुन: सक्रिय करने का अवसर देती है। युवाओं को अपनी प्राथमिकताओं में नींद को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना पढ़ाई, नौकरी या मनोरंजन को देते हैं।

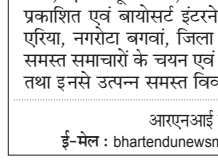
सफलता केवल देर रात तक जागकर काम करने से नहीं मिलती। स्वस्थ शरीर और शांत मन ही लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता देते हैं। इसलिए युवाओं को अपनी जीवनशैली में आवश्यक बदलाव करते हुए समय पर सोने और समय पर जागने की आदत विकसित करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए 'जल्दी सोएं, जल्दी जागें' की पुरानी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आधुनिक तकनीक का उपयोग आवश्यक है, लेकिन उसका संतुलित उपयोग ही जीवन को बेहतर बना सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

व्यक्तित्व विशेष

टीवी से फिल्मों तक श्रद्धा निगम

श्रद्धा निगम भारतीय मनोरंजन जगत की जानी-पहचानी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने टेलीविजन और फिल्मों में अपने अभिनय से पहचान बनाई। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1979 को भारत में हुआ था। अभिनय के क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने विभिन्न टेलीविजन धारावाहिकों और फिल्मों में काम किया तथा अपने सहज अभिनय और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। उनका करियर ऐसे दौर में आगे बढ़ा, जब हिंदी मनोरंजन उद्योग में टेलीविजन धारावाहिकों का तेजी से विस्तार हो रहा था और छोटे पर्दे के कलाकारों को व्यापक लोकप्रियता मिलने लगी थी।



श्रद्धा निगम
जन्म : 1 अक्टूबर 1979

श्रद्धा निगम ने अपने अभिनय करियर में अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं। वर्ष 1995 में वह 'मनो या न मानो' से जुड़ीं, जो रहस्यमय और असामान्य घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम था। इसके बाद उन्होंने फिल्मों की ओर भी रुख किया। वर्ष 2000 में प्रदर्शित फिल्म 'आगाज' में उन्होंने अभिनय किया। इसी वर्ष वह फिल्म 'जोश' में भी नजर आईं। इन फिल्मों में काम करने के साथ उन्होंने हिंदी मनोरंजन जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

श्रद्धा निगम का नाम टेलीविजन की दुनिया से भी जुड़ा रहा है। अभिनय के अलावा वह मनोरंजन उद्योग की बदलती कार्यशैली और रचनात्मक वातावरण का हिस्सा रही हैं। उनके करियर की शुरुआत उस समय हुई, जब कलाकारों के लिए टेलीविजन एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभर रहा था। टेलीविजन ने कई कलाकारों को घर-घर पहचान दिलाई और श्रद्धा निगम भी इस बदलाव का हिस्सा रहीं। उन्होंने अपने करियर में विभिन्न भूमिकाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंच बनाई।

उनका निजी जीवन भी कई बार चर्चा में रहा। श्रद्धा निगम ने अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से विवाह किया था, हालांकि यह विवाह लंबे समय तक नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। इसके बाद जनवरी 2013 में उन्होंने अभिनेता और कलाकार मयंक आनंद से विवाह किया। मयंक आनंद भी मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े रहे हैं।

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

यूपी टी-20 का पांचवां सत्र लखनऊ और वाराणसी में कराने की तैयारी

संजय कपूर और संजीव सिंह फिर यूपी टी-20 गवर्निंग काउंसिल में

एजेंसी, कानपुर



उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की वार्षिक आमसभा बुधवार को होटल लैंडमार्क में हुई। बैठक में प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें यूपी टी-20 गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के नाम भी तय किए गए। संजय कपूर और संजीव सिंह को एक बार फिर गवर्निंग काउंसिल में चुना गया। वहीं, वार्षिक आमसभा में घोषित की जाने वाली सभी अन्य कमेटियों को फिलहाल होल्ड कर दिया गया है। इन कमेटियों के गठन और घोषणा को लेकर बाद में निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रदेश में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे और आने वाले समय में बड़े मुकाबलों के आयोजन को लेकर जानकारी साझा की। राजीव शुक्ला ने बताया कि वाराणसी में तैयार हो रहे नए क्रिकेट स्टेडियम की शुरुआत महिला प्रीमियर लीग के मुकाबले से कराने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए रूपरेखा तैयार की गई है। स्टेडियम के तैयार होने के बाद यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मुकाबलों के आयोजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।

उन्होंने कहा कि कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश की क्रिकेट विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे नए स्वरूप में तैयार करने की योजना है, जिससे स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा सके। ग्रीन पार्क में लंबे समय से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुकाबले आयोजित होते रहे हैं। ऐसे में इसके पुराने गौरव और आधुनिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाते हुए इसे विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

राजीव शुक्ला ने यह भी बताया कि यूपी टी-20 लीग के पांचवें सत्र को लेकर भी प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। लीग के मुकाबले लखनऊ के साथ वाराणसी के नए स्टेडियम में कराने की योजना है। इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में क्रिकेट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में नए स्टेडियम के शुरू होने से पूर्वांचल के खिलाड़ियों को भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकेगा।

वाराणसी में नए स्टेडियम में होंगे मैच

राजीव शुक्ला ने यह भी बताया कि यूपी टी-20 लीग के पांचवें सत्र को लेकर भी प्रारंभिक रूपरेखा तैयार कर ली गई है। लीग के मुकाबले लखनऊ के साथ वाराणसी के नए स्टेडियम में कराने की योजना है। इससे प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में क्रिकेट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वाराणसी में नए स्टेडियम के शुरू होने से पूर्वांचल के खिलाड़ियों को भी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकेगा। वार्षिक आमसभा में गवर्निंग काउंसिल के गठन के साथ ही यूपीसीए की आगामी क्रिकेट गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। हालांकि अन्य कमेटियों के नाम फिलहाल घोषित नहीं किए गए। इन्हें होल्ड किए जाने के कारण एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों और सदस्यों की निगाहें अब अगली घोषणा पर टिकी हैं।

फर्रुखाबाद में 38वें मानस सम्मेलन का शुभारंभ

रामचरित मानस के आदर्शों को जीवन में उतारने का संतों ने किया आह्वान

एजेंसी, फर्रुखाबाद



पंडाबाग रेलवे रोड स्थित महाभारत कालीन मंदिर श्री पाण्डेश्वर नाथ के सत्संग भवन में बुधवार को मानस विचार समिति के तत्वावधान में 38वें मानस सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ हुआ। धार्मिक वातावरण में आयोजित सम्मेलन की शुरुआत सूर्य पूजन से की गई। इसके बाद श्री गणेश, श्रीराम दरबार, श्री हनुमान जी और मानस ग्रंथ का विधिवत पूजन-अर्चन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर देवी-देवताओं की आरती की और प्रसाद ग्रहण किया।

मुख्य यजमान प्रधानाचार्य डॉ. होम सिंह ने अपनी पत्नी मालती देवी के साथ पं. रामेन्द्र नाथ मिश्रा, डॉ. रामबाबू पाठक और पं. विशेष पाठक के सानिध्य में पूजन-अर्चन संपन्न कराया। इस दौरान संत शिरोमणि स्वामी लक्ष्मीनारायण सरस्वती, स्वामी श्यामानन्द सरस्वती, रामरथ सरस्वती, अवधेशानंद सरस्वती, कमलानंद सरस्वती और स्वामी सम्पूर्णानंद सरस्वती ने सम्मेलन में पहुंचे संतों और श्रद्धालुओं का स्वागत किया।

मानस विद्वान डॉ. रामबाबू पाठक ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरित मानस केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन को सही दिशा देने वाला महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। इसमें धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष के महत्व को समझाया गया है। उन्होंने कहा कि रामायण और रामराज्य की अवधारणा धर्म और लोककल्याण के आधार पर स्थापित है। सम्मेलन का उद्देश्य समाज में सुख, शांति, सद्भाव और मंगल की भावना को मजबूत करना है।

संत शिरोमणि स्वामी लक्ष्मीनारायण सरस्वती ने कहा कि श्रीरामचरित मानस परिवार, समाज और राष्ट्र में व्यक्ति के चरित्र निर्माण का मार्ग दिखाता है। जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियों में भी मानस मनुष्य को धैर्य, संयम और सही आचरण की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि केवल मानस का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है। इसके आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना भी आवश्यक है। परिवार और समाज में प्रेम, सम्मान, मर्यादा तथा सेवा की भावना को बढ़ाने में मानस की शिक्षाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

मानस सम्मेलन में उमड़े श्रद्धालु, हुई आरती और प्रसाद वितरण

कार्यक्रम में सुरजीत पाठक, अपूर्व पाठक, नरेश दुबे, अखिलेश शुक्ला, ज्योति स्वरूप अग्निहोत्री, बृजेन्द्र श्रीमाली, अशोक शुक्ल, सदानंद शुक्ल, अद्भुत और अभिषेक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने मानस ग्रंथ और देवी-देवताओं की आरती की। इसके बाद प्रसाद का वितरण किया गया। सम्मेलन के संयोजक ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रमों में समय से पहुंचकर संतों के प्रवचन और मानस पाठ का लाभ लें। सम्मेलन के कार्यक्रम सायंकाल चार बजे से रात नौ बजे तक आयोजित किए जाएंगे।

दिव्या मित्तल की नई राजनीतिक पारी के ऐलान से हलचल

दिव्या मित्तल की सियासी पारी से यूपी की राजनीति में हलचल



एजेंसी, वाराणसी

मीरजापुर की पूर्व जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के राजनीति में कदम रखने की चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगी या किसी मौजूदा दल का दामन थामेंगी, लेकिन ताजा घटनाक्रम ने उनकी राजनीतिक सक्रियता को लेकर चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है। जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव डा. बृजेश सिंह राजावत के एक्स हैंडल से जारी एक पोस्टर में दिव्या मित्तल को राजा भैया के साथ दिखाया गया है। पोस्टर सामने आने के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

◆ दिव्या मित्तल के राजनीतिक कदम पर बढ़ी चर्चा

जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव के एक्स हैंडल से जारी पोस्ट में दिव्या मित्तल के राजनीति में आने का स्वागत किया गया है। पोस्ट में लिखा गया है कि क्या उत्तर प्रदेश में राजनीति का नया अध्याय शुरू होगा। इसमें कहा गया कि पूर्व आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने नई राजनीतिक पारी शुरू करने की घोषणा की है। पोस्ट के माध्यम से उन्हें राजनीति के क्षेत्र में स्वागत भी किया गया है। साथ ही दिव्या मित्तल के प्रशासनिक अनुभव और राजा भैया की जमीनी राजनीतिक पकड़ को जोड़ते हुए प्रदेश की राजनीति में नई दिशा की संभावना का संकेत दिया गया है।

दिव्या मित्तल प्रशासनिक सेवा के दौरान अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रही हैं। मीरजापुर की जिलाधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल को लेकर भी विभिन्न अवसरों पर चर्चा होती रही है।

राजाभैया की पार्टी से जुड़ेंगी दिव्या मित्तल?

पोस्टर में राजा भैया के साथ उनकी तस्वीर और जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी की ओर से किए गए पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि दिव्या मित्तल आगे किस राजनीतिक मंच से अपनी पारी शुरू करेंगी। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर अलग-अलग चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल उनके अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि वह किसी दल के साथ जुड़ती हैं या अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा करती हैं तो प्रदेश की राजनीति में उनके प्रशासनिक अनुभव को लेकर भी चर्चा होना स्वाभाविक है।

सपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए रामगोपाल और नाथवानी को उतारा

अखिलेश यादव समेत सपा नेताओं की मौजूदगी में रामगोपाल यादव और धनराज नाथवानी ने दाखिल किए नामांकन

एजेंसी, लखनऊ



उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को अपने दो प्रत्याशियों के नामांकन के साथ चुनावी प्रक्रिया में औपचारिक रूप से कदम आगे बढ़ाया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रो. रामगोपाल यादव तथा धनराज परिमल नाथवानी ने निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन के दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव के साथ सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव, विधायक रविदास मेहरोत्रा, ओपी सिंह और अतुल प्रधान समेत कई नेताओं ने प्रत्याशियों का समर्थन किया। दोनों उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत नामांकन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा विधायकों की मौजूदगी से पार्टी के भीतर चुनाव को लेकर सक्रियता भी दिखाई दी।

प्रो. रामगोपाल यादव सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी के वरिष्ठ संसदीय चेहरों में शामिल हैं। वह लंबे समय से राज्यसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। सपा ने उन्हें एक बार फिर उच्च सदन के लिए प्रत्याशी बनाया है। वहीं धनराज परिमल नाथवानी उद्योग और खेल प्रशासन से जुड़े रहे हैं। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सपा द्वारा दोनों नामों की घोषणा के बाद राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है।

उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान प्रस्तावित है। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख छह अक्टूबर निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होगी और इसके बाद मतदान कराया जाएगा। मौजूदा विधानसभा संख्या बल के आधार पर राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 प्रथम वरीयता मतों की आवश्यकता होगी। ऐसे में सभी प्रमुख दल अपने-अपने विधायकों के समर्थन और संख्या बल के आधार पर चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं।

सपा ने बुधवार को फिलहाल दो प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी की ओर से तीसरे प्रत्याशी के नाम को लेकर अभी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सपा के पास विधानसभा में उपलब्ध संख्या बल को देखते हुए तीसरे उम्मीदवार को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चा बनी हुई है। हालांकि पार्टी की ओर से इस संबंध में अंतिम निर्णय की घोषणा अभी नहीं की गई है। नामांकन के बाद अब चुनावी समीकरण और विधायकों के समर्थन को लेकर गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। राज्यसभा चुनाव में मतदान और परिणाम के बीच राजनीतिक दलों की रणनीति, प्रत्याशियों की स्थिति तथा विधानसभा में दलों के संख्या बल की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।

बच्चों का वीडियो वायरल होते ही 10 घंटे में रोशन हुआ गांव

कौशांबी में बच्चों की अपील रंग लाई, डीएम के निर्देश पर गांव में पहुंची रोशनी

एजेंसी, कौशांबी



डीएम तक पहुंची आवाज और रोशन हुआ गांव।

उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में तीन मासूम बच्चों की छोटी-सी पहल ने प्रशासन को तत्काल कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। मंझनपुर तहसील क्षेत्र के चक अहमदीपुर गांव में शाम होते ही गलियों में अंधेरा छा जाने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। गांव के तीन बच्चों ने अपनी समस्या को लेकर एक वीडियो तैयार किया और जिलाधिकारी से गांव में बिजली के खंभों पर रोशनी की व्यवस्था कराने की अपील की। बच्चों ने वीडियो में बताया कि शाम के बाद गांव की गलियां पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती हैं। आसपास खेत होने के कारण जंगली जानवरों का डर भी बना रहता है।

ऐसे में जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी होती है। बच्चों की यह अपील सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन तक पहुंची और जिलाधिकारी अमित पाल शर्मा ने मामले का तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने के निर्देश दिए। इसके बाद बिजली विभाग की टीम सक्रिय हुई और मंगलवार देर रात चक अहमदीपुर गांव पहुंचकर लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि बच्चों का वीडियो सामने आने के करीब 10 घंटे के भीतर ही गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई।

कई स्थानों पर रात में ही लाइटें लगा दी गईं, जिससे गांव की गलियों में रोशनी हो गई। अंधेरे से परेशान ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। गांव में रोशनी होने के बाद बच्चों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर खुशी जताई और जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। बच्चों का कहना था कि उन्होंने अपनी समस्या प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया था और अधिकारियों ने उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए तुरंत समाधान कराया। सूचना अधिकारी रवि जायसवाल ने बताया कि बच्चों की ओर से तैयार वीडियो प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निर्देश मिलते ही विभागीय टीम को गांव भेजा गया और स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य शुरू कराया गया। ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से गांव की गलियों में पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। बच्चों ने अपनी बात जिस सरल तरीके से प्रशासन तक पहुंचाई, उससे समस्या का समाधान भी तेजी से हो गया। प्रशासन की इस कार्रवाई की सोशल मीडिया पर भी चर्चा हुई।

गरबा नाइट पर रोक की मांग, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन

सामूहिक गरबा आयोजन पर रोक की मांग को लेकर फर्रुखाबाद में हिंदू संगठनों ने उठाई आवाज

एजेंसी, फर्रुखाबाद



फर्रुखाबाद में सामूहिक गरबा नाइट कार्यक्रम के आयोजन को लेकर बुधवार को हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार को सौंपा। ज्ञापन में आयोजकों की ओर से आयोजित किए जाने वाले सामूहिक डांडिया और गरबा कार्यक्रम को लेकर कई आपत्तियां जताई गईं। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ऐसे आयोजनों में धार्मिक भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता और कार्यक्रमों की आड़ में युवतियों की तस्वीरें लेने तथा व्यक्तिगत जानकारी हासिल करने जैसी गतिविधियां हो सकती हैं। उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति पर पुनर्विचार करने और आयोजन पर रोक लगाने की मांग की।

बजरंग दल के जिला सह संयोजक रोहन मिश्रा ने कहा कि गरबा और डांडिया धार्मिक परंपराओं से जुड़े आयोजन हैं और इनके स्वरूप की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ आयोजक धार्मिक भावनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में टिकट के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना था कि प्रशासन को ऐसे आयोजनों की अनुमति देने से पहले सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री अनुज श्रीवास्तव ने भी कार्यक्रम में बाहरी लोगों की भागीदारी को लेकर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि कार्यक्रमों के दौरान युवतियों की तस्वीरें लेने और मोबाइल नंबर हासिल करने जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जिन्हें लेकर संगठन चिंतित हैं।

गरबा कार्यक्रम में नियमों के पालन की मांग

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांग किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि धार्मिक आयोजनों की मर्यादा और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। उन्होंने प्रशासन से कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की पहचान और आयोजन की व्यवस्थाओं की जांच कराने की मांग भी की। संगठनों का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रमों में महिलाओं की सुरक्षा और उनकी निजता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। साथ ही आयोजकों को भी कार्यक्रम के दौरान निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

अगले छह दिन यूपी में बारिश की संभावना कम

उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई करीब, रात में बढ़ेगी हल्की ठंडक

एजेंसी, लखनऊ



उत्तर प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राज्य के शेष हिस्सों से अगले दो से तीन दिनों के दौरान मानसून के पूरी तरह पीछे हटने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। फिलहाल मानसून की वापसी की रेखा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ से होकर गुजर रही है। इसके चलते राज्य में बारिश का दौर धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगा है। मौसम में बदलाव के साथ आने वाले दिनों में दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी और रात के समय ठंडक बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, 30 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां अब काफी कम हो गई हैं और आने वाले दिनों में अधिकांश इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। एक अक्टूबर से छह अक्टूबर के बीच राज्य के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना बेहद कम बताई गई है।

मानसून की विदाई के साथ उत्तर-पश्चिम भारत में किसी बड़े मानसूनी तंत्र के सक्रिय होने की संभावना भी फिलहाल नहीं है। इससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। बारिश थमने के बाद खेतों में कटाई, फसलों को सुखाने और भंडारण से जुड़े कार्य आसानी से किए जा सकेंगे। हालांकि किसानों को स्थानीय मौसम परिस्थितियों पर नजर रखने की सलाह दी जाती है।

मौसम में बदलाव का असर आम जनजीवन पर भी दिखाई देगा। दिन में धूप बढ़ने से तापमान में कुछ वृद्धि हो सकती है, जबकि रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। धीरे-धीरे मौसम में शुष्कता बढ़ने के साथ सुबह और शाम के समय तापमान में अंतर भी बढ़ सकता है। इस तरह सितंबर के अंत के साथ प्रदेश में मानसून का दौर समाप्त होने और मौसम के अगले चरण में प्रवेश करने की स्थिति बन रही है।

निर्माण धोबीनिया नाला के जर्जर पुल की जगह नया सेतु बनाने की तैयारी, मांगा गया आगणन

तुलसीपुर-बहराइच मार्ग पर 55 करोड़ से बनेगा नया पुल

एजेंसी, बलरामपुर



धोबीनिया नाला पर नए दीर्घ सेतु का प्रस्ताव।

तुलसीपुर-बहराइच सिरसिया मार्ग पर धोबीनिया नाला के जर्जर पुल की जगह अब नया दीर्घ सेतु बनाया जाएगा। वर्षों पुराना यह पुल वर्तमान में जर्जर हालत में होने के बावजूद आवागमन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पुल की स्थिति को देखते हुए तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने शासन को पत्र भेजकर नए पुल के निर्माण की मांग की थी। शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नए पुल के निर्माण के लिए सर्वे कर आगणन रिपोर्ट मांगी है। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (सेतु) रवींद्र सिंह ने 26 सितंबर को संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर जर्जर सेतु का आगणन तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। नए पुल के निर्माण पर करीब 55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

धोबीनिया नाला पर स्थित यह पुल तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र में बहराइच-सिरसिया-तुलसीपुर-गुलरिहा राज्य मार्ग-158 के किलोमीटर 46 पर है। यह मार्ग बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के साथ नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। नए पुल के बनने से इन जिलों के अलावा सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं तथा नेपाल से भारत और भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा सिद्धार्थनगर और नेपाल क्षेत्र से श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर जाने वाले लोगों के लिए भी यह मार्ग सीधा और सुविधाजनक है। इससे लोगों को बलरामपुर होकर लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा।

तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने बताया कि धोबीनिया नाला पहाड़ी नाला है और इसमें अचानक पानी आने के कारण बहाव कई बार तेज हो जाता है। ऐसे में पुराने पुल पर आवागमन को लेकर लगातार चिंता बनी रहती है। पुल अधिक क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में मार्ग बंद करना पड़ सकता है, जिससे दोनों जिलों के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों के लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए जर्जर पुल के समानांतर नया दीर्घ सेतु बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। विधायक ने बताया कि शासन ने प्रस्ताव पर सकारात्मक पहल करते हुए संबंधित विभाग से तत्काल आगणन रिपोर्ट मांगी है।

आवाजाही और धार्मिक पर्यटन को मिलेगा लाभ

जल्द ही विभागीय टीम मौके पर पहुंचकर पुल और आसपास के क्षेत्र का सर्वे करेगी। सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजे जाने के बाद निर्माण के लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। नया पुल बनने से क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था मजबूत होने के साथ व्यापार, आवागमन और धार्मिक पर्यटन को भी सुविधा मिलने की उम्मीद है। नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग का रणनीतिक और स्थानीय महत्व भी है। समय रहते नए पुल का निर्माण होने से भविष्य में जर्जर सेतु के कारण आवागमन बाधित होने की आशंका को कम किया जा सकेगा।

प्रगति योजना में शामिल हुए हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल शहर

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल को केंद्र सरकार की प्रगति योजना से जुड़ी 50 शहरों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में तीनों शहरों के नगर निकायों को भी दर्ज किया गया है। फरीदाबाद नगर निगम, गुरुग्राम नगर निगम और करनाल नगर निगम इसके दायरे में रहेंगे।

प्रगति यानी प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय तथा महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी का तंत्र है। इसके तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। इसका उद्देश्य योजनाओं को तय समय में पूरा कराना और उनके जमीनी स्तर पर परिणाम सुनिश्चित करना है।

शहरों को इस व्यवस्था से जोड़ने के बाद नगर निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन, कचरा प्रसंस्करण, स्वच्छता, हरियाली और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को इन व्यवस्थाओं को मिशन मोड में आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

मई 2026 की प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं और कचरा प्रसंस्करण संयंत्रों को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया था। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों की नियमित समीक्षा पर भी बल दिया गया था।

फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल के लिए इसका प्रभाव शहरों की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं की निगरानी में दिखाई दे सकता है। कचरे के संग्रह और निस्तारण, सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई, सड़क व फुटपाथ व्यवस्था, हरित क्षेत्रों के विकास और नागरिक सेवाओं की निगरानी जैसे कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर रहेगा।

हरियाणा में असुरक्षित भवनों पर सरकार सख्त

35 वर्ष पुराने भवन में मिलीं सुरक्षा खामियां, जांच पूरी होने तक विद्यार्थियों के रहने पर रोक

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

देश-प्रदेश में लगातार सामने आ रही भवन गिरने और आगजनी की घटनाओं के बाद हरियाणा सरकार ने भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है। पुराने, प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर चुके और अग्नि सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरने वाले भवनों को विशेष रूप से जांच के दायरे में लिया जा रहा है। सरकार ने भवनों का सुरक्षा और अग्निशमन ऑडिट शुरू किया है।

इस अभियान के तहत पहली बड़ी कार्रवाई अंबाला के चमन वाटिका स्कूल में हुई है। चंडीगढ़-अंबाला हाईवे स्थित स्कूल परिसर में बने छात्रावासों में फिलहाल विद्यार्थियों के रहने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अग्निशमन विभाग के निरीक्षण में सामने आया कि परिसर में अग्निशमन की बुनियादी सुविधाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पर्याप्त नहीं हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि



जब तक प्रदेश सरकार के निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन नहीं किया जाता, तब तक छात्रावासों में विद्यार्थियों को रहने की अनुमति नहीं होगी।

चमन वाटिका स्कूल का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्कूल का करीब 35 वर्ष पुराना भवन तीन बार बाढ़ का सामना कर चुका है। भवन की स्थिति और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए यहां छात्राओं के लिए संचालित आवासीय गुरुकुल को मार्च 2026 में बंद कर दिया गया था।

अंबाला के अग्निशमन अधिकारी की ओर से जारी पत्र के अनुसार स्कूल प्रबंधन के पास उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्र केवल 374.86 वर्ग मीटर के भू-आवरण क्षेत्र के लिए है। निरीक्षण के दौरान परिसर का वास्तविक क्षेत्र इससे काफी अधिक पाया गया। परिसर के तीन छात्रावास खंड, भोजनालय और स्विमिंग पूल क्षेत्र मौजूदा अग्निशमन सुरक्षा प्रमाणपत्र के दायरे में नहीं आते।

विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नया संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा छात्रावास और स्कूल भवनों के सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नक्शे भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

जोखिम वाले भवनों पर नजर

सरकार की ओर से शुरू किए गए सुरक्षा ऑडिट में ऐसे भवनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जो पुराने हैं, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं अथवा जिनकी संरचनात्मक मजबूती को लेकर सवाल हैं। स्कूलों, छात्रावासों और अन्य सार्वजनिक भवनों की अग्निरोधी व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। हाल में दिल्ली, अंबाला और देश के अन्य हिस्सों में भवन गिरने तथा आग लगने की घटनाओं के बाद सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है।

भर्ती के बीच नहीं बदल सकते नियम, साक्षात्कार में न्यूनतम अंक न होने पर राहत : हाई कोर्ट

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़



पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि भर्ती विज्ञापन में साक्षात्कार के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं तो चयन समिति केवल साक्षात्कार के आधार पर किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित नहीं कर सकती। चयन समिति को विज्ञापन में पहले से निर्धारित सभी मानकों और उनके लिए तय अंकों के आधार पर उम्मीदवार की योग्यता का आकलन करना होगा।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय, भिवानी में सहायक पद की भर्ती से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान ऐसा अयोग्यता मानदंड लागू करना, जिसका उल्लेख विज्ञापन में नहीं था, चयन प्रक्रिया के नियमों को बीच में बदलने के समान है। ऐसा करना भर्ती प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा।

मामला सहायक के आठ पदों की भर्ती का था। इनमें एक पद बीसी-बी श्रेणी के लिए आरक्षित था। याचिकाकर्ता ने इसी पद के लिए आवेदन किया था। विश्वविद्यालय की ओर से जारी विज्ञापन में चयन प्रक्रिया के लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए थे। इनमें कंप्यूटर टाइपिंग के 35, सामान्य योग्यता परीक्षा के 30, शैक्षणिक योग्यता के 10, कार्य अनुभव के पांच, विषय ज्ञान के आठ और साक्षात्कार के 12 अंक रखे गए थे।

विज्ञापन के अनुसार पहले चार मानकों के आधार पर मेरिट तैयार कर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना था। याचिकाकर्ता स्नातक था और उसके पास आवश्यक पांच वर्ष के अनुभव के मुकाबले 10 वर्ष का कार्य अनुभव था। उसने पहले चार मानकों में 35.55 अंक हासिल किए और बीसी-बी श्रेणी में स्वयं को सर्वाधिक मेरिट वाला उम्मीदवार बताया।

हालांकि, चयन के दौरान याचिकाकर्ता को विषय ज्ञान और साक्षात्कार दोनों में शून्य अंक दिए गए और उसे 'योग्य नहीं पाया गया' घोषित कर दिया गया। खास बात यह थी कि चयन प्रक्रिया के बाद किसी भी उम्मीदवार की नियुक्ति के लिए सिफारिश नहीं की गई और पद खाली रह गया।

हाई कोर्ट ने कहा कि संबंधित भर्ती प्रक्रिया न तो पूरी तरह और न ही मुख्य रूप से साक्षात्कार पर आधारित थी। कुल 100 अंकों में 80 अंक कंप्यूटर टाइपिंग, सामान्य योग्यता परीक्षा, शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के लिए निर्धारित थे। वहीं विषय ज्ञान और साक्षात्कार के लिए संयुक्त रूप से केवल 20 अंक रखे गए थे। विज्ञापन में इन दोनों चरणों में न्यूनतम अंक हासिल करना अनिवार्य नहीं किया गया था।

रेवाड़ी में दो दिन से लापता युवक का जोहड़ में मिला शव

भारतेन्दु संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के गांव बेरली कलां से दो दिन से लापता 36 वर्षीय युवक प्रवीन का शव बुधवार सुबह गांव के जोहड़ में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने जोहड़ में शव तैरता देखा और तुरंत जाटूसाना थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की सहायता से शव को बाहर निकलवाया। जानकारी के अनुसार, प्रवीन दो दिन पहले अचानक घर से लापता हो गया था। उसके घर नहीं लौटने पर परिजनों ने आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने जोहड़ में शव देखा। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बाहर निकलवाया और पहचान की प्रक्रिया पूरी की। घटनास्थल पर सीन ऑफ क्राइम टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार, मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। इसके बावजूद मौत के कारणों को लेकर पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रवीन की मौत जोहड़ में डूबने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण रहा।

फतेहाबाद में पेंशनरों का 24 घंटे का पड़ाव समाप्त, प्रदर्शन जारी

पेंशनरों ने महंगाई भत्ते का बकाया और अतिरिक्त पेंशन देने की उठाई मांग

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद



आठवें वेतन आयोग का लाभ सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर उपायुक्त कार्यालय फतेहाबाद के बाहर शुरू हुआ 24 घंटे का पड़ाव बुधवार को प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के साथ समाप्त हो गया। पड़ाव के दूसरे दिन बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारी एकत्र हुए और मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने एसडीएम को मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

रिटायर्ड कर्मचारी संघ फतेहाबाद के जिला प्रधान भोला सिंह, कोषाध्यक्ष रघुनाथ मेहता और जिला सचिव बेगराज के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में टोहाना, जाखल, भूना, भट्ठू और फतेहाबाद क्षेत्र से पेंशनर शामिल हुए। वक्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आठवें वेतन आयोग के लाभों को लेकर सरकार का रवैया पेंशनरों के हित में नहीं है।

जिला प्रधान भोला सिंह और जिला सचिव बेगराज ने कहा कि 31 दिसंबर 2025 से पहले और उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बीच अंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को लेकर अपनाई गई व्यवस्था से पेंशनभोगियों में असंतोष है।

ज्ञापन में कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा 65 वर्ष की आयु पर पांच प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत, 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत और 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन देने की मांग रखी गई।

◆ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने सरकार से लंबित भुगतान जारी करने की मांग की

पेंशनरों ने पारिवारिक पेंशनरों को एलटीसी का लाभ देने और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल व हवाई यात्रा में पहले की तरह रियायत बहाल करने की मांग भी उठाई। संघ नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जिलेभर में सदस्यता अभियान चलाकर और संघर्ष कोष जुटाकर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।

नर्सिंग ऑफिसर्स ने मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति के विरोध में खोला मोर्चा

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम



हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू किए जाने के विरोध में प्रदेशभर के नर्सिंग कैडर ने बुधवार से शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू कर दिया। गुरुग्राम सहित प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सिंग ऑफिसर्स ने काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी की। नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले शुरू किए गए आंदोलन में कर्मचारियों ने पॉलिसी वापस लेने की मांग की।

गुरुग्राम के सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल सहित जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में नर्सिंग स्टाफ ने विरोध जताया। एसोसिएशन के अनुसार आंदोलन के पहले चरण में 30 सितंबर और एक अक्टूबर को नर्सिंग कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। इसके बाद पांच, छह और सात अक्टूबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रखने की बात कही गई है।

एसोसिएशन ने कहा कि नर्सिंग कैडर में करीब 95 प्रतिशत महिलाएं हैं और कर्मचारी 24 घंटे तीन पालियों में ड्यूटी करते हैं। संगठन का कहना है कि ऑनलाइन स्थानांतरण की व्यवस्था के कारण महिला कर्मचारियों को परिवार से दूर सैकड़ों किलोमीटर स्थानांतरित किए जाने की स्थिति बन सकती है। इससे बच्चों, बुजुर्गों और परिवार की जिम्मेदारियों को संभालने में परेशानी हो सकती है।

नर्सिंग ऑफिसर्स ने यह भी कहा कि प्रदेश के कई स्वास्थ्य संस्थान ग्रामीण और अपेक्षाकृत दूरदराज क्षेत्रों में स्थित हैं। रात की पाली में वहां पहुंचना महिला कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। संगठन ने सरकार से महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और पारिवारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि वे मरीजों की सेवा प्रभावित किए बिना चरणबद्ध तरीके से अपना विरोध जारी रखेंगे।

डेढ़ साल से ढकी प्रतिमा के अनावरण में देरी पर युवाओं ने उठाया कदम

यमुनानगर में युवाओं ने भगत सिंह की प्रतिमा से हटाया आवरण

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर



यमुनानगर शहर के शहीद भगत सिंह चौक पर करीब डेढ़ साल से कपड़े से ढकी प्रतिमा को बुधवार रात कुछ युवकों ने खुद ही खोल दिया। प्रतिमा से आवरण हटाने के बाद युवकों ने 'जय हिंद, जय भारत' के नारे लगाए। घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

युवकों का कहना है कि चौक के नवीनीकरण के बाद से प्रतिमा लंबे समय से ढकी हुई थी। उनका आरोप है कि नई प्रतिमा लगाए जाने और औपचारिक अनावरण की प्रक्रिया में देरी के कारण पुरानी प्रतिमा को ढककर रखा गया था। काफी समय बीतने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ा तो उन्होंने स्वयं प्रतिमा से कपड़ा हटा दिया।

नगर निगम ने शहीद भगत सिंह चौक के नवीनीकरण पर करीब 15.65 लाख रुपये खर्च किए हैं। परियोजना के तहत चौक पर साढ़े छह फुट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित की जानी है। वर्तमान प्रतिमा की ऊंचाई करीब पांच फुट 11 इंच बताई गई है। निर्माण कार्य की जांच में निर्धारित मानक से कम ऊंचाई की प्रतिमा लगाए जाने की बात सामने आई थी।

इसके बाद मेयर सुमन बहमनी ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर मौजूदा प्रतिमा हटाकर निर्धारित ऊंचाई की नई प्रतिमा लगाने के निर्देश दिए थे। नई प्रतिमा स्थापित करने में देरी के कारण पुरानी प्रतिमा लंबे समय तक ढकी रही।

वहीं, चौक के नवीनीकरण को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। चौक पर लगाए गए लाल बलुआ पत्थर के कुछ हिस्सों का रंग फीका पड़ने से निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठे। परियोजना के तहत करीब सात मीटर की गोल परिधि में चौक को नया स्वरूप दिया गया है। प्रतिमा के नीचे ग्रेनाइट, ऊपर पत्थर की छतरी, चारों ओर पारदर्शी शीशे और सजावटी एलईडी लाइटें लगाई गई हैं।

◆ चौक की बदहाल व्यवस्था को लेकर भी उठते रहे सवाल

न्यूज ब्रीफ

खेलों के जरिए गुरुग्राम में स्वच्छता का संदेश प्लास्टिक पर रोक

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। स्वच्छ एवं प्लास्टिक-मुक्त गुरुग्राम बनाने और बेहतर कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम गुरुग्राम और वन स्टेज एनजीओ ने संयुक्त रूप से जागरूकता पहल आयोजित की। सेक्टर-34 स्थित नगर निगम कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में खेलों और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। प्रतिभागियों को प्लास्टिक के अनावश्यक उपयोग से बचने, कचरे को अलग-अलग करने और उसका उचित निस्तारण करने के लिए प्रेरित किया गया। खेलों के माध्यम से स्वच्छता जैसे महत्वपूर्ण विषय को रोचक और सहज तरीके से लोगों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि शहर को स्वच्छ बनाए रखना केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि स्वच्छ और प्लास्टिक-मुक्त गुरुग्राम के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। जागरूकता को सहभागी गतिविधियों से जोड़ने पर स्वच्छता का संदेश अधिक प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचता है।

निशा यादव बनीं सेक्टर-14 राजकीय कन्या महाविद्यालय की बेस्ट एथलीट

भारतेन्दु संवाददाता, गुरुग्राम। राजकीय कन्या महाविद्यालय सेक्टर-14 में बुधवार को 63वीं वार्षिक एथलीट मीट का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय की छात्राओं ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्साह के साथ भाग लिया और अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तीन स्पर्धाओं में दूसरे स्थान पर रहने के बावजूद निशा यादव को प्रतियोगिता की बेस्ट एथलीट चुना गया। एथलीट मीट का शुभारंभ मुख्य अतिथि गुरुग्राम की मेयर राज रानी मल्होत्रा ने किया। कार्यक्रम प्राचार्या डॉ. इंदू राव के मार्गदर्शन और उप-प्राचार्या डॉ. सुनीता ढाका के निर्देशन में हुआ। इस अवसर पर तिलक राज मल्होत्रा, आयोजन सचिव डॉ. ज्योति सोलंकी सहित महाविद्यालय के प्राध्यापक और छात्राएं मौजूद रहीं। छात्राओं ने बैंड की धुन पर मार्च पास्ट करते हुए ध्वज को सलामी दी।

पंकज अग्रवाल पर 100 करोड़ ट्रांसफर और निजी लाभ लेने के आरोप

भारतेन्दु संवाददाता, पंचकूला। हरियाणा में सरकारी विभागों के बैंक खातों से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में आईएएस पंकज अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई के आरोपपत्र में उन पर वित्त विभाग की आपत्तियों के बावजूद बड़ी रकम बैंक खातों में स्थानांतरित कराने, नोटशीट में बदलाव करवाने और बैंक से जुड़े लोगों से कथित अनुचित लाभ लेने के आरोप लगाए गए हैं। आरोपपत्र के अनुसार जनवरी 2025 में एचएसएसपीपी के खाते से आइडीएफसी फर्स्ट बैंक के नए खाते में तीन किस्तों में कुल 100 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए गए और उसी दिन खाते से डेबिट शुरू हो गया। कृषि विपणन बोर्ड से जुड़े मामले में भी नए बैंक खाते खोलने और 10 करोड़ रुपये की कथित निकासी का उल्लेख है। सीबीआई ने आरोपपत्र में होटल बुकिंग, भुगतान रिकॉर्ड, काल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज समेत विभिन्न दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया है। आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया में होगी।

पानीपत में चिकित्सक से मांगी एक करोड़ रंगदारी

भारतेन्दु संवाददाता, पानीपत। निजी अस्पताल के संचालक चिकित्सक डॉ. संजय सैन से फोन पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया और चिकित्सक को धमकी दी कि उसकी पूरी रेकी की जा चुकी है। आरोपित ने 24 घंटे के भीतर रकम तैयार रखने को कहा। रुपये नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। जिस नंबर से फोन आया, उसकी तकनीकी जानकारी जुटाई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध जांच और साइबर टीम को भी जांच में लगाया गया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धमकी देने वाला वास्तव में किसी गिरोह से जुड़ा है या गिरोह का नाम लेकर डराने की कोशिश की गई है। पुलिस आरोपित की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।

यमुनानगर में खेत में मिला शव, सिर पर चोट के निशान

भारतेन्दु संवाददाता, यमुनानगर



यमुनानगर के छछरौली थाना क्षेत्र के जेधर गांव में बुधवार सुबह श्मशान घाट के पास खेत में करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। प्रारंभिक परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने हत्या की आशंका से जांच शुरू की है।

जानकारी के अनुसार, सुबह कुछ ग्रामीण श्मशान घाट की ओर खेतों के रास्ते टहलने निकले थे। इसी दौरान उन्हें एक खेत में सफेद कपड़ों में व्यक्ति पड़ा दिखाई दिया। पास जाकर देखने पर उसके सिर पर चोट और चेहरे पर खून के निशान मिले। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की।

फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मृतक की जेब से करीब 50 हजार रुपये मिले हैं। वहीं, जेब फटी हुई और पजामा खुला मिला है। घटनास्थल के आसपास वाहन के टायरों के निशान भी मिले हैं, जबकि पैरों के निशान स्पष्ट नहीं हैं।

छछरौली थाना प्रभारी वेदपाल ने बताया कि सिर पर चोट के निशान मिले हैं और हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतक की पहचान के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

आशियाना | प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन किस्तों में ढाई लाख रुपए की मिलेगी सहायता

कैथल में 593 परिवारों के पक्के घर का सपना होगा साकार

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल



अपने पक्के आशियाने का सपना देख रहे परिवारों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत कैथल जिले के 593 लाभार्थियों को जल्द ही घर निर्माण के लिए पहली किस्त जारी की जाएगी। इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है। नगर परिषद और नगर पालिकाओं की ओर से लाभार्थियों से संबंधित प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

योजना के तहत पात्र परिवारों को नया मकान बनाने के लिए तीन किस्तों में कुल ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहली किस्त एक लाख, दूसरी किस्त एक लाख और तीसरी किस्त 50 हजार रुपये की होगी। इस बार मकान की मरम्मत को योजना में शामिल नहीं किया गया है। केवल नया घर बनाने के लिए पात्र लाभार्थियों को सहायता दी जाएगी।

जिले के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत कुल 7776 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें नगर परिषद कैथल क्षेत्र से 1993 आवेदन आए हैं। निकायवार मंजूर हुए लाभार्थियों में नगर परिषद कैथल के 150, नगर पालिका चीका के 145, कलायत के 50, पूंडरी के 112, राजौंद के 65 और सीवन के 71 लाभार्थी शामिल हैं। इस तरह कुल 593 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने की मंजूरी मिली है।

आवेदनों का मौके पर हो रहा सर्वे: योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की जांच और सर्वे का कार्य लगातार जारी है। इसके लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं। संबंधित वार्डों के कनिष्ठ अभियंता मौके पर जाकर आवेदकों की पात्रता की जांच कर रहे हैं। सर्वे के दौरान यह देखा जा रहा है कि जमीन वैध क्षेत्र में है या नहीं। आवेदक के नाम जमीन दर्ज है या नहीं और उस पर बना मकान कच्चा है या पक्का, इसकी भी जांच की जा रही है।

जांच के दौरान निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले आवेदनों को स्वीकार किया जा रहा है, जबकि पात्रता में कमी मिलने पर आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार कई आवेदनों में आवेदक का मकान पहले से पक्का पाया गया है। कुछ मामलों में आवेदन किसी व्यक्ति के नाम किया गया, जबकि जमीन की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम मिली। ग्रामीण क्षेत्र का पता शहरी क्षेत्र में दर्ज कराने और अवैध कालोनी में जमीन होने के कारण भी कुछ आवेदन निरस्त किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इस बार खाली प्लाट वाले पात्र आवेदकों को भी लाभ देने का प्रावधान किया गया है। पिछली योजना में खाली प्लाट धारकों को योजना का लाभ नहीं दिया गया था। अब पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने वाले ऐसे परिवार भी योजना के तहत मकान निर्माण के लिए सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

न्यूज ब्रीफ

फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों का सफाया, भारी पुलिस बल रहा तैनात

एजेंसी ,नई दिल्ली । फरीदाबाद में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने बसेलवा और कांवरा गांव के राजस्व क्षेत्र में विकसित की जा रही चार अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान 20 डीपीसी, 18 बाउंड्रीवाल, सड़क नेटवर्क और अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इन कॉलोनियों को बिना जरूरी अनुमति के विकसित किया जा रहा था। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, ताकि कार्रवाई में किसी तरह की बाधा न आए। विभाग ने अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों को चेतावनी दी है कि बिना स्वीकृति निर्माण और प्लॉटिंग करने पर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग का उद्देश्य अवैध निर्माण पर रोक लगाना और लोगों को अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति खरीदने से होने वाले संभावित नुकसान से बचाना है।



एचटेट अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना, 4 अक्टूबर को वेरिफिकेशन

एजेंसी, नई दिल्ली । हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट-2025 के अभ्यर्थियों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। गत चार और पांच जुलाई को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को परिणाम जारी होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए चार अक्टूबर को प्रदेश के सभी 22 जिलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन केंद्र स्थापित किए हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित केंद्र पर पहुंचकर अपनी बायोमेट्रिक पहचान सत्यापित करानी होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी नहीं होगी, उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी संबंधित अभ्यर्थियों से चार अक्टूबर को अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन कराने की अपील की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि परिणाम जारी होने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी या देरी का सामना न करना पड़े।



दिल्ली दंगा मामला: ताहिर हुसैन को दस्तावेज हासिल करने की मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को पुलिस के पास मौजूद कुछ दस्तावेज हासिल करने की अनुमति दी है। इन दस्तावेजों में उनके मोबाइल फोन से निकाला गया फोरेंसिक डेटा और कॉल रिकॉर्ड सहित अन्य सामग्री शामिल है। हुसैन ने दूसरे दंगा मामले में चल रहे मुकदमे में इन दस्तावेजों का इस्तेमाल अपने बचाव के लिए करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद हुसैन को उन दस्तावेजों तक पहुंच मिल सकेगी, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दंगों से जुड़े अन्य मामलों की जांच और सुनवाई के दौरान इस्तेमाल किया है। हुसैन वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी हैं। उनके खिलाफ अलग-अलग मामलों में मुकदमे चल रहे हैं और एक मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई जा चुकी है। हाई कोर्ट के ताजा आदेश का संबंध दस्तावेजों तक पहुंच और उनके बचाव में संभावित उपयोग से है। अदालत के फैसले से संबंधित मामले में अब इन दस्तावेजों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल कर उपयोग किए जाने का रास्ता खुल गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन को पुलिस का फोरेंसिक डेटा और कॉल रिकॉर्ड हासिल करने की अनुमति दी, ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया।



आईएनए स्मारक निर्माण से हाई कोर्ट का इनकार

एजेंसी, नई दिल्ली



दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किले पर इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) के शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाने का निर्देश देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि स्मारक बनाना सरकार का नीतिगत निर्णय है और न्यायालय सरकार को किसी विशेष स्थान पर जमीन आवंटित करने का आदेश नहीं दे सकता। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ स्वतंत्रता सेनानी ललती राम ट्रस्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

ट्रस्ट ने केंद्र सरकार को लाल किले पर आईएनए के हजारों बलिदानियों की याद में स्मारक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में संसद में दिए लिखित जवाब में लाल किले पर आईएनए शहीदों के लिए स्मारक बनाने की योजना की जानकारी दी थी। ट्रस्ट का दावा है कि इस घोषणा के करीब पांच वर्ष बाद भी स्मारक बनाने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। ट्रस्ट की ओर से अदालत में तर्क दिया गया कि स्मारक निर्माण में देरी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार से जुड़ा मामला है।

याचिकाकर्ता ने सरकार की घोषणा को लागू कराने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की। हालांकि अदालत ने कहा कि केवल सरकारी घोषणा या प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर ऐसा कानूनी अधिकार पैदा नहीं होता, जिसके तहत न्यायालय सरकार को स्मारक बनाने या जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दे सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि आईएनए के बलिदानियों के सम्मान में स्मारक बनाने की इच्छा पर अदालत को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसका निर्माण सरकार के नीतिगत निर्णय का विषय है। अदालत ने ट्रस्ट को संबंधित सरकारी मंत्रालय के समक्ष अपनी मांग रखने की स्वतंत्रता दी। पीठ ने कहा कि यदि ट्रस्ट सरकार के सामने औपचारिक प्रतिनिधित्व करता है, तो संबंधित अधिकारी उस पर विचार कर कानून के अनुसार उचित निर्णय ले सकते हैं। इस फैसले के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने लाल किले पर आईएनए स्मारक बनाने के लिए सीधे आदेश देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने लाल किले पर आईएनए शहीद स्मारक बनाने का आदेश देने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि स्मारक निर्माण और जमीन आवंटन सरकार का नीतिगत निर्णय है, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

प्रयागराज से लापता दो सगी बहनों की तलाश में हरियाणा-पंजाब पहुंची पुलिस



एजेंसी, नई दिल्ली

प्रयागराज के एक गांव से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुईं दो सगी बहनों की तलाश में पुलिस की टीमें हरियाणा और पंजाब तक पहुंच गई हैं। दोनों बहनों के अचानक गायब होने से परिवार में चिंता का माहौल है। स्वजन किसी अनहोनी की आशंका को लेकर परेशान हैं और लगातार पुलिस से उनकी जल्द तलाश करने की मांग कर रहे हैं।

पुलिस के अनुसार, लापता बहनों में बड़ी बहन की उम्र 13 वर्ष है और वह कक्षा आठ में पढ़ती है। वहीं, छोटी बहन आठ वर्ष की है और कक्षा चार की छात्रा है। दोनों बहनें एक ही गांव की रहने वाली हैं। उनके अचानक लापता होने के बाद परिवार के लोगों ने आसपास के इलाकों और परिचितों के यहां उनकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मामले की सूचना पुलिस को दिए जाने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की। पुलिस ने सबसे पहले गांव और आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।

जांच के दौरान सुरियावां रेलवे स्टेशन के आसपास लगे कैमरों की फुटेज में दोनों बहनें दिखाई दीं। फुटेज से पता चला कि दोनों बहनें रेलवे स्टेशन पहुंची थीं और वहां से वाराणसी जाने वाली ट्रेन में बैठी थीं। सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिलने के बाद पुलिस ने उनकी तलाश का दायरा बढ़ा दिया।

154 करोड़ के धनशोधन मामले में गौतम भल्ला पर ईडी का शिकंजा

एजेंसी, नई दिल्ली



वटिका समूह से जुड़े धनशोधन मामले में गुरुग्राम की विशेष धनशोधन निवारण अदालत ने समूह के निदेशक गौतम भल्ला को चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने जांच एजेंसी की 10 दिन की हिरासत की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए भल्ला को दो अक्टूबर को दोपहर तीन बजे अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। यह आदेश सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश नरेंद्र सूरा ने 29 सितंबर को सुनाया।

ईडी ने अदालत के समक्ष वटिका समूह से जुड़े प्लॉट की खरीद-बिक्री और खरीदारों से प्राप्त रकम के लेन-देन की जांच का हवाला देते हुए हिरासत की मांग की थी। जांच एजेंसी के अनुसार, मामले में प्लॉट की बिक्री, खरीदारों से मिली रकम और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की जा रही है। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान सामने आए दस्तावेजों और लेन-देन की जानकारी के आधार पर मामले की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। ईडी ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वर्ष 2026 में वटिका लिमिटेड, अनिल भल्ला और गौतम भल्ला के खिलाफ पांच प्राथमिकी दर्ज की हैं। ये मामले वटिका इंडिया नेक्स्ट और वटिका इंडिया नेक्स्ट-2 परियोजनाओं से जुड़े प्लॉट के सौदों से संबंधित हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, इन परियोजनाओं में प्लॉट की खरीद-बिक्री और खरीदारों से प्राप्त धनराशि के इस्तेमाल तथा लेन-देन की जांच महत्वपूर्ण है।

ईडी इसी वित्तीय लेन-देन से जुड़े पहलुओं की जांच आगे बढ़ा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी की 10 दिन की हिरासत की मांग को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया और गौतम भल्ला को चार दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

गुरुग्राम में प्रदूषण नियंत्रण की तैयारी तेज, 396 किमी सड़कों पर काम

एजेंसी, नई दिल्ली



सर्दियों के प्रदूषण से निपटने को गुरुग्राम तैयार

गुरुग्राम नगर निगम ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए नगर निगम ने अलग-अलग विभागों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए कई स्तरों पर लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनमें सड़क की धूल पर नियंत्रण, वायु गुणवत्ता की निगरानी, निर्माण एवं विध्वंस कचरे का उचित प्रबंधन और यातायात व्यवस्था सुधारना शामिल है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, सड़कों से उड़ने वाली धूल वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है।

इसे नियंत्रित करने के लिए प्रमुख सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही शहर की सड़कों की स्थिति सुधारने की दिशा में भी काम किया जाएगा। कुल 396 किलोमीटर सड़कों को सुधारने और आवश्यक रखरखाव कार्य करने की योजना बनाई गई है। वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए शहर में आठ एयर मॉनीटरिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है। इन स्टेशनों के जरिए वायु गुणवत्ता की रियल टाइम निगरानी की जा सकेगी। इससे प्रदूषण के स्तर में होने वाले बदलावों की जानकारी समय पर मिलेगी और जरूरत के अनुसार संबंधित विभाग कार्रवाई कर सकेंगे।

नगर निगम ने निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाले मलबे के प्रबंधन को भी अपनी कार्ययोजना में शामिल किया है। निर्माण स्थलों से निकलने वाले कचरे को खुले में फैलने से रोकने तथा उसके उचित निस्तारण पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्माण स्थलों पर निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे। शहर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए भी विभागवार लक्ष्य तय किए गए हैं। नगर निगम का मानना है कि सड़कों पर वाहनों की भीड़ कम होने से ईंधन की खपत और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।

आगरा के आलू किसानों पर संकट नहीं मिल रहा फसल का उचित भाव

एजेंसी, नई दिल्ली



आगरा के आलू किसान इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। किसानों को उनकी फसल का उचित बाजार भाव नहीं मिल पा रहा है, जिससे आलू की उत्पादन लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। किसानों का कहना है कि उन्हें लागत का दोगुना मूल्य दिलाने और फसल को नुकसान से बचाने के लिए किए गए सरकारी प्रयास अब तक जमीन पर नजर नहीं आए हैं। आलू किसानों को राहत देने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से करीब 15 दिन पहले आलू क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया था।

इसमें उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया था। सम्मेलन के दौरान किसानों को घाटे से उबारने, आलू की बिक्री बढ़ाने और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयासों का उल्लेख किया गया था। हालांकि किसानों का दावा है कि इनमें से किसी भी योजना का अपेक्षित लाभ उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। सबसे बड़ी चिंता कोल्ड स्टोरेज में रखे आलू को लेकर है।

किसानों के अनुसार, पर्याप्त मांग और उचित कीमत नहीं मिलने के कारण बड़ी मात्रा में आलू खराब होने की स्थिति में पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज में रखा करीब 55 से 60 प्रतिशत आलू फेंकने की कगार पर है। यदि जल्द बिक्री नहीं हुई तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। आलू के निर्यात को लेकर भी किसानों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। किसानों के मुताबिक, आगरा से आलू के निर्यात को बढ़ावा देने और निर्यात तथा भंडारण शुल्क पर सब्सिडी देने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक निर्यात के नाम पर एक बैग आलू भी बाहर नहीं भेजा जा सका है। किसानों का कहना है कि बाजार में कम कीमत, बढ़ती लागत और भंडारण की समस्या ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

मेरठ में दुस्साहसिक चेन लूट, चलती स्कूटी से महिला को गिराया

एजेंसी, नई दिल्ली

मेरठ में बागपत रोड पर बदमाशों ने एक उद्यमी की पत्नी के साथ दुस्साहसिक लूट की वारदात को अंजाम दिया। स्कूटी सवार बदमाशों ने चलती स्कूटी से महिला को सड़क पर गिरा दिया और उनके गले से करीब 11 तोले सोने की चेन झपटकर फरार हो गए। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। चित्रकूट एन्क्लेव कॉलोनी निवासी उद्यमी शशि कुमार गुप्ता की मोहकमपुर में शशि पैकेजिंग नाम से फैक्ट्री है।

मंगलवार को वह अपनी पत्नी पिंकी गुप्ता के साथ दिल्ली रोड स्थित वीनस गार्डन में आयोजित सत्संग में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम से लौटते समय बागपत रोड पर बदमाशों ने उनकी स्कूटी को निशाना बनाया। बताया गया कि बदमाशों ने पहले चलती स्कूटी से पिंकी गुप्ता को गिराया। सड़क पर गिरने के बाद वह काफी दूर तक घिसटती चली गईं। उनके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन तोड़ ली और मौके से भाग निकले। लूट के बाद शशि कुमार गुप्ता ने स्कूटी से बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की। आरोप है कि बदमाशों ने तमंचा दिखाकर उन्हें गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद वह पीछे हट गए और आरोपी फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई।

आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें बदमाश सफेद रंग की स्कूटी पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और तलाश में जुटी है। वारदात के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।

प्रयागराज से मुंबई तक 50 शहरों का होगा कायाकल्प

एजेंसी, नई दिल्ली



देश के 50 शहर बनेंगे स्वच्छ आदर्श शहर

केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 50 शहरों को 'स्वच्छ आदर्श शहर' के रूप में विकसित करने की पहल शुरू की है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इन शहरों की स्वच्छता और विकास कार्यों की प्रगति की वह हर दो महीने में व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करेंगे। इस पहल में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, अयोध्या और मथुरा समेत कई प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा बिहार के गया और पटना, दिल्ली और मुंबई सहित देश के कुल 50 शहरों का चयन किया गया है। सरकार का उद्देश्य इन शहरों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाकर उन्हें आदर्श स्वच्छ शहर के रूप में विकसित करना है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चयनित शहरों में स्वच्छता से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी।

हर दो महीने में प्रगति की समीक्षा होने से संबंधित एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन पर काम को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रहेगी। हालांकि, सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी चयनित शहरों को कब तक 'स्वच्छ आदर्श शहर' का दर्जा हासिल हो जाएगा। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस पहल की शुरुआत 51वें प्रगति सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद की है। इसे 'प्रगति-50' नाम दिया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित प्रमुख शहरों में स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

बम फटने से पहले मिलेगी चेतावनी पुलिस के बेड़े में शामिल हुई नई डिवाइस

एजेंसी, नई दिल्ली



गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के सुरक्षा इंतजामों को और मजबूत करते हुए बम निरोधक दस्ते को रूस की अत्याधुनिक तकनीक से लैस 'एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर' डिवाइस उपलब्ध कराई गई है। इसका ईवीडी-एम-आईओएन मॉडल हवा में मौजूद विस्फोटक पदार्थों के वाष्प की पहचान कर संभावित खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी देने में सक्षम है। इस तकनीक से बम विस्फोट जैसी घटनाओं को रोकने और सुरक्षा जांच को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस को उपलब्ध कराई गई इस पोर्टेबल डिवाइस को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पुलिस के स्टॉल पर प्रदर्शित किया गया।

यहां आम लोगों को अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली और पुलिस की तकनीकी क्षमता से परिचित कराया गया। अधिकारियों के मुताबिक, डिवाइस को विशेष रूप से विस्फोटक पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। पुलिस विभाग के अनुसार, यह उपकरण हवा में मौजूद विस्फोटक पदार्थों से निकलने वाले सूक्ष्म वाष्प कणों को पहचान सकता है। दावा है कि यह 10 सेकंड से भी कम समय में विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों की पहचान करने में सक्षम है।

इसकी पोर्टेबल बनावट के कारण इसे सुरक्षा जांच के दौरान अलग-अलग स्थानों पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस डिवाइस के इस्तेमाल से संवेदनशील स्थानों, सार्वजनिक आयोजनों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और अन्य सुरक्षा क्षेत्रों में जांच व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिल सकती है। खासतौर पर किसी संदिग्ध वस्तु या स्थान की जांच के दौरान विस्फोटक पदार्थों की मौजूदगी का शुरुआती संकेत मिलने से सुरक्षा बलों को समय रहते आवश्यक कदम उठाने में मदद मिल सकती है।

यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में पुलिस स्टॉल पर इस डिवाइस के अलावा कई अन्य आधुनिक सुरक्षा उपकरण और पुलिस संसाधन भी प्रदर्शित किए गए। अधिकारियों ने बताया कि बदलते सुरक्षा खतरों को देखते हुए पुलिस बल को आधुनिक तकनीक और उपकरणों से लैस किया जा रहा है।

छात्रों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, केंद्र-डीयू से जवाब तलब

पीजी-हॉस्टल में छात्रों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट सख्त

एजेंसी, नई दिल्ली



छात्र आवास सुरक्षा पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने सत्य निकेतन में 6 सितंबर को हुई इमारत ढहने की घटना के बाद छात्रों के आवास की सुरक्षा को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगम और दिल्ली विश्वविद्यालय समेत संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। याचिका में निजी पेइंग गेस्ट (पीजी), किराए के फ्लैट और निजी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा के लिए कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा प्रमुख छात्र और कोचिंग क्षेत्रों के स्तर पर छात्र आवास सलाहकार एवं निगरानी समितियां बनाने की मांग की गई है। यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के पीजीडीएवी कॉलेज के दूसरे वर्ष के छात्र शिवांश कालिया ने अधिवक्ता आशु बिधूड़ी के माध्यम से दायर की है।

याचिका के मुताबिक, राजधानी में बड़ी संख्या में छात्र संस्थागत हॉस्टल की सीमित उपलब्धता के कारण निजी आवास पर निर्भर हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए समन्वित व्यवस्था जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि फिलहाल भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, पुलिस, जिला प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी जिम्मेदारियां अलग-अलग एजेंसियों में बंटी हुई हैं, जबकि छात्रों के पास शिकायत दर्ज कराने और कार्रवाई पाने के लिए कोई एकीकृत तंत्र नहीं है। प्रस्तावित समितियों के लिए 24 घंटे की छात्र हेल्पलाइन, समर्पित ईमेल और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाने की मांग की गई है।

इनके जरिए छात्र संरचनात्मक या अग्नि सुरक्षा संबंधी खतरे, अत्यधिक भीड़, बिजली और स्वच्छता की समस्याएं, उत्पीड़न, शोषण तथा अन्य आवास संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। याचिका में निजी छात्र आवासों की समय-समय पर सुरक्षा जांच कराने और अधिकारियों के साथ संरचनात्मक, विद्युत तथा अग्नि सुरक्षा आकलन का समन्वय करने का प्रस्ताव भी है। याचिका में कॉलेज स्तर की समिति में कॉलेज, छात्र, पुलिस, जिला प्रशासन, नगर निगम और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर वरिष्ठ विश्वविद्यालय अधिकारियों के साथ सरकार, पुलिस, नगर निगम और छात्र प्रतिनिधियों की भागीदारी का सुझाव है।

प्रमुख कोचिंग और छात्र केंद्रों के लिए भी समान निगरानी समितियां बनाने की मांग की गई है। साथ ही, याचिका में छात्रों की सहमति और डेटा सुरक्षा उपायों के साथ निजी आवासों में रहने वाले छात्रों का स्वैच्छिक डेटाबेस बनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य आपात स्थिति में छात्रों तक जल्दी पहुंचना और विभिन्न क्षेत्रों में छात्र आबादी की जानकारी जुटाना है।

याचिकाकर्ता ने सुरक्षित और किफायती संस्थागत हॉस्टल बढ़ाने तथा विश्वविद्यालयों की हॉस्टल क्षमता मजबूत करने की मांग भी की है। सत्य निकेतन हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी, जिनमें पांच छात्र बताए गए। दिल्ली पुलिस के अनुसार, छह आरोपियों पर निर्माण या मरम्मत के दौरान पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं करने का आरोप है। एमसीडी ने अदालत को बताया कि संबंधित संपत्ति के लिए कोई स्वीकृत भवन योजना नहीं थी और वैध अनुमति के तहत उसका निर्माण नहीं हुआ था। एमसीडी के अनुसार, दिल्ली के 12 जोनों में चिन्हित 2,453 पीजी भवनों का सर्वे किया गया। इनमें 2,342 भवन दृष्टिगत रूप से सुरक्षित पाए गए, जबकि 91 में मामूली, 30 में बड़े मरम्मत कार्य की जरूरत और चार भवन खतरनाक स्थिति में पाए गए।

न्यूज ब्रीफ

जयनगर कॉलेज में सीएससीए पदाधिकारियों ने ली शपथ



भारतेंदु संवाददाता, अर्की। अर्की उपमंडल के राजकीय डिग्री कॉलेज जयनगर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज छात्र केंद्रीय संघ (सीएससीए) का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्या डॉ. अंजना सूद मुख्यअतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, सरस्वती वंदना और वंदे मातरम की प्रस्तुति के साथ हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रियंका (बीए तृतीय वर्ष), उपाध्यक्ष पूनम देवी (बीए तृतीय वर्ष), महासचिव शबनम (बीए द्वितीय वर्ष) और संयुक्त सचिव हर्षिता ठाकुर (बीए प्रथम वर्ष) ने पद की शपथ ली। कक्षा प्रतिनिधियों और विभिन्न क्लबों व समितियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने दायित्व निभाने का संकल्प लिया। प्राचार्या डॉ. अंजना सूद ने पदाधिकारियों को बधाई देते हुए नेतृत्व, अनुशासन, टीम भावना और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अध्यक्ष प्रियंका ने प्राचार्या, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार जताते हुए छात्र हितों एवं कॉलेज विकास के लिए मिलकर कार्य करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का समापन प्रो. जयंत शर्मा के धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ हुआ।

मंडी में अक्तूबर माह में होंगे राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) द्वारा अक्तूबर 2026 में मंडी जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण संचालित किए जाएंगे। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग विकास योजनाओं और नीतियों के निर्माण में किया जाता है। सहायक निदेशक एवं प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण टिपरी, दतवाड़ और मंडी में होगा। वार्षिक असंगठित क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण मंडी व शिवा, जबकि राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण डीपीएफ तुंग रासन में किया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सर्वेक्षण मंडी, तुंगाधार, महादेव, साई और शाकरा में तथा ऋण एवं निवेश और कृषि परिवारों का स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण सरकाघाट व चांबी में होगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षित कर्मचारी डिजिटल उपकरणों से जानकारी जुटाएंगे और सभी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी। चयनित परिवारों और संस्थानों से सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की गई है।

भाजपा परिवहन प्रकोष्ठ में पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए सह-संयोजकों की नियुक्तियां

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भारतीय जनता पार्टी परिवहन प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मनोज कुमार राणा, जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर तथा पार्टी हाईकमान से विचार-विमर्श के उपरांत भाजपा परिवहन प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विनोद कुमार सोनी ने हमीरपुर जिला में सह-संयोजकों की नियुक्तियां की हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से हरनाम सिंह और सतीश कुमार, बड़सर विधानसभा क्षेत्र से विजय कुमार और रवि कांत, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से मनोहर लाल और नसीब सिंह, भोरंज विधानसभा क्षेत्र से जोगिंदर सिंह और वीरेंद्र ठाकुर तथा नादौन विधानसभा क्षेत्र से सुरिंदर उप्पल को परिवहन प्रकोष्ठ के सह-संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने सभी नवनियुक्त सह-संयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परिवहन प्रकोष्ठ संगठन को विधानसभा स्तर पर और अधिक मजबूत करने तथा कार्यकर्ताओं एवं परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

2 अक्तूबर को विशेष ग्राम सभा में भाग लें अधिक से अधिक लोग: गंधर्वा राठौड़

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि शुक्रवार 2 अक्तूबर को जिला हमीरपुर की सभी 242 ग्राम पंचायतों में भी विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। इस विशेष ग्राम सभा में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), वित 2026-27 के बजट और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण चर्चा की जानी है। उपायुक्त ने बताया कि ग्राम पंचायतों के विभिन्न वार्डों में आयोजित उप ग्राम सभा के मुद्दों पर भी 2 अक्तूबर की विशेष ग्राम सभा में चर्चा की जाएगी। इसलिए, जिला की सभी ग्राम पंचायतों के निवासी 2 अक्तूबर को विशेष ग्राम सभा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें।

उद्यान विकास अधिकारी ने विद्यार्थियों को दी करियर ओरिएंटेशन की जानकारी



भातरेन्दु संवाददाता, मंडी। प्रदेश सरकार के अपना विद्यालय-द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम के तहत उद्यान विकास अधिकारी डॉ. अनुपमा मैहरा ने गोद लिए गए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जयदेवी में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को करियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान कर उन्हें भविष्य के लिए सही दिशा चुनने के लिए प्रेरित करना रहा। इस दौरान डॉ. अनुपमा मैहरा ने विद्यार्थियों को विभिन्न करियर विकल्पों की जानकारी देते हुए जीवन में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और उसे हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए पढ़ाई के साथ-साथ व्यक्तित्व विकास और अनुशासन भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने, नियमित शारीरिक व्यायाम करने तथा दैनिक जीवन में अनुशासन अपनाने के लिए प्रेरित किया। एकाग्रता बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट योग या ध्यान करने की सलाह भी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को स्किल, संवाद कौशल, आत्मविश्वास और समयबद्धता जैसे गुण विकसित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। डॉ. मेहरा ने कार्यक्रम के सफल आयोजन और सहयोग के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. धर्मेंद्र कुमार तथा समस्त शिक्षक वर्ग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि विद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार की गतिविधियां समय-समय पर आयोजित की जाती हैं। इसी कड़ी में अगले माह छोटे विद्यार्थियों के लिए भी करियर ओरिएंटेशन एवं मार्गदर्शन सत्र आयोजित किया जाएगा।

कांगड़ा में फ्लेवर्ड तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। कांगड़ा जिला में फ्लेवर्ड एवं कूलिंग इफेक्ट वाले धुआंरहित तंबाकू उत्पादों के भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री तथा बिक्री के लिए प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 'कूललिप फिल्टर टोबेको' सहित ऐसे धुआंरहित तंबाकू उत्पाद, जिनमें स्वाद, सुगंध, ठंडक या तंबाकू की स्वीकार्यता बढ़ाने वाले फ्लेवरिंग एजेंट अथवा अन्य पदार्थ शामिल हैं, इस आदेश के दायरे में आएंगे। जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि तंबाकू सेवन जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है तथा फ्लेवरिंग एजेंट उत्पादों को अधिक आकर्षक बनाकर तंबाकू सेवन की शुरुआत और निकोटीन पर निर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे उत्पादों के निरंतर भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री से जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए यह एहतियाती कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा की सीमा में कोई भी व्यक्ति ऐसे तंबाकू उत्पादों का भंडारण, परिवहन, आपूर्ति, बिक्री के लिए प्रदर्शन अथवा बिक्री नहीं कर सकेगा। थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा विक्रेता, ट्रांसपोर्टर तथा इस प्रकार के उत्पादों से जुड़े अन्य व्यक्तियों को इन गतिविधियों को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा, नूरपुर एवं देहरा, सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी तथा संबंधित अधिकृत अधिकारियों को आदेश की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करने और उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

नालागढ़ में मिले दो ग्रेनेड

बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज किए; आरोपी दंपत्ति अरेस्ट; एसआईटी करेगी मामले की जांच

भारतेन्दु संवाददाता, बद्दी। हिमाचल के सोलन जिले के नालागढ़ के दयोली गांव में जांच के दौरान पुलिस टीम को बुधवार को दूसरा ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। पंजाब से आए बम निरोधक दस्ते ने दोनों ग्रेनेड को सुरक्षित डिस्पोज कर दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को अरेस्ट कर लिया है।

पुलिस ने मुख्य आरोपी रशीद मोहम्मद उर्फ बाऊ निवासी मजरा को बीते मंगलवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आरोपी की पत्नी को बुधवार गिरफ्तार किया गया। रशीद मोहम्मद को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड मांगा जा रहा है। इसके बाद दोनों आरोपियों से मामले के संबंध में गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस टीम को जांच के दौरान एक ग्रेनेड घर के पास और दूसरा मकान के साथ लगते खेत में मिला। एसपी बद्दी विनोद ने बताया कि आरोपी के घर एवं आसपास के क्षेत्र में भी बम निरोधक दस्ते की सहायता से गहन तलाशी ली गई, जिसमें अन्य कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। एसपी ने बताया कि इस मामले की गहन जांच के लिए डीएसपी नालागढ़ की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया है। यह एसआईटी मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से जांच करेगी और पता लगाएगी कि बरामद ग्रेनेड कहा से लाया गया। इसके पीछे कौन कौन और लोग शामिल है।



साल का दूसरी बार विस्फोटक से जुड़ा मामला

नालागढ़ थाना क्षेत्र में इस साल विस्फोटक से जुड़ा यह दूसरा बड़ा मामला सामने आया है। इससे पहले साल के पहले दिन एक जनवरी को नालागढ़ पुलिस थाना परिसर में आईईडी विस्फोट हुआ था। उस मामले की जांच बाद में एनआईए ने अपने हाथ में ली। 25 सितंबर को एनआईए ने हरमन हैरी और जशन सैनी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उस मामले में एनआईए की गिरफ्तारियों की संख्या आठ हो गई। इस घटनाक्रम के बीच माजरा में एक के बाद एक दो ग्रेनेड मिलने से पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल इनके स्रोत, उद्देश्य और आपसी विवाद से इनके संबंध का है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

अनुराग ठाकुर ने शिक्षा, वित्त और रक्षा क्षेत्र के हितधारकों से की चर्चा

◆ गोवा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पर जेपीसी के अध्ययन दौरे में हुए शामिल

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एवं लोकसभा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गोवा अध्ययन दौरे में भाग लिया। अध्ययन दौरे का उद्देश्य विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर प्रमुख हितधारकों से सुझाव और विचार प्राप्त करना रहा।



दौरे के प्रथम सत्र में समिति ने गोवा सरकार, आईआईटी गोवा और गोवा विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के साथ उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। महाराष्ट्र स्थित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, सी-डैक पुणे तथा भारतीय भू-चुंबकत्व संस्थान के प्रतिनिधियों ने भी विधेयक से संबंधित सुझाव समिति के समक्ष रखे। समिति ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। भोजनावकाश के बाद हुई बैठक में उच्च शिक्षा के वित्तीय और रक्षा क्षेत्र से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और नाबार्ड सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए। रक्षा क्षेत्र से संबंधित चर्चा में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर अपने विचार साझा किए। जेपीसी का यह दौरा विधेयक पर व्यापक हितधारक परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा रहा।

विश्व बैंक के सहयोग से 900 करोड़ की बागछाल नादौन सड़क परियोजना को गति : जीतराम कटवाल

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल, पेयजल व बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है।



बुधवार को झंडूता भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कटवाल ने बताया कि क्षेत्र में करीब तीन दर्जन सड़कों का निर्माण किया गया है तथा नौ पुलों का निर्माण भी हुआ है। इनमें 55 करोड़ रुपए की लागत से बना बागछाल पुल और 70 करोड़ रुपए का नंद-नगरांव पुल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के सहयोग से करीब 900 करोड़ रुपए की लागत वाली बागछाल-थापना-बड़सर-नादौन सड़क परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 14 पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। करीब 70 करोड़ रुपए की कुटबौंगड़ योजना की क्षमता 80 लाख लीटर है, जिससे 20 पंचायतों की लगभग 75 हजार आबादी को लाभ मिलने का दावा किया गया।

बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए बडोल देवी में 33 केवी सब-स्टेशन हेतु 16.11 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इसके अलावा 74 नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं और करीब 45 ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जा रही है। कटवाल ने पर्यटन और रोजगार को भी प्राथमिकता बताया। उन्होंने बागछाल में औद्योगिक क्षेत्र, कोटधार में पर्यटन विकास तथा गोविंद सागर के टापुओं को पर्यटन से जोड़ने की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने क्षेत्र को फोरलेन से जोड़ने के लिए सुरंग और रोपवे निर्माण की योजनाओं को भी प्राथमिकता बताया।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की जेल, जुर्माना भी

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने 40 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला शिमला जिले के रामपुर का है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पॉक्सो/बलात्कार, किन्नौर डिवीजन, रामपुर बुशहर की अदालत ने बुधवार को यह सजा सुनाई। मामले में दोषी राजिन्दर सिंह (40) रामपुर तहसील के तकलेच का रहने वाला है। अदालत ने उसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया। पुलिस के अनुसार रामपुर थाने में 24 दिसंबर 2025 को मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

हिमाचल में 5 अक्तूबर से फिर बारिश के आसार

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले दो से तीन दिनों में हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और देश के कुछ अन्य हिस्सों से मानसून की आगे की वापसी के लिए स्थितियां बन सकती हैं। मानसून ने राज्य में 30 जून को दस्तक दी थी।

इस बीच प्रदेश में अगले चार दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। बुधवार को राज्य के अधिकतर हिस्सों में धूप खिली रही। इससे मैदानी क्षेत्रों में उमस फिर बढ़ गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण रातें हल्की ठंडी बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार, एक से 4 अक्तूबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके बाद 5 और 6 अक्तूबर को पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आ सकता है। इस दौरान मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की



संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। उत्तर हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों में बना पश्चिमी विक्षोभ का चक्रवाती परिसंचरण अभी भी सक्रिय है और समुद्र तल से करीब 1.5 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। शिमला जिले के रामपुर में 16 मिलीमीटर और खदराला में 7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बुधवार को प्रदेश का न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। लाहौल-स्पीति जिले का ताबो सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कुकुमसेरी में 4.4 डिग्री, केलांग में 4.8 डिग्री और कल्पा में 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार बुधवार दोपहर तक प्रदेश में भूस्खलन के कारण 46 सड़कें बंद थीं। इनमें मंडी में 28, कांगड़ा में छह, कुल्लू में पांच, सिरमौर, ऊना और लाहौल-स्पीति में दो-दो तथा शिमला में एक सड़क शामिल है। प्रदेश में 44 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित थे। इनमें मंडी के गोहर में 29, किन्नौर में आठ, शिमला के रामपुर में छह और चंबा के तीसा में एक ट्रांसफार्मर शामिल है। इस मानसून सीजन में बारिश से जुड़े हादसों में अब तक प्रदेश में 374 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में 222 की जान सड़क हादसों में गई है, जबकि 152 मौतें भूस्खलन, अचानक बाढ़, डूबने, बहने, फिसलने और बारिश से जुड़े अन्य हादसों में हुई हैं।

त्योहारी सीजन में व्यापारियों ने एडीसी के समक्ष उठाई बाजार की समस्याएं

बाहरी राज्यों के फेरीवालों पर नियंत्रण की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, ऊना। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ जिला मुख्यालय ऊना के बाजारों में बढ़ रही व्यापारिक गतिविधियों के बीच व्यापार मंडल ने बाजार से जुड़ी विभिन्न समस्याएं प्रशासन के समक्ष उठाई। बुधवार को व्यापार मंडल ऊना के प्रतिनिधिमंडल ने चेयरमैन अश्विनी जैतिक की अध्यक्षता में एडीसी ऊना इशांत जसवाल से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर चर्चा की। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस राजपूत भी मौजूद रहे।

अध्यक्ष प्रिंस राजपूत ने बाहरी राज्यों से आने वाले फेरीवालों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय दुकानदारों के कारोबार पर असर पड़ रहा है। व्यापारियों ने दीपावली तक खाद्य सुरक्षा और अन्य विभागों की सैंपलिंग व जांच के दौरान दुकानदारों को अनावश्यक परेशानी से राहत देने का आग्रह



◆ दीपावली तक सैंपलिंग व जांच में राहत की मांग

किया। व्यापार मंडल ने त्योहारी सामान दुकानों के बाहर सजाने की अनुमति देने की मांग भी रखी। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं को लेकर व्यापारियों ने देर रात 11 बजे के बाद डिलीवरी कर्मियों की आवाजाही पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने बाजार और प्रमुख चौकों में प्रशासन की ओर से लगाए गए पोल पर जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह किया। वहीं पुराना होशियारपुर रोड, पुल वाला बाजार और डीएवी स्कूल क्षेत्र के पास खुले नालों पर स्लैब लगाने की मांग भी उठाई। व्यापारियों ने कहा कि खुले नालों से बच्चों और राहगीरों के लिए खतरा बना रहता है। इस अवसर पर व्यापार मंडल के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

पंचतत्व में विलीन हुए मेजर मनकोटिया अंतिम विदाई में उमड़ी लोगों की भीड़

भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। हिमाचल सरकार में दो बार मंत्री व शाहपुर से पांच बार के विधायक मेजर विजय सिंह मनकोटिया पंचतत्व में विलीन हो गए।

विदेश से उनके बेटे और बेटी के पहुंचने के साथ ही बुधवार को दोपहर बाद पूर्व मंत्री मनकोटिया का उनके पैतृक गांव तियारा में अंतिम संस्कार किया गया। घर से शमशान घाट तक बैंडबाजे के साथ निकली शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं, सहित आम लोगों और उनके समर्थकों ने बड़ी संख्या में अपने नेता को अंतिम विदाई दी। प्रशासन की ओर से एसडीएम शाहपुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया (87) का बीते दिन मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। पूर्व मंत्री के बेटा और बेटी दोनों विदेश में होने के कारण उनका अंतिम संस्कार पिछले कल नही हो पाया था। ऐसे में उनके पहुंचने के बाद आज अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इससे पूर्व मनकोटिया के निधन के बाद बीते दिन से ही उनके घर पर बड़ी संख्या में लोग जुटने शुरू हो गए थे।



तियारा पंचायत के पूर्व प्रधान संदीप मनकोटिया ने बताया कि शव यात्रा में प्रदेश के कोने-कोने से पूर्व सैनिक और कांगड़ा के लोग शामिल हुए। मनकोटिया के सम्मान में तियारा बाजार भी आज बंद रखा गया। उधर मुख्यमंत्री के भी अंतिम संस्कार में पंहुचने के कयास लगाए जा रहे थे लेकिन वह नहीं पंहुच पाए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत कांग्रेस-भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। चार दशक से ज्यादा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे मेजर विजय सिंह मनकोटिया मेजर मनकोटिया ने हिमाचल की राजनीति में चार दशक तक सक्रिय भूमिका निभाई।

विद्यार्थियों ने चलाया स्वच्छता अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। स्वच्छता ही सेवा अभियान-2026 के तहत नगर परिषद बिलासपुर और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एनसीसी, एनएसएस और रोवर-रेंजर्स के विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान के दौरान विद्यार्थियों ने जल निकायों, चिन्हित हॉटस्पॉट तथा वार्ड नंबर 5 और 6 के मार्गों एवं आसपास के क्षेत्रों में सफाई की। इसके साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए स्वच्छता रैली भी निकाली गई। कॉलेज के प्रधानाचार्य पीएस कटवाल ने कार्यक्रम में विद्यार्थियों और स्टाफ के सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि नगर परिषद शहर की स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग देने और अन्य लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया।

अमेरिकी सांसदों ने दलाई लामा से की मुलाकात चीन की आपत्ति दरकिनार कर पहुंचे धर्मशाला



भारतेन्दु संवाददाता, धर्मशाला। धर्मशाला में बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस का 10 सदस्यीय दल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मिलने पहुंचा। चीन की आपत्तियों को नजरअंदाज कर हुई इस मुलाकात से शी जिनपिंग सरकार नाराज है। मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ब्रायन मास्ट ने मीडिया से बात की।

उन्होंने कहा कि चीन के दमन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मास्ट ने बताया कि दलाई लामा के साथ चीन और तिब्बती लोगों की आजादी पर लंबी चर्चा हुई। उन्होंने दलाई लामा को स्वतंत्रता का प्रतीक बताया और कहा कि अमेरिका और तिब्बत स्वतंत्रता व लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो चीन से अलग है। मास्ट

◆ कहा- तिब्बती धर्मगुरु स्वतंत्रता के प्रतीक

ने चीन पर जासूसी, पुलिस भेजने, लोगों के अंग निकालने और बौद्धिक संपदा चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि चीनी सरकार तिब्बतियों और उइगरों का दमन कर रही है, जिसके खिलाफ अमेरिकी संसद आवाज उठाती रहेगी।

प्रेस वार्ता के दौरान सांसद हेली स्टीवंस ने भी कहा कि जब दुनियाभर में स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं, तब दलाई लामा और अमेरिकी नेतृत्व मिलकर खड़े हैं, जो चीन के सूचना नियंत्रण व दमन के खिलाफ एक कड़ा संदेश है।

हिमाचल विश्वविद्यालय फोरेंसिक साइंस, एमए जेएमसी और एमएड के परिणाम घोषित

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जून-जुलाई 2026 में आयोजित परीक्षाओं के पांच परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए। परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एमएससी फोरेंसिक साइंस द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम 96.67 प्रतिशत रहा, जबकि चतुर्थ सेमेस्टर में 100 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे। एमए जेएमसी के प्रथम सेमेस्टर के जनवरी बैच का परिणाम 87.50 प्रतिशत रहा। वहीं, तृतीय सेमेस्टर के जनवरी बैच में सभी विद्यार्थी सफल रहे। एमएड तृतीय सेमेस्टर का परिणाम भी 100 प्रतिशत रहा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित विभागों और वेब व्यवस्थापक को परिणाम वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। विद्यार्थी अपनी पहचान संख्या के माध्यम से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को परिणाम से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक माध्यमों का उपयोग करने की सलाह दी है।

एनटीपीसी कोलडैम 200 एकल विद्यालयों का करेगा संचालन



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद बच्चों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने तथा शिक्षा के अवसरों को सुदृढ़ करने की दिशा में एनटीपीसी कोलडैम द्वारा अपने नैगम सामाजिक दायित्व कार्यों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।

इस पहल के तहत एनटीपीसी कोलडैम एवं भारत लोक शिक्षा परिषद के बीच बिलासपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 200 एकल विद्यालयों के संचालन हेतु समझौता ज्ञापन किया गया। 30 सितंबर को एनटीपीसी कोलडैम के परियोजना प्रमुख श्री एस एस राव तथा भारत लोक शिक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव राजीव अग्रवाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनटीपीसी कोलडैम की मानव संसाधन प्रमुख श्रीमती मंगला हरींद्रन, उप-महाप्रबंधक (सीएसआर) डॉ. अंजुला अग्रवाल, उप-प्रबंधक (सीएसआर) पूरन सिंह तथा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं भारत लोक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष अखिल कुमार गुप्ता सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस पहल के अंतर्गत एनटीपीसी कोलडैम द्वारा एकल विद्यालयों के माध्यम से ग्रामीण परिवेश के बच्चों को गैर-औपचारिक बुनियादी प्राथमिक शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं विकास से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय के लिए स्थानीय स्तर पर योग्य शिक्षित युवाओं को 'आचार्य' के रूप में चयनित किया जाएगा, जो अपने गांव एवं आसपास के क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ-साथ उनके समग्र व्यक्तित्व निर्माण पर भी केंद्रित है। भारत लोक शिक्षा

न्यूज ब्रीफ

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 दिसंबर को

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने बताया कि 12 दिसंबर को जिला बिलासपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित और पूर्व मुकदमेबाजी से जुड़े समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इनमें बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद सहित अन्य समझौता योग्य मामले शामिल हैं। न्यायालय में लंबित मामलों के पक्षकार लोक अदालत में निपटारे के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं, लंबित न होने वाले विवादों के पक्षकार भी आपसी समझौते के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-कोर्ट डिजिटल मोटर वाहन चालान का निपटारा ऑनलाइन ई-पेमेंट से लोक अदालत से पहले भी किया जा सकता है। निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 15100 और 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है।

अंडर-19 कबड्डी में राधिका ठाकुर का शानदार प्रदर्शन, राज्य स्तर के लिए चयन



भारतेन्दु संवाददाता, सोलन। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नंड की छात्रा राधिका ठाकुर ने सुबाथू में आयोजित अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कबड्डी में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हासिल किया है। प्रतियोगिता के दौरान राधिका ने बेहतरीन खेल कौशल, दमदार प्रदर्शन और आत्मविश्वास का परिचय दिया, जिससे उन्होंने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया। राधिका ने यह उपलब्धि विद्यालय के पीईटी वीरेंद्र कंवर के मार्गदर्शन में हासिल की। अब वह आगामी राज्य स्तरीय अंडर-19 कबड्डी प्रतियोगिता में जिला सोलन का प्रतिनिधित्व करेंगी। उनके चयन से विद्यालय में खुशी का माहौल है। विद्यालय की प्रधानाचार्य इंदुबाला शर्मा ने पीईटी वीरेंद्र कंवर और छात्रा राधिका ठाकुर को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि राधिका ने अपनी मेहनत, लगन और खेल प्रतिभा से विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय परिवार ने राधिका को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल प्रदर्शन की कामना की।

बिलासपुर में आज स्वच्छता व नशा-मुक्ति अभियान

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बिलासपुर को स्वच्छ, सुंदर और नशा-मुक्त बनाने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर को व्यापक जनभागीदारी के साथ 'स्वच्छ एवं नशा-मुक्त बिलासपुर अभियान' आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में यह अभियान नगर परिषद के सभी 11 वार्डों तथा बामटा, ओयल, रघुनाथपुरा और नौणी पंचायतों में चलाया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त रूपिंदर कौर ने बताया कि अभियान सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगा। प्रतिभागी सुबह 9:45 बजे निर्धारित स्थलों पर एकत्रित होंगे। अभियान के तहत 15 स्थानों पर स्वच्छता, श्रमदान और नशा-मुक्ति को लेकर जागरूकता गतिविधियां होंगी। अभियान में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों के साथ सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी और युवा संगठनों की भागीदारी रहेगी। एनएसएस, एनसीसी, रेड क्रॉस, महिला एवं युवक मंडल तथा व्यापार मंडल भी सहयोग करेंगे। प्रशासन ने नागरिकों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है।

बिलासपुर कॉलेज के छात्रों का शैक्षणिक भ्रमण संपन्न

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर के गणित विभाग की दो दिवसीय शैक्षणिक यात्रा ज्ञान, संस्कृति और रोमांच के साथ संपन्न हुई। यात्रा में 30 विद्यार्थियों ने हिमाचल की ऐतिहासिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक वादियों का भ्रमण किया। दल का नेतृत्व गणित विभाग के सहायक आचार्य डॉ. जय चंद और डॉ. राधेश्याम ने किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने कांगड़ा किले की वास्तुकला में वृत्त, त्रिकोणमिति और सममिति के प्रयोग को समझा। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में अंतर-महाविद्यालय संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां विद्यार्थियों ने करियर और गणितीय विषयों पर विचार साझा किए। भागसूनाग वाटरफॉल में विद्यार्थियों ने झरने के बहाव और चट्टानों की संरचना को गणितीय दृष्टिकोण से समझा। यात्रा के अगले चरण में विद्यार्थियों ने चाय बागानों और बैजनाथ धाम का भ्रमण किया। बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों के माध्यम से गणित के व्यावहारिक उपयोग को समझने का अवसर मिला। प्राचार्य डॉ. पी.एस. कटवाल ने यात्रा की सफलता पर विद्यार्थियों और शिक्षकों को बधाई दी।

बवासी स्कूल की छात्राएं एकांकी में प्रथम



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बवासी की छात्राओं ने जिला सोलन की अंडर-19 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए एकांकी में प्रथम स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता 28 से 30 सितंबर तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चायल में आयोजित हुई। एकांकी में श्रियांशी, हिमानी, तनुजा, सोनिया, नव्या, गीतांजलि, अनिषा, दृष्टि, सिमरन और आरुषि ने प्रभावशाली अभिनय प्रस्तुत किया। वहीं, विद्यालय की 10+2 की छात्रा हिमानी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विजेता टीम के विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्या शची और स्टाफ ने छात्राओं का स्वागत किया। एकांकी तैयार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टीजीटी राजकुमार को भी बधाई दी गई। प्रधानाचार्या ने पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए मेहनत जारी रखने का आह्वान किया। विजेता टीम राज्य स्तर पर जिला सोलन का प्रतिनिधित्व करेगी।

नगरोटा बगवां में रामलीला आयोजन को लेकर समितियों का गठन, सदस्यों को सौंपी जिम्मेदारियां

भारतेन्दु संवाददाता, नगरोटा बगवां। श्री रामलीला व दशहरा कमेटी की बैठक मंगलवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से रामलीला की तैयारियां चल रही हैं तथा आयोजन से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। सफल आयोजन के लिए स्थानीय लोगों द्वारा दिए जा रहे आर्थिक सहयोग के लिए कमेटी ने आभार जताया। बैठक में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। महिला विंग में मेकअप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धन संग्रह की जिम्मेदारी तय की गई। बच्चों के लिए टॉफियां बांटने तथा अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी सदस्यों को दी गई। मंच संचालन की जिम्मेदारी गोल्डी शर्मा, अमित बंटी और विकास खोसला को सौंपी गई। दशहरा कार्यक्रम में पुतले खड़े करने और झांकी तैयार करने का जिम्मा बलवंत मेहरा, मोहित मेहरा व विनोद सैनी की टीम को दिया गया। शोभायात्रा की जिम्मेदारी युवा वर्ग संभालेगा। कमेटी सचिव अखिल बस्सी ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कलाकारों और सदस्यों से सहयोग लिया जा रहा है।

विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका अहमः त्रिलोक जम्वाल



भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सदर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिनौला में बुधवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक त्रिलोक जम्वाल ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की, जबकि भाजपा सदर मंडल अध्यक्ष हंसराज ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बिनौला सहित आसपास की पंचायतों की आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को समाजहित में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। विधायक ने कहा कि आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता सरकार तथा आम जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही हैं। वे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, पोषण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्वास्थ्य एवं पोषण के प्रति जागरूकता भी फैला रही हैं। विधायक ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिलाओं का स्वस्थ, सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार की महिला कल्याण योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचाने पर जोर दिया।

दियोटसिद्ध को सरकार की एक और सौगात रोपवे बनाने की योजना को मिले 65 करोड़

टैक्सी पार्किंग से मंदिर तक पहुंचेगी सुविधा, आरटीडीसी संभाल रहा परियोजना की जिम्मेदारी

सुरेंद्र कटोच, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। उत्तर भारत के प्रसिद्ध बाबा बालक नाथ मंदिर स्थित दियोटसिद्ध को सरकार की एक और बड़ी सौगात मिली है।

मंदिर तक जाने के लिए 65 करोड़ की लागत से रोपवे बनाने की योजना को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस योजना को वर्ष 2028 तक पूरा किया जा सकता है। रोपवे टैक्सी पार्किंग क्षेत्र से मंदिर तक बनाया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना की जिम्मेदारी रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (आरटीडीसी) को दी गई है। मंदिर न्यास या जिला प्रशासन सीधे इसका निर्माण नहीं करेगा। परियोजना को पीपीपी मोड और डीबीएफओटी मॉडल पर विकसित किया जाना है, जिसमें निजी कंपनी डिजाइन, निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगी जबकि पूरी प्रक्रिया आरटीडीसी की निगरानी में आगे बढ़ेगी। आरटीडीसी के रिकॉर्ड के अनुसार रोपवे की टेंडर प्रक्रिया वर्ष 2023 में शुरू हुई थी। इसके बाद परियोजना से जुड़े तकनीकी और वित्तीय दस्तावेजों में संशोधन किए गए। निर्माण से पहले टेंडर प्रक्रिया और अन्य जरूरी क्लीयरेंस पूरी करना अहम होगा। प्रस्तावित रोपवे की लंबाई 520 मीटर और दोनों स्टेशनों के बीच ऊंचाई का अंतर करीब 129 मीटर है। इसमें एक स्टेशन टैक्सी पार्किंग के पास और दूसरा बाबा बालक नाथ मंदिर के पास प्रस्तावित है। रोपवे के लिए दो तरह की केबिन व्यवस्था का विकल्प रखा गया है। एक विकल्प में 12 केबिन, प्रत्येक में आठ यात्रियों की क्षमता जबकि दूसरे विकल्प में दो बड़े केबिनए प्रत्येक में 40 यात्रियों की क्षमता का प्रावधान बताया गया है।



रोपवे के लिए चार टावर का प्रस्ताव

एक तरफ का सफर करीब एक मिनट 15 सेकेंड में पूरा होने का अनुमान है। इसके लिए चार टावर की जरूरत पड़ेगी, जबकि दूसरे विकल्प में दो टावर का प्रावधान बताया गया है। रोपवे की डिजाइन क्षमता करीब 1000 यात्री प्रति घंटे प्रति दिशा रखने का प्रस्ताव है। इसे साल में करीब 350 दिन चलाने का प्रावधान भी रखा गया है।

पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने में मिलेगी सुविधा

दियोटसिद्ध में चैत्र मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे समय में सड़क पर वाहनों और श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ जाता है। रोपवे शुरू होने के बाद पार्किंग से मंदिर तक पहुंचने में सुविधा मिलने के साथ सड़क पर यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है। हालांकि, रोपवे बनने से स्थानीय बाजार और टैक्सी कारोबार पर पडने वाले असर को लेकर भी चर्चाएं हैं।

जमीनी सर्वे पूरा, क्लियरेंस की प्रक्रिया जारी: ई. अमित

डीजीएम आरटीडीसी शिमला ई. अमित शर्मा ने बताया कि रोपवे की जियो टेक्निकल जांच और जमीनी सर्वे का काम पूरा हो चुका है। परियोजना को पीपीपी मोड पर विकसित किया जा रहा है। फिलहाल आवश्यक क्लियरेंस की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद परियोजना का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की संभावना है।

अर्की पुलिस ने शटरिंग प्लेट चोरी मामले में आरोपी पकड़ा



भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। अर्की पुलिस ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली शटरिंग प्लेटें चोरी करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई प्लेटें बरामद कर ली हैं।

पुलिस के अनुसार शिमला निवासी आशीष कौशल ने थाना अर्की में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह ठेकेदारी का कार्य करते हैं और अर्की-शालाघाट सड़क पर ब्रेस्ट वॉल का निर्माण करवा रहे हैं। निर्माण स्थल पर लगाई गई शटरिंग की 46 प्लेटें 15 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया। चोरी हुई प्लेटों की अनुमानित कीमत करीब 50 हजार रुपए बताई गई। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना अर्की में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने चोरी की प्लेटों और आरोपी की तलाश के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान अमर देव (45) पुत्र बाबू राम, निवासी गांव छामला, डाकघर नवगांव, तहसील अर्की, जिला सोलन के रूप में की। पुलिस ने आरोपी को 28 सितंबर को अर्की से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे तीन दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर भेजा गया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की गई सभी शटरिंग प्लेटें बरामद कर ली गई हैं। पुलिस आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। मामले में आगामी जांच जारी है। पुलिस अधीक्षक सोलन ने मामले की पुष्टि की है।

वोट चोरी होती, तो हिमाचल में कांग्रेस सत्ता में न होती: जम्वाल

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि यदि वास्तव में 'वोट चोरी' जैसी कोई स्थिति होती, तो आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार नहीं होती।



उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव चुनाव आयोग की निगरानी में हुआ था और उसी जनादेश के आधार पर कांग्रेस सत्ता में आई तथा सुखविंद्र सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री बने। जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाना बनाने से पहले तथ्यों को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला और 19 फरवरी 2025 को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि अलग-अलग चुनावों में मिले परिणामों के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पार्टी अपनी रणनीति, संगठन और नेतृत्व की समीक्षा क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के साथ संवाद करता रहा है और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर उनके सुझाव व चिंताएं सुनता है। ऐसे में संस्थागत संवाद के रास्ते खुले होने के बावजूद केवल सार्वजनिक आरोप लगाकर आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना उचित नहीं है। जम्वाल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से पूछा कि यदि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल हैं तो वर्ष 2022 में इसी व्यवस्था से मिले कांग्रेस के जनादेश को लेकर पार्टी का क्या रुख है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि है और राजनीतिक दलों को अपने प्रदर्शन का जवाब देना चाहिए।

चक्की दरिया में मिले अज्ञात महिला के शव की हुई शिनाख्त

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। डमटाल थाना क्षेत्र के चक्की दरिया में 9 सितंबर को मिले अज्ञात महिला के शव की पहचान किरण के रूप में हुई है। मृतका के बेटे संदीप सिंह ने बताया कि उनकी माता 8 सितंबर की शाम घर से लापता हो गई थीं, जिसके बाद थाना डिवीजन नंबर-2 पठानकोट में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। परिजनों को चक्की दरिया में महिला का शव मिलने की जानकारी मिली, जिसके बाद डमटाल पहुंचकर शव की पहचान की गई। शिकायत के अनुसार अशरफ अली ने किरण से एक लाख रुपये उधार लिए थे। पैसे वापस मांगने पर कथित तौर पर धमकियां दी जाती थीं। आरोप है कि अशरफ अली और उसके रिश्तेदार बशीर दीन ने रकम हड़पने के लिए किरण को बहाने से बुलाकर हत्या कर दी और शव चक्की दरिया में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 29 सितंबर की रात हत्या सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

किसानों को नकदी फसलों की उन्नत तकनीकों का दिया प्रशिक्षण

हरे मटर और एक्सोटिक सब्जियों की खेती से लेकर विपणन तक दी जानकारी

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददता, मंडी। कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर में 'हिम्मोथान सोसाइटी', लेह-लद्दाख के सौजन्य से लद्दाख से आए किसानों के लिए नकदी फसलों के उत्पादन विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।



इसमें लद्दाख के 24 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ हरे मटर और एक्सोटिक सब्जियों की खेती, उत्पादन तथा विपणन की जानकारी देना रहा। प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य डॉ. ओम प्रकाश बंसल ने किसानों का स्वागत करते हुए उन्हें आधुनिक एवं लाभकारी कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने प्रशिक्षण के बाद किसानों से संवाद कर उनके अनुभव और प्राप्त जानकारी के बारे में भी चर्चा की। उप प्रधानाचार्य डॉ. जगदीश कुमार जंजीहा ने हरे मटर की खेती के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने भूमि की तैयारी, बिजाई, सिंचाई, कीट एवं रोग प्रबंधन, उत्पादन और विपणन की तकनीकों को समझाया तथा किसानों के सवालों के जवाब दिए। प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. सुधीर कुमार ने एक्सोटिक एवं विदेशी सब्जियों की खेती की जानकारी साझा की। उन्होंने किसानों को भूमि तैयार करने से लेकर बिजाई, सिंचाई, रोग एवं कीट प्रबंधन, उत्पादन और बाजार तक पहुंच बनाने की तकनीकों से अवगत करवाया। कार्यक्रम के तहत डॉ. नरेश कुमार और डॉ. सुधीर कुमार के मार्गदर्शन में किसानों को सुंदरनगर के आसपास के प्रगतिशील किसानों के खेतों का भ्रमण भी करवाया गया। इस दौरान किसानों ने खेतों में अपनाई जा रही नवीन तकनीकों और कृषि प्रयोगों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव भी साझा किए। भ्रमण से लद्दाख के किसानों को व्यावहारिक स्तर पर उन्नत कृषि तकनीकों को समझने और उन्हें अपने क्षेत्रों में अपनाने की जानकारी मिली।

प्रताप वर्ल्ड स्कूल में 'ज्वॉइन इंडियन आर्मी' कार्यक्रम के तहत साइकिल यात्रियों का स्वागत



अशोक ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। प्रताप वर्ल्ड स्कूल, पठानकोट में 'ज्वॉइन इंडियन आर्मी' कार्यक्रम के तहत साइकिल यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

यह कार्यक्रम 16 सितंबर से 3 अक्तूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं में शारीरिक तंदुरुस्ती, अनुशासन, साहस, दृढ़ता और राष्ट्रसेवा की भावना को बढ़ावा देना है। साथ ही युवाओं को भारतीय सेना में उपलब्ध अवसरों और सैनिक जीवन के बारे में जानकारी देना भी इसका उद्देश्य है। यात्रा के दौरान विद्यालय पहुंचे साइकिल यात्रियों ने विद्यार्थियों से संवाद किया और अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। विद्यार्थियों को इस दौरान दृढ़ संकल्प, अनुशासन और प्रतिबद्धता के महत्व को समझने का अवसर मिला।

कार्यक्रम का आयोजन निफा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक एस. प्रीतपाल सिंह पन्नू तथा सरबप्रीत सिंह के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। पंजाब की निफा टीम में अध्यक्ष सचप्रीत सिंह खैराबेट, परियोजना निदेशक एवं महासचिव दीपक वालिया तथा दलवीर सिंह बाजवा शामिल हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या शुभ्रा रानी ने कहा कि साइकिल यात्रियों की यात्रा अनुशासन, दृढ़ता और संकल्प का प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखने का अवसर देते हैं। विद्यालय के निदेशक सनी महाजन ने कहा कि इस सार्थक पहल का हिस्सा बनना विद्यालय के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने निफा और कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की। विद्यालय परिवार ने सभी साइकिल यात्रियों को उनकी आगामी यात्रा के लिए सुरक्षित, सफल और प्रेरणादायक सफर की शुभकामनाएं दीं।

अर्की के बतीवां में तेंदुए ने बाइक सवार पर किया हमला, बाल-बाल बची जान

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। उपमंडल अर्की में तेंदुओं की बढ़ती सक्रियता ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। क्षेत्र में तेंदुए से जुड़ी घटनाओं के बाद अब रोहांज-जलाना पंचायत के बतीवां गांव में एक और मामला सामने आया है। हालांकि, इस घटना में बाइक सवार प्रदीप शर्मा बाल-बाल बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई।

बतीवां निवासी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बीते कल दोपहर करीब 3:40 बजे वह अर्की से मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। घर से लगभग 200 मीटर पहले बतीवां खाल के पास अचानक एक तेंदुआ सड़क पर आ गया और उसने उनकी मोटरसाइकिल पर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि तेंदुआ करीब 100 मीटर तक मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ता रहा। प्रदीप ने मोटरसाइकिल की गति बढ़ाकर किसी तरह वहां से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस सड़क मार्ग पर तेंदुए की गतिविधि सामने आई है, वहां सुबह से शाम तक लोगों की आवाजाही रहती है। इसी मार्ग से स्कूली बच्चे भी आते-जाते हैं। ऐसे में तेंदुए की मौजूदगी लोगों और बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, तेंदुए की गतिविधियों पर निगरानी रखने और सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

बच्चों को अकेले सुनसान रास्तों पर न भेजें: वन विभाग

वन परिक्षेत्राधिकारी अर्की अशोक कुमार ने बताया कि विभाग को घटना की जानकारी मिली है। टीम जल्द क्षेत्र का निरीक्षण करेगी व तेंदुए की गतिविधियों का पता लगाकर आवश्यक कार्रवाई करेगी। उन्होंने ग्रामीणों से सुबह-शाम सतर्क रहने और बच्चों को अकेले सुनसान रास्तों पर न भेजने की अपील की।

हिमानी के अभिनय ने जीता दिल, बनीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

भारतेन्दु संवाददाता, अर्की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बवासी की 10+2 की छात्रा हिमानी ने जिला सोलन की अंडर-19 छात्रा वर्ग की जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता में अपनी अभिनय प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। एकांकी प्रतियोगिता में हिमानी ने प्रभावशाली अभिनय करते हुए निर्णायक मंडल का ध्यान आकर्षित किया। उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्या शची और समस्त विद्यालय स्टाफ ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उनकी उपलब्धि ने बवासी स्कूल की विजेता एकांकी टीम के प्रदर्शन को और खास बना दिया। हिमानी अब टीम के साथ राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला सोलन का प्रतिनिधित्व करेंगी।



राष्ट्रपति दौरे की तैयारियों को लेकर आनंदपुर साहिब हेलिपैड का किया निरीक्षण

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 अक्तूबर को प्रस्तावित बिलासपुर दौरे के मद्देनजर बिलासपुर और रोपड़ प्रशासन ने आनंदपुर साहिब हेलीपैड का संयुक्त निरीक्षण किया। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान सहित संबंधित अधिकारियों ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, बैरिकेडिंग, आवागमन और संचार व्यवस्था पर चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद प्रशासनिक टीम ने टोबा से श्री नयना देवी मंदिर तक सड़क, यातायात, सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल और बिजली व्यवस्था की समीक्षा की। उपायुक्त ने मंदिर परिसर का भी निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुविधा, प्रवेश-निकासी और सुरक्षा व्यवस्था को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तैयारियां पूरी करने को कहा।

दौरा भड़वाल में विधायक पवन काजल ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

अनसोली में लगेंगे दो ट्यूबवेल



भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। भाजपा उपाध्यक्ष व विधायक पवन काजल ने बुधवार को जनसंपर्क अभियान के तहत भुली भड़वाल के वार्ड नंबर-3 का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और क्षेत्र में चल रहे तथा प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी साझा की।

काजल ने प्रदेश सरकार पर ग्रामीणों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायत से परिवार नकल के लिए ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और ऑनलाइन भुगतान का उपयोग न करने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित शुल्क का भी विरोध किया और कहा कि इससे ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। महिलाओं को 1500 रुपए देने के कांग्रेस सरकार के वादे का जिक्र करते हुए काजल ने कहा कि सरकार इसे पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि भड़वाल गांव के लिए पेयजल योजना का पानी अब अनसोली और मटोर नहीं जाएगा, जिससे भड़वाल के ग्रामीणों को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। काजल ने बताया कि अनसोली पंचायत के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपए की नई पेयजल योजना को विधायक प्राथमिकता के तहत मंजूरी मिली है। योजना के तहत अनसोली में दो ट्यूबवेल लगाए जाएंगे तथा नए जल भंडारण टैंक का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना के पूरा होने से क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस दौरान विधायक ने वार्ड नंबर-3 में दो रास्तों के निर्माण के लिए पांच लाख रुपये देने की घोषणा भी की। उन्होंने स्थानीय लोगों को क्षेत्र के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत मंदल की प्रधान पुष्पा देवी, उपप्रधान सुरेंद्र कुमार, पंच निशा देवी, जिला परिषद सदस्य विजय कुमार बिज्जू, ग्राम पंचायत मटोर के उपप्रधान संजीव काका, सत प्रकाश सोनी, चरणजीत सहित अन्य ग्रामीण और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे।

खोली पंचायत में चला स्वच्छता अभियान प्रधान कुलवंत चौधरी ने संभाली कमान



आशीष दमीर, भारतेन्दु संवाददाता, कांगड़ा। ग्राम पंचायत खोली में रीसायकल हिमालय के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पंचायत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर सफाई कर कूड़े-कचरे को एकत्रित किया गया।

इस दौरान ग्रामीणों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किया गया। स्वच्छता अभियान में ग्राम पंचायत खोली के प्रधान कुलवंत चौधरी ने सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं सफाई अभियान में हिस्सा लेकर ग्रामीणों के साथ मिलकर गांव की सफाई की। पंचायत के उपप्रधान, वार्ड सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लिया। प्रधान कुलवंत चौधरी ने कहा कि स्वच्छ गांव स्वस्थ समाज की पहचान है। गांव को साफ-सुथरा रखना केवल पंचायत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक ग्रामीण का दायित्व है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास गंदगी न फैलाने तथा कूड़े का उचित निपटारा करने की अपील की। रीसायकल हिमालय की टीम ने ग्रामीणों को कचरे के

बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला का अंदाज निराला

भारत की दिग्गज बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन की खूबसूरती खिलाड़ियों में एक हैं। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ज्वाला गुट्टा ने अपने पार्टनर अश्विनी पोनप्पा के साथ भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। वहीं, ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में ज्वाला गुट्टा ने स्वर्ण पदक हासिल किया था।



एशियन गेम्स: आज भारत और पाकिस्तान में हॉकी सेमीफाइनल

मलेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला

एजेंसी, नई दिल्ली

एशियन खेल 2026 में वीरवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमें टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में आमने-सामने होंगी, जहां जीतने वाली टीम स्वर्ण पदक के मुकाबले में पहुंचेगी। दूसरा सेमीफाइनल मलेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। गत चैंपियन भारत ने पूल चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांचों मुकाबले जीते और पूल-ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत ने अभियान की शुरुआत इंडोनेशिया को 13-1 से हराकर की। इसके बाद श्रीलंका को 16-1, दक्षिण कोरिया को 8-2, मेजबान जापान को 2-0 और बांग्लादेश को 10-0 से शिकस्त दी।

भारतीय टीम की आक्रमण पंक्ति ने अबतक शानदार प्रदर्शन किया है। दिलप्रीत सिंह नौ गोल के साथ टूर्नामेंट के संयुक्त रूप से दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोरर हैं। अभिषेक और कप्तान हरमनप्रीत सिंह के नाम आठ-आठ गोल हैं।



पेनल्टी कॉर्नर में हरमनप्रीत की ड्रैग-फ्लिक भारत का अहम हथियार रही है। वहीं, पाकिस्तान पूल-बी में शीर्ष पर रहते हुए भारत से फाइनल में भिड़ने की स्थिति में था लेकिन मलेशिया के खिलाफ 4-5 की हार के कारण उसे दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। पाकिस्तान ने थाईलैंड को 9-0, उज्बेकिस्तान को 5-1, चीन को 3-0 और ओमान को 7-2 से हराया।

पाकिस्तान के लिए सुफियान खान सबसे बड़ा खतरा होंगे। पेनल्टी कॉर्नर पर शानदार प्रदर्शन कर रहे सुफियान के नाम अब तक 11 गोल हैं और वह टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर हैं। ऐसे में सुफियान और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत के बीच पेनल्टी कॉर्नर की जंग मुकाबले का अहम पहलू हो सकती है। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला सिर्फ सेमीफाइनल नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही प्रतिद्वंद्विता का एक और अध्याय होगा। भारत ने 2016 दक्षिण एशियाई खेलों के फाइनल के बाद से पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुकाबला नहीं गंवाया है। गत चैंपियन भारतीय टीम इस सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार दूसरी बार एशियन खेल के फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। भारत के मुख्य कोच फुल्टन ने कहा कि सेमीफाइनल टूर्नामेंट का बेहद महत्वपूर्ण मुकाबला है और टीम पेनल्टी कॉर्नर के आक्रमण और बचाव सहित अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करेगी।

राजकुमार पाल बाहर निलकंठ शर्मा टीम में

भारत को सेमीफाइनल से पहले बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी पूल मुकाबले में राजकुमार पाल के बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया, जिसके कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह रिजर्व खिलाड़ी नीलकंठ शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने कहा कि राजकुमार का चोटिल होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन नीलकंठ के आने से टीम को अनुभवी खिलाड़ी का विकल्प मिला है। नीलकंठ ओलंपिक और विश्वकप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

भारत की पुरुष और महिला स्क्वॉश टीमें सेमीफाइनल में

एजेंसी, नागोया



भारतीय पुरुष और महिला स्क्वॉश टीमों ने बुधवार को यहां क्रमशः कुवैत और सिंगापुर को हराकर एशियाई खेलों की स्क्वाश प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में जगह बनाई और इस तरह से अपने लिए पदक पक्के किये। शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में कुवैत पर 2-0 से जीत हासिल की। वीर चोटरानी ने पहले एकल मुकाबले में बदर अलमोगरेबी के खिलाफ काफी पसीना बहाया लेकिन आखिर में वह 34 मिनट तक चले मैच में 12-10, 8-11, 11-0, 11-5 से जीत हासिल करने में सफल रहे। भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी और एकल में रजत पदक जीतने वाले अभय सिंह ने दूसरे एकल में अम्मार अल्तमिमी पर 11-3, 11-4, 11-8 से जीत हासिल करके टीम की सेमीफाइनल में जगह सुरक्षित की।

महिला वर्ग में अनाहत सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने क्वार्टरफाइनल में सिंगापुर को 2-0 से हराया। भारत की तरफ से तन्वी खन्ना ने शुरुआत करते हुए पहले एकल मैच में औ येओंग वाई इयन को 11-6, 4-11, 15-13, 11-1 से पराजित किया। यह मैच 32 मिनट तक चला। व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली अनाहत ने दूसरे एकल मुकाबले में केवल 22 मिनट में औ योंग वाई यान को 11-7, 11-3, 11-4 से हराकर भारत की सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इस तरह से मिश्रित युगल में कांस्य पदक जीतने वाली अनुभवी खिलाड़ी जोशना चिनप्पा को कोर्ट में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। सेमीफाइनल वीरवार को खेला जाएगा। भारत ने पूल सी के अपने पहले दो मैचों में चीन और जापान को हराने के बाद मंगलवार को ग्रुप चरण के अपने आखिरी मैच में ईरान को 3-0 से हराया था।

स्पोर्ट्स विंडो

सुनील कुमार ग्रीको-रोमन कुश्ती में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय

एजेंसी, नागोया। भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने एशियन खेल 2026 में पुरुषों के ग्रीको-रोमन 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। सुनील ने बुधवार को कांस्य पदक मुकाबले में फिलीपींस के कैलम जॉनस्टन रॉबर्ट्स को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 9-0 से हराया। नागोया सिटी इनाए स्पोर्ट्स सेंटर में हुए मुकाबले में सुनील ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। उन्होंने 9-0 की बढ़त हासिल की और मुकाबला खत्म होने में करीब तीन मिनट बाकी रहते ही तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत दर्ज कर ली। इस जीत के साथ सुनील कुमार एशियन खेल में ग्रीको-रोमन कुश्ती में दो पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। उन्होंने इससे पहले 2023 हांगझोऊ एशियन खेल में भी कांस्य पदक जीता था। सुनील ने हांगझोऊ में अपने अभियान की शुरुआत ताजिकिस्तान के मुहम्मद सुल्तोनज़ोदा को 9-0 से हराकर की थी। हालांकि, सेमीफाइनल में उन्हें जापान के ताइजो योशिदा के खिलाफ 0-11 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कांस्य पदक मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए रॉबर्ट्स को एकतरफा अंदाज में हराया। सुनील का यह प्रदर्शन एशियन खेल में भारतीय कुश्ती के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने ग्रीको-रोमन शैली में देश के लिए लगातार दूसरे एशियन खेल में पदक सुनिश्चित किया है।



गिल वनडे रैंकिंग में पहले, कोहली दूसरे और रोहित चौथे नंबर पर



एजेंसी, नई दिल्ली। विराट कोहली आईसीसी की वनडे बैटर्स रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नाबाद 139 रन की पारी खेलने का उन्हें फायदा मिला। कोहली के अब 796 रेटिंग पॉइंट हैं। वे टॉप पर मौजूद भारतीय कप्तान शुभमन गिल से सिर्फ 20 पॉइंट पीछे हैं। रैंकिंग हर हफ्ते बुधवार को जारी की जाती है। 27 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले वनडे में कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन बनाए थे। यह उनका वनडे करियर का 55वां शतक था। इसी पारी के दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15 हजार रन भी पूरे किए। वह सचिन तेंदुलकर के बाद यह आंकड़ा छूने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। भारत ने मुकाबला 8 विकेट से जीता था।

टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, दक्षिणेश्वर बाहर

एजेंसी, नागोया। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने बुधवार को यहां एशियाई खेलों के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली जबकि दक्षिणेश्वर सुरेश तीसरे दौर में हारकर बाहर हो गए। सातवीं वरीयता प्राप्त और विश्व रैंकिंग में 249वें स्थान पर काबिज नागल ने उज्बेकिस्तान के सर्गेई फोमिन को सीधे सेट में 6-3, 6-2 से हराकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। नागल ने फोमिन के खिलाफ मुकाबले में शुरू से नियंत्रण बनाए रखा और सीधे सेटों में जीत दर्ज की। अब उनका सामना तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के यीबिंग वू से होगा जो विश्व रैंकिंग में 111वें स्थान पर हैं। नागल और वू इससे पहले 2024 शंघाई मास्टर्स में एक बार आमने-सामने हुए थे जहां भारतीय खिलाड़ी को चीनी खिलाड़ी के खिलाफ 3-6, 3-6 से हार मिली थी। दूसरी ओर दक्षिणेश्वर को तीसरे दौर में चीनी ताइपे के छठी वरीयता प्राप्त चुन शिन सेंग के हाथों 3-6, 4-6 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी ने मंगलवार को इंडोनेशिया के गुनावान त्रिस्मुवंतारा को सीधे सेटों में हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई थी। भारत के पुरुष युगल अभियान को भी झटका लगा जब एन श्रीराम बालाजी और बाएं हाथ के अनिरुद्ध चंद्रशेखर की जोड़ी को चीन के फुमिन चियांग और तियानहुई जियांग के खिलाफ कड़े क्वार्टर फाइनल में 7-6, 6-7, 8-10 से हार मिली।

भारतीय साइकिलिस्ट एशियाई खेलों के क्वालीफाइंग दौर से बाहर

एजेंसी, इजू। भारतीय साइकिलिस्ट का एशियाई खेलों में प्रदर्शन निराशाजनक रहा और दोनों महिला और पुरुष टीमें बुधवार को बाहर हो गईं। भारत के रोनाल्डो सिंह लाइतोंगजाम और डेविड बैकहम पहले क्वालीफाइंग दौर से आगे निकले। डेविड पुरुषों की फर्राटा स्पर्धा में 9.996 सेकंड का समय निकालकर 14वें और रोनाल्डो 10.052 के साथ 15वें स्थान पर रहे। दोनों अंतिम 16 में हारकर बाहर हो गए। रोनाल्डो हीट दो में चीन के झिवेइ लि के बाद दूसरे स्थान पर रहे जबकि बैकहम मलेशिया के मोहम्मद अजीजुल्हासनी अवाग के बाद दूसरे स्थान पर थे। अंतिम 16 रेपेशॉज हीट में भी दोनों दूसरे स्थान पर रहे। महिला केरिन स्पर्धा में दोनों राइडर पहले दौर से आगे नहीं बढ सके। हीट दो में सरिता कुमारी पांचवें और हीट तीन में कीर्ति चिक्का रंगास्वामी चौथे स्थान पर रही।

बांग्लादेश, न्यूजीलैंड सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की घोषणा

एजेंसी, मेलबर्न



ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए अपनी महिला टीम घोषित कर दी है। दोनों सीरीज के लिए सोफी मोलिन्यू को कप्तान बनाया गया है। हालांकि, कूल्हे की चोट से उबर रही मोलिन्यू की उपलब्धता पर लगातार नजर रखी जाएगी।

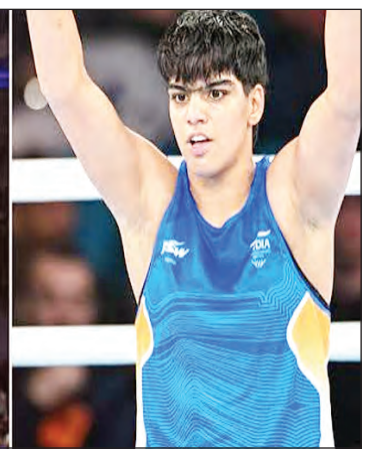
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि मोलिन्यू टीम में शामिल हैं, लेकिन चोट से पूरी तरह उबरने के बाद ही उनकी सीरीज में भागीदारी पर अंतिम फैसला होगा। राष्ट्रीय चयनकर्ता शॉन फ्लेगलर ने कहा कि मोलिन्यू कूल्हे की चोट का प्रबंधन कर रही हैं और आने वाले दिनों में उनकी स्थिति का आकलन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दोनों सीरीज के लिए 14 सदस्यीय टीम चुनी है। तेज गेंदबाज डार्सी ब्राउन पीठ की चोट के कारण टीम से बाहर हैं, जबकि लूसी हैमिल्टन बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में क्वाड स्ट्रेन के कारण उपलब्ध नहीं रहेंगी। हालांकि, उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज तक फिट होने की उम्मीद है। ग्रेस हैरिस को टीम में जगह नहीं मिली है। चयनकर्ता फ्लेगलर ने स्पष्ट किया कि वह भविष्य की योजनाओं में बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि टी20 टीम का आकार छोटा होने और विश्व कप के दौरान सीमित अवसरों के कारण हैरिस चयन से चूक गईं। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 9 अक्टूबर से शुरू होगी। तीनों मुकाबले ब्रिस्बेन के एलन बॉर्डर फील्ड में खेले जाएंगे। पहला वनडे 9 अक्टूबर, दूसरा 11 अक्टूबर और तीसरा 14 अक्टूबर को होगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज होगी। पहला मैच 18 अक्टूबर, दूसरा 20 अक्टूबर और तीसरा 22 अक्टूबर को सिडनी के नॉर्थ सिडनी ओवल में खेला जाएगा।

भारतीय पुरुष और महिला मुक्केबाजों को सेमीफाइनल में हार का करना पड़ा सामना

एशियन गेम्स में कपिल और प्रिया को कांस्य पदक

एजेंसी, नागोया





भारतीय मुक्केबाज कपिल पोखरिया ने एशियन खेल 2026 में पुरुषों के 90 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल में कपिल को उज्बेकिस्तान के मौजूदा विश्व चैंपियन तुराबेक खबीबुल्लायेव के खिलाफ 1-4 के स्प्लिट डिसीजन से हार का सामना करना पड़ा। तुराबेक ने मुकाबले की शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा। उन्होंने पहला राउंड 5-0 से अपने नाम किया, जबकि दूसरे राउंड में भी 4-1 से बढ़त हासिल की।

भारतीय मुक्केबाज ने वापसी की कोशिश की, लेकिन उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी की बढ़त को पाट नहीं सके। अंत में जजों के बहुमत के फैसले से तुराबेक को विजेता घोषित किया गया। तुराबेक 2022 हांगझोऊ एशियन खेल के कांस्य पदक विजेता भी हैं और मौजूदा विश्व चैंपियन होने के कारण उन्हें मुकाबले में मजबूत दावेदार माना जा रहा था।

वहीं, भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने एशियन खेल में अपने पदार्पण को कांस्य पदक के साथ समाप्त किया। हरियाणा के झज्जर जिले की 20 वर्षीय प्रिया को बुधवार को महिलाओं के 60 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में चीन की पूर्व विश्व चैंपियन यांग चेंग्यू के खिलाफ 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। निशियो में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में प्रिया ने अनुभवी चीनी मुक्केबाज को कड़ी चुनौती दी, लेकिन यांग चेंग्यू ने अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही प्रिया का कांस्य पदक पहले ही पक्का हो गया था। प्रिया ने हाल के महीनों में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 2026 राष्ट्रमंडल खेल, 2026 एलीट एशियाई चैंपियनशिप, 2026 उस्ती नाद लाबेम ग्रां प्री और 2026 बॉक्सम कप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने 2025 थाईलैंड ओपन में कांस्य पदक भी हासिल किया था।

कपिल को विश्व चैंपियन खबीबुल्लायेव और प्रिया को पूर्व चैंपियन यांग ने हराया

तकनीकी सटीकता, रिंग में समझ और संयमित अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली प्रिया ने एशियन गेम्स के अपने पहले ही अभियान में पदक जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई।

अमेरिका ने कनाडा की एक अरब डॉलर की वस्तुओं पर लगाया प्रतिबंध

एजेंसी, वाशिंगटन



अमेरिका और कनाडा के बीच लंबे समय से जारी व्यापारिक तनाव अब और गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने करीब एक अरब डॉलर मूल्य की कनाडाई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला मंगलवार आधी रात से लागू हुआ। हालांकि दोनों देशों के बीच होने वाले करीब 880 अरब डॉलर के कुल द्विपक्षीय व्यापार की तुलना में प्रतिबंधित वस्तुओं का मूल्य कम है, लेकिन इससे व्यापारिक और कूटनीतिक संबंधों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने कनाडा की डेयरी, शराब और वाहन उद्योग से जुड़ी नीतियों को भेदभावपूर्ण बताते हुए पहले भी कनाडाई उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया था। इसके जवाब में कनाडा ने अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क लगाया और कई दुकानों से अमेरिकी शराब हटाई।

◆ डेयरी और शराब विवाद के बीच अमेरिका ने कनाडा पर कसा शिकंजा

अब कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका पर निर्भरता घटाने की रणनीति शुरू की है। उन्होंने अगले दशक में अन्य देशों के साथ व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इस विवाद से अमेरिका-कनाडा-मेक्सिको व्यापार समझौते के भविष्य को लेकर भी चिंता बढ़ी है।

एपल पे की भारतीय बाजार में एंट्री

एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी एपल ने भारत में अपनी भुगतान सेवा एपल पे शुरू कर दी है। शुरुआत में यह सुविधा एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत एक्सिस बैंक के ग्राहक अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड को आईफोन या एपल वॉच के एपल वॉलेट में जोड़ सकेंगे। भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए फेस आईडी या टच आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राहक दुकानों पर संपर्क रहित भुगतान के साथ वेबसाइट और मोबाइल अनुप्रयोगों पर भी इसका उपयोग कर सकेंगे। कंपनी की योजना आने वाले समय में अन्य बैंकों के कार्ड को भी एपल पे से जोड़ने की है। भारत की लोकप्रिय एकीकृत भुगतान प्रणाली को भी जल्द इसमें शामिल किए जाने की तैयारी है। इससे देश के डिजिटल भुगतान बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। भारत में एपल के दिल्ली और मुंबई समेत छह आधिकारिक खुदरा स्टोर हैं और कंपनी अपने साझेदार स्टोरों का नेटवर्क भी बढ़ा रही है। भारत अब एपल के लिए केवल बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण विनिर्माण और निर्यात केंद्र भी बन चुका है। भुगतान सेवा की शुरुआत कंपनी के भारतीय बाजार में विस्तार की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है।

मेटल और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली

सेंसेक्स 72,480 और निफ्टी 22,620 पर बंद

एजेंसी, मुंबई



घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 48 अंक टूटकर 72,480 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 92 अंकों की गिरावट रही और यह 22,620 के स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान मेटल और फार्मा क्षेत्र के शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली देखने को मिली। बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली का असर भी दिखाई दिया।

बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने पिछले सात दिनों में भारतीय शेयर बाजार में 24,055 करोड़ रुपये के शेयर बेचे हैं। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इसी अवधि में 19,281 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। पिछले 30 दिनों में विदेशी निवेशकों की कुल बिकवाली 33,865 करोड़ रुपये रही, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 64,759 करोड़ रुपये की खरीदारी की।

इसी बीच बुधवार को दो नए आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) भी खुले। सिविल इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचा क्षेत्र की कंपनी विशाल निर्मिति तथा आभूषण क्षेत्र की कंपनी नित्यास जेम्स एंड ज्वैलरी के आईपीओ में निवेशक पांच अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे। विशाल निर्मिति आईपीओ के माध्यम से 178 करोड़ रुपये, जबकि नित्यास जेम्स एंड ज्वैलरी 108 करोड़ रुपये जुटाने की योजना लेकर बाजार में आई है।

एशियाई बाजारों में बुधवार को मिलाजुला कारोबार रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.48 प्रतिशत गिरा, जबकि जापान का निक्केई 1.94 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग 0.37 प्रतिशत बढ़कर बंद हुआ। इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी बाजारों में भी गिरावट रही थी। डाउ जोन्स, नैस्डैक और एसएंडपी 500 में कमजोरी दर्ज की गई थी।

डिजिटलीकरण — 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा सुविधा, विपणन मजबूत करने पर जोर

देश की 1800 पर्यटन परिसंपत्तियों का होगा डिजिटलीकरण

एजेंसी, नई दिल्ली



देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार देशभर की 1,800 और पर्यटन परिसंपत्तियों को डिजिटल मंच पर लाने की तैयारी कर रही है। योजना के तहत जनवरी से जून 2027 के बीच छह महीने में इन पर्यटन परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। पर्यटन परिसंपत्तियों को डिजिटल मंच से जोड़ने का उद्देश्य पर्यटकों को यात्रा से पहले ही संबंधित स्थल की आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी यात्रा की बेहतर योजना बना सकें।

संयुक्त पर्यटन सचिव हरि किशोर ने राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन से इतर बताया कि पर्यटन परिसंपत्तियों के डिजिटलीकरण के तहत केवल किसी स्थल की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराना ही शामिल नहीं है, बल्कि टिकट बुकिंग, आसपास के पर्यटन स्थलों की जानकारी, प्रबंधन और अन्य सुविधाओं को भी डिजिटल माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे पर्यटकों को एक ही मंच पर यात्रा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रबंधन वाली कई पर्यटन परिसंपत्तियों को पहले ही डिजिटल मंच पर लाया जा चुका है। इस व्यवस्था से पर्यटक घर बैठे किसी स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर यात्रा की तैयारी कर सकते हैं।

डिजिटल व्यवस्था का लाभ पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों को भी मिल सकता है। टूर और ट्रैवल कंपनियां इन डिजिटल सेवाओं को अपने मंच से जोड़कर ग्राहकों को यात्रा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगी।

वीजा प्रक्रिया अहम

पर्यटन सम्मेलन में विशेषज्ञों ने पर्यटन क्षेत्र के व्यापक विकास पर भी जोर दिया। इसमें चिकित्सा पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों को अलग-अलग विकसित करने और उनकी मांग बढ़ाने की जरूरत बताई गई। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक पहनावा, खान-पान और स्थानीय जीवनशैली विदेशी पर्यटकों के साथ घरेलू पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का बड़ा आधार बन सकते हैं। इसलिए केवल ऐतिहासिक स्मारकों और पर्यटन स्थलों के प्रचार तक सीमित रहने के बजाय पर्यटकों को भारत के विविध अनुभवों से जोड़ने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यटन को बढ़ावा देने में वीजा प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है और ऑनलाइन वीजा आवेदनों में करीब 95 प्रतिशत का निपटारा 24 घंटे के भीतर कर दिया जाता है।

वाहनों के लिए नए कैफे नियम अधिसूचित, 2027 से होंगे लागू



एजेंसी, मुंबई

प्रदूषण पर लगाम लगाने और वाहनों की ईंधन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था (कैफे) के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। विद्युत मंत्रालय की ओर से जारी कैफे-3 नियम एक अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे। इनके तहत वित्त वर्ष 2027-28 में ईंधन खपत का मानक 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर तय किया गया है, जिसे हर वर्ष सख्त किया जाएगा। वर्ष 2031-32 तक यह मानक 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर करने का लक्ष्य है। इस तरह पांच वर्षों में ईंधन दक्षता में 16.7 प्रतिशत सुधार किया जाएगा। नियमों के तहत कंपनियों को किसी एक मॉडल के बजाय अपने सभी वाहनों की औसत ईंधन खपत निर्धारित सीमा में रखनी होगी। बैटरी चालित, प्लग-इन हाइब्रिड, मजबूत हाइब्रिड और वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों को सुपर क्रेडिट दिया जाएगा।

◆ पांच साल में वाहनों की ईंधन दक्षता में 16.7 प्रतिशत सुधार का लक्ष्य